# हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 13 मार्च, 2018 को अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

**प्रश्न काल**

**तारांकित प्रश्न**

13.03.2018/1100/बी0एस0/डी0सी0-1

**प्रश्न संख्याः 63**

**श्री राम लाल ठाकुरः** माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री जी ने सूचना सभापटल पर रखी है, उसमें बिलासपुर जिला में कुछ 157 ग्रीन हाऊस लगाने की सूचना दी है। जिन पर 85 प्रतिशत अनुदान देने की बात भी कही गई है और जो "ख" भाग है, इसमें मैंने पूछा था कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ग्रीन आऊस का पैसा लिया? सब्सिडी हड़प ली और एक साल के अन्दर-अन्दर सारा ग्रीन आऊस आगे बेच दिया? सूचना यह मिली कि ऐसा कोई भी ग्रीन हाऊस नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा। कि यह जो 85 प्रतिशत अनुदान की बात कही गई है क्या यह 85 प्रतिशत अनुदान शुरू के लेकर अब तक एक बराबर था? मैं यह कहना चाहूंगा कि शुरू में जो ग्रीन हाऊस लगे थे, वह केन्द्र सरकार की स्कीम थी, अनुदान कम था। दो-तीन सालों के अन्दर अनुदान बढ़कर 80 प्रतिशत हुआ। अब कृषकों को ग्रीन हाऊस में 85 प्रतिशत का अनुदान मिल रहा है। इस बारे पूर्व के मुख्य मंत्री जी से भी काफी लोग मिले थे। हिमाचल प्रदेश में ऐसे लोग हैं, जिनको ग्रीन हाऊस के लिए कम सब्सिडी पहले मिली, बाद में 85 प्रतिशत अनुदान मिला। मार्किट में जो 85 प्रतिशत अनुदान वाले लोग थे वे मार्केटिंग ठीक से कर पाए, लेकिन जो 15 प्रतिशत अनुदान वाले लोग थे, जिन्होंने बैंको से लोन लिया था, आज 450 से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनकी जमीन की कुर्की निकल गईं। कई बार वे लोग पहले की सरकार से भी मिले और मौजूदा सरकार में भी मैं समझता हूं कि इसी सत्र के दौरान माननीय मुख्य मंत्री से मिले होंगे। जिनकी जमीने जा रही हैं। मेरा निवेदन है कि 85 प्रतिशत की जो आप बात कह रहे हैं यह तो अब की बात है। लेकिन शुरू से अगर देखा जाए तो पहले कम सब्सिडी थी। कम अनुदान वाले लोगों की बजाए अधिक अनुदान जिन लोगों को मिला वे सरवाईव कर गए और पुरानी जो सब्सिडी थी वह भी दो साल के बाद मिली, तब तक बैंकों

के लोन बहुत ज्यादा हो गए। मैं कहना चाहता हूं कि यह जो सूचना है यह सही सूचना नहीं है।

13.03.2018/1100/बी0एस0/डी0सी0-2

दूसरा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कुछ लोग सब्सिडी खा गए। आपके जिला में जो अधिकारी/कर्मचारी हैं वे कुछ लोगों से मिले हैं। वे सारी सूचना को दबा करके रखते हैं। मैंने कोशिश की कि जिला बिलासपुर में मुझे बताया जाए कि एक साल के अन्दर सब्सिडी खाने वाले कितने लोग हैं? आपके डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस से कोई सूचना नहीं दी गई, कभी कहा गया कि एग्रीकल्चर विभाग से सम्बन्धित है, एग्रीकल्चर विभाग वाले बोलते हैं कि यह तो होर्टिकल्चर मिशन के अंडर है।

**अध्यक्षः** माननीय सदस्य, कृपया एक मिनट। सभी माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि वे क्लीयरली 3 सप्लीमेंट्री करें।

**श्री ठाकुर राम लालः** सर, मैं तो अभी दूसरी में आया हूं।

**अध्यक्षः** आप तीन भी करें परंतु जब उसमें स्पष्टता नहीं होगी तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। आपने जो अधिकारियों से पूछा आप मंत्री जी से सीधा पूछें।

**श्री राम लाल ठाकुरः** मैं मन्त्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि क्या कारण है कि जिन्होंने सब्सिडी का पैसा खाया और साल के अन्दर-अन्दर अध्यक्ष महोदय, उसे आगे बेच दिया, विभाग के पास उसकी सूचना क्यों नहीं है? अगर मैं उनको सूचना दूंगा तो क्या उसके ऊपर आप एक्शन लेंगे? उन अधिकारियों के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे?

13.3.2018/1105/DT/DC-1

**प्रश्न संख्याः 63...जारी...**

**कृषि मंत्रीः** अध्यक्ष महोदय,माननीय सदस्य, ठाकुर राम लाल जी ने जो प्रश्न पूछा है कि ऐसे कितने किसान हैं जिन्होंने एक वर्ष के भीतर अनुदान राशि को लेकर ग्रीन हाउस बंद कर दिया? माननीय सदस्य ने एक वर्ष की सूचना मांगी है। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि यह अनुदान राशि वर्ष 2014-15 से 85 प्रतिशत की गई है। उससे पूर्व यह राशि 80 प्रतिशत हुआ करती थी। <u>आप मुझे उन व्यक्तियों के नाम दें, मैं निश्चित तौर पर इसकी जांच करवाउंगा और आपको रिपोर्ट दूंगा</u>। अधिकारी कोई भी हो, जो गलत करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी।

13.3.2018/1105/DT/DC-2

<u>**प्रश्न संख्याः64**</u>

**श्री हीरा लालः** अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने 'प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना' वर्ष 2000-2001 में शुरू की, जिससे हिमाचल प्रदेश के सभी गांव सड़कों से जुड़े हैं। मैं तत्काल प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि प्रदेश के सभी गांव प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों से जुड़े हैं। इस योजना के तहत करसोग मंडल में 83 सड़कों के लिए कराड़ों रुपये स्वीकृत हुए हैं। लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अभी भी दो पंचायतें, बिन्दला और सूरतला के सड़क निर्माण का कार्य रूका हुआ है। इसकी एफ.सी.ए. भी क्लीयर है। यह दो सड़कें , माहूनाग- सत्यारा और शाकरा -परलोग वाया बिन्दला हैं, इन सड़कों का कार्य कब शुरू होगा और इनका निर्माण कार्य कब पूरा होगा?

**मुख्य मंत्रीः** अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने उत्तर के माध्यम से स्वीकार किया है कि करसोग मंडल में कुल 83 सड़कें स्वीकृत हुई हैं। विशेषतौर से ये सड़कें इनके विधान सभा क्षेत्र में आती है। इनमें से 52 सड़कों का कार्य पूरा कर लिया गया है। 15 सड़कों का कार्य प्रगति पर है और 6 सड़कें ऐसी हैं जहां पर एफ.सी.ए. का प्रोसैस चला हुआ है। 10 सड़कें ऐसी हैं जिनकी टैंडर प्रकिया शुरू कर दी गई है। आपने प्रश्न में जो 2 पंचायतों

बिन्दला और सत्यारा का जिक्र किया है, मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हमारा लक्ष्य है कि सभी पंचायत के मुख्यालयों व गांव को सड़क से जोड़ा जाए। उस दृष्टि से काम चला हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी फोरैस्ट क्लीयरैंस का इश्यू और निजी भूमि की गिफ्ट डीड का इश्यू है, जो हमारे प्रगति के कार्य में बाधा डाल रहे हैं। माननीय सदस्य ने जिन दो सड़कों का जिक्र किया है, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इन सड़कों के कार्य की सारी प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद जल्द ही इनका कार्य शुरू कर दिया जाएगा ताकि उस क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिल सके। माननीय सदस्य आप यह बताएं कि आपने किन-किन सड़कों के बारे में प्रश्न किया है?

13.3.2018/1105/DT/DC-3

**श्री हीरा लालः** सर, माहूनाग-सत्यारा और शाकरा-परलोग वाया बिन्दला। पंचायत मुख्यालय बिन्दला और सत्यारा में अभी सड़कें पहुंची नहीं हैं।

**मुख्य मंत्रीः** अध्यक्ष महोदय, दोनों सड़कों की जो काम करने की आवश्यकता है, चाहे वह एफ.सी.ए. क्लीरैंस हो या कोई अन्य विषय हो, जिसके कारण सड़क का काम रुका हुआ है, उसको जल्द शुरू किया जाएगा। हम उस कार्य को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे।

**13.03.2018/1110/SLS-HK-1**

**प्रश्न संख्या : 64 ...जारी**

**अध्यक्ष :** वैसे तो यह करसोग मंडल का प्रश्न है फिर भी, श्री राकेश पठानिया जी, आप अपना सप्लीमैंटरी पूछें।

**श्री राकेश पठानिया :** अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह प्रश्न प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जुड़ा हुआ है इसलिए मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी से इसमें एक छोटी-सी क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। मैंने प्लानिंग की बैठक में भी इस बात को उठाया था। अध्यक्ष महोदय, जो हमारा सैन्सस बना हुआ है और जो सैटेलाईट से मैप बना हुआ है, वह 2001

का बना हुआ है। उस समय 500 से अधिक आबादी के गावों को इसमें कवर किया गया था। अब PMGSY Phase-III आ गया है जिसमें 100 तक की आबादी को भी कवर किया जा रहा है। क्या सरकार की प्रस्तावना कोई नया सर्वेक्षण करवाने की है जिसमें a new survey would be done ताकि ये 100 की हैबिटेशन वाले गांवों भी इसके अंतर्गत कवर हों? अगर यह 100 की हैबिटेशन वाले गांवों प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत कवर हो जाएं तो आदरणीय मुख्य मंत्री जी, फिर शायद हमारा कोई गांव शेष नहीं बचेगा।

**मुख्य मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि पहले प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत पहले 500 की आबादी वाले गांव और फिर उसको रिलैक्स करके 250 की आबादी वाले गांव कवर किए गए। हमारे लिए यह खुशी की बात है कि 250 की आबादी की जब यह रिलैक्सेशन दी गई थी, उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद में, जो गांव सड़कों की वजह से छूट रहे थे, उन गांवों को भी सड़कों से जोड़ने की एक गुंजाईश बनी और उन सड़कों को बनाया गया। जहां तक इससे कम आबादी का प्रश्न है, हमने इस मसले को केंद्र के साथ उठाया है। अभी भी विशेष तौर से दिल्ली जाकर हमारी केंद्रीय मंत्री जी से बात हुई है। हमारे अधिकारी भी बार-बार जा रहे हैं और बात कर रहे हैं। अभी भी हमारे बहुत से गांव ऐसे रह गए हैं जो इस आबादी से भी नीचे रहते हैं। उनकी आबादी 60, 70 या 100 है। यह ऐसे छोटे-छोटे

**13.03.2018/1110/SLS-HK-2**

गांव हैं जो अभी रह गए हैं। उस दृष्टि से हमने अपनी बात को रखने की कोशिश की है कि उन छूट गए छोटे गांवों को भी इसमें कवर किया जाए। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना हमारे पास एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में गांवों तक सड़क पहुंचाने का एक बहुत बड़ा काम हुआ है और इस काम को करने के लिए हमें इस योजना से बहुत मदद मिली है। हमें इस बात की खुशी है क्येांकि प्रदेश के पास बहुत कम संशासन होने के कारण हम अपने स्तर पर वहां नहीं पहुंच पाते, लेकिन प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत पैसा केंद्र से आता है और इस पैसे से हम सड़कों को गांव तक पहुंचाने में सफल

हुए हैं। जो माननीय सदस्य ने पूछा, अभी तक हमें 100 से नीचे की आबादी को कवर करने के मामले में नियमानुसार छूट नहीं है। लेकिन हम सारे मामले को बार-बार इस तरह से उठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम हर गांव को सड़क से जुड़ने की सुविधा दे सकें। उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे है। लेकिन उसके बावजूद भी, अध्यक्ष महोदय, जो हमारे इस तरह के छोटे गांवों रहते हैं, उन गांवों को सड़क से जोड़ने की दृष्टि से प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत उनको कंसीडर किया जाता है और किया भी जा रहा है। उस दृष्टि से हम और भी कोशिश करेंगे कि ऐसे गांव सड़क से जुड़ें और इसमें प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना का एक बहुत बड़ा योगदान है।

धन्यवाद।

**13.03.2018/1110/SLS-HK-3**

**प्रश्न संख्या : 65**

**श्री होशयार सिंह :** Thank you, Speaker Sir. According to this report, JNNURM की 33 बसें देहरा के लिए खरीदी गई थीं और वहां के लिए आवंटित हुई थीं। वह 33 की 33 बसें इस वक्त खड़ी हैं। यह कब सड़क पर चलना शुरू करेंगी और ये खड़ी क्यों हैं, इसकी जानकारी देने की कृपा करें।

**वन मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, श्री होशयार सिंह जी का प्रश्न है कि देहरा डिपो की 33 बसें खड़ी हैं और ये कब तक चला दी जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार के माध्यम से JNNURM की लगभग 791 बसिज प्रदेश को मिल थीं।

**13/03/2018/1115/RG/HK/1**
**प्रश्न सं. 65---क्रमागत**
**वन मंत्री-----जारी**

उसके पश्चात जो क्लस्टर बनाए गए थे उनमें वे बसें चलनी थीं। बसें चलना प्रारम्भ भी हुआ, लेकिन निजी ऑपरेटर्ज उच्च न्यायालय में चले गए। उन्होंने कहा कि ये बसें गैर-कानूनी तरीके से चल रही हैं जिन क्लस्टर्ज में इनको चलना चाहिए, उसके आधार पर ये नहीं चल रही हैं। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी और उसके पश्चात जो बसें क्लस्टर के आधार पर नहीं चल रही थीं, वे बंद हो गईं। लेकिन पूर्व सरकार की मैं एक और जानकारी देना चाहूंगा कि उसके बावजूद कुछ बसें चलीं। फिर माननीय उच्च न्यायालय में contempt of Court हुआ। उस पर कहा गया कि आप कोई ठीक प्रकार की नीति लाकर उन बसों को चलाएं। अध्यक्ष महोदय, अभी उस संबंध में अधिसूचना जारी हो गई है और स्टेक होल्डर्ज या बाकी सब लोगों से ऑब्जैक्शन्ज मांगे गए हैं और वे ऑब्जैक्शन्ज कुछ दिनों में रिमूव किए जाएंगे। गत् दिनों निजी ऑपरेटर्ज और हिमाचल पथ परिवहन निगम की मिलकर बातचीत भी हो चुकी है जिसके आधार पर मिलकर क्लस्टर के अनुसार बसें चलाने का निर्णय हम जल्दी करेंगे। परिवहन विभाग इन बसों को कानूनी तरीके से चलाने के लिए परमिट जारी करेगा और जहां-जहां ये बसें खड़ी हैं, बहुत जल्दी ये चलना प्रारम्भ होंगी। मैं यहां बता दूं कि लगभग 300 बसें पूरे प्रदेश में खड़ी हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक जानकारी यहां और देना चाहूंगा कि जे.एन.एन.यू.आर.एम. की बसों को खरीदने के लिए जब डी.पी.आर. बनाई गई, उस समय इतनी बड़ी गलती की गई कि बारह मीटर लम्बी बसें, जिन बसों की हिमाचल प्रदेश में आवश्यकता नहीं थी, ले ली गईं। उस समय धर्मशाला में विधान सभा का सत्र चल रहा था, पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी और पूरे विधायक दल ने जब देखा, तो कहा कि इस प्रदेश में ये बसें उपयुक्त नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद बारह मीटर लम्बी बसें लाई गईं। जो हिमाचल प्रदेश की सड़कों के अनुसार ठीक नहीं थीं। फिर नौ मीटर लंबी लो फ्लोर बसें जो हिमाचल के योग्य नहीं थीं, ली गईं। लेकिन जो गलती तब हो गई, हो गई, लेकिन अब उन बसों को चलाने के लिए हम कानूनी तरीके से चलें, मिलकर चलें और क्लस्टर में चलें। इस आधार पर हम इस पर बहुत जल्दी निर्णय करके इन सब बसों को ठीक प्रकार से क्लस्टर में चलाएंगे।

**13/03/2018/1115/RG/HK/2**

**श्री अरुण कुमार** : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न में पूछा था कि जो वॉल्वो, ए.सी., डीलक्स और अन्य टैम्पो ट्रेवलर्ज वैट लीज पर ऑऊटसोर्स के माध्यम से रखी गईं, उनसे अभी तक कितना नफ़ा-नुकसान हुआ है? कृपया माननीय मंत्री जी इस बारे में उचित तरीके से जानकारी दें।

**वन मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि गत् तीन वर्षों में वैट लीज पर जो बसें चली हैं, इन सभी में ये अलग-अलग बसों के रूप हैं। लेकिन ओवर-ऑल लगभग 17 करोड़ रुपये के लगभग तो लाभ रहा और जो हमने लिखित उत्तर दिया है, उसमें भी यह है। लेकिन जो छोटी मिनी बसें हैं उसमें 1,18,00,000/-रुपये के लगभग नुकसान हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी माननीय सदस्य चाहते हैं, उसमें आपके माध्यम से एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि वर्ष 2015-16 में हिमाचल पथ परिवहन निगम ने 10 वॉल्वों बसें खरीदीं, वर्ष 2016-17 में 15 बसें खरीदीं और ये भी बस अड्डा प्रबन्धन प्राधिकरण के माध्यम से खरीदी गईं। क्योंकि हिमाचल पथ परिवहन निगम को लोन नहीं मिलना था।

**13/03/2018/1120/MS/YK/1**

**प्रश्न संख्याः 65 क्रमागत--**
**--वन मंत्री जारी----**

उसके पश्चात जो बसें ली हैं उसमें हैरानी की बात देखिए कि वर्ष 2016-17 में 20 वोल्वो बसें और खरीदीं यानी एक ही समय में 45 वोल्वो बसें HRTC ने अपने आप खरीदीं और 45 बसें आपकी अपनी उसके साथ चल रही थीं तथा 52 वोल्वो बसिज आपने वेट लीज पर ली। यानी ऐसा कभी नहीं होता था। आप या तो वेट लीज की बसों को चलाते या अपनी बसें चलाते। वे अधिकतर बसें मनाली-शिमला, मनाली-दिल्ली और धर्मशाला-दिल्ली आदि जगहों पर चलाई गई जहां पर HRTC की अपनी बसें चल रही थीं। यानी प्रोफिट शेयरिंग में वह सब था। कुल-मिलाकर जितनी वेट लीज बसें चलाई गई हैं उनकी आवश्यकता नहीं थी यानी डिमाण्ड नहीं थी। बिना डिमाण्ड के उन बसों को चलाया गया। कुल-मिलाकर यह घालमेल मुझे समझ नहीं आता। माननीय सदस्यों ने इसी में अपना एक प्रश्न किया है कि

कुल बसें कितनी खरीदी गईं? अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि वर्ष 2011-12 तक एक परम्परा थी कि कभी भी बसों को खरीदने के लिए अतिरिक्त लोन नहीं लिया जाता था। जो कैपिटल ग्रांट है उसके अंगेस्ट ही बसें ली जाती थी परन्तु वर्ष 2013-14 से लगातार बसों की खरीद के लिए सैंकड़ों करोड़ रुपयों का लोन लिया जाता रहा। हैरानी तो यह है कि वर्ष 2012-13 तक 1800 बसों का टोटल बेड़ा था तो उसके बाद इतनी बसें खरीदने की आवश्यकता नहीं थी। लगभग 2100 बसें और अतिरिक्त जो खरीदीं वे बिना किसी डिमाण्ड के खरीदी गईं। अभी वर्ष 2017-18 में 325 बसें और ली गई हैं। अभी वित्त विभाग की एक ऑब्जर्वेशन थी कि हिमाचल प्रदेश में बसों का बेड़ा 2500 बसों का होगा तो उपयुक्त उनकी प्रोडक्टिविटी चलाकर काम करेंगे। वर्तमान में जो HRTC को ट्रैक से बाहर किया गया उसका कारण यह है कि वर्ष 2012-13 में 230/-रुपये पर-किलोमीटर पर-डे की हमारी आमदनी थी जो अब घटकर के 190/-रुपये पर-किलोमीटर पर-डे की रह गई है। इसी तरह से वर्ष 2017-18 में कोई डिमाण्ड नहीं थी और उसके पश्चात जब लोन लेने के लिए गए तो वित्त विभाग ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी और तत्कालीन सरकार ने भी स्वीकृति नहीं दी क्योंकि बसों की आवश्यकता नहीं थी।

**13/03/2018/1120/MS/YK/2**

फिर बिना स्वीकृति के लोन लेकर के 325 बसें अतिरिक्त ली गईं। अध्यक्ष जी, कुल-मिलाकर बात यह है कि सारा सिस्टम बाहर कर दिया गया और आगामी दिनों में इस सिस्टम को जय राम ठाकुर जी की सरकार बिल्कुल ट्रैक पर लाएगी और ट्रैक पर लाकर हम इसको बहुत अच्छे से चलाएंगे।

**अध्यक्षः** मुकेश अग्निहोत्री जी का भी प्रश्न में नाम है।

**श्री मुकेश अग्निहोत्रीः** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि परिवहन निगम के बेड़े में इस समय 3103 बसें हैं जिनमें से 25 इलैक्ट्रिक हैं। इसका मतलब इनका 3078 बसों का बेड़ा है। जो मेन आपका बसों का बेड़ा है इनमें से कितनी बसें रूट पर चल रही हैं और इनमें से फालतू कितनी बसें खड़ी हैं तथा इनमें से कितनी बसें जीरो वैल्यु हैं? दूसरे, JNNURM की 791 बसिज हैं जिनमें से 325 खड़ी हैं। मैं

---

जानना चाहता हूं कि ये 325 बसें कब से खड़ी हैं और इनके न चलने से HRTC को कितना घाटा हुआ है तथा इन बसों को कब तक आप रोड पर लाने के लिए ऑपरेशनल कर देंगे?

**13.03.2018/1125/जेके/वाईके/1**
**प्रश्न संख्याः 65ः---------जारी-----**

**वन मंत्रीः** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है ये बसें लगभग 3,222 के करीब है, 3103 बसे एच0आर0टी0सी0 की अपने बेड़े की हैं और 25 इलैक्ट्रिक बसें हैं। इसके अलावा 97 वॉल्वो बसिज़ वैट लीज़ पर ली गई हैं। इनमें से अभी बाकी बसें लगभग अपने रूट पर चल रही हैं। कुछ रिज़र्व बेड़ा है उसकी जानकारी मेरे पास अभी नहीं है वह मैं बाद में दे दूंगा। दूसरे, वैट लीज़ पर जो घाटा है, वह घाटा एच0आर0टी0सी0 को ही उठाना पड़ता है। आगामी आने वाले दिनों में हम यह विचार कर रहें हैं कि इसके एग्रीमैंट में हम कुछ इस प्रकार की शर्त डालें, वैसे तो हमें लगता है कि आवश्यकता नहीं रहेगी लेकिन जो एच0आर0टी0सी0 का हमारा बेड़ा है, इसी फ्लीट की प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ाने वाले हैं। यदि कहीं नीड बेस पर आवश्यकता होती है तो हम आने वाले दिनों में इसमें संशोधन करेंगे कि जो वैट लीज़ पर बस चल रही है, घाटे में चल रही है, उस घाटे के लिए प्राईवेट एंट्रप्रीन्योर और एच0आर0टी0सी0 दोनों बराबर भागीदार होंगे और कुछ समय उसको दिया जाएगा तो अल्टिमेटली अगर घाटा है तो प्राइवेट उसको छोड़ सकता है और वे छोड़ के निकलेंगे । पहले जो एग्रीमैंट था उसमें सारा घाटा एच0आर0टी0सी0 के ऊपर था चाहे प्राइवेट बस खाली ही चले। ऐसी अनेक लम्बी जानकारी हमने लिखित में आपको भेजी है और यदि और भी जानकारी चाहिए तो उसको भी दे देंगे। इसके अतिरिक्त जो 325 बसें हैं, हमने कहा कि जो हमने ऑब्जैक्शन्ज़ मांगने थे, जो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था, वे ऑब्जैक्शन्ज़ हमारे पास आ गए हैं। विभाग ने उन पर अध्ययन कर लिया है। बहुत जल्द एक हफ्ते के अंदर हम कोशिश करेंगे कि उनका निपटारा करें और जिन स्टेक होल्डर्ज़ ने, लगभग 125 लोगों ने अपने ऑब्जैक्शन्ज़ रेज़ किए हैं, उन सबको हम सुनेंगे।

---

सुनने के बाद हमने यह विचार किया है कि एच0आर0टी0सी0 और साथ में हिमाचल प्रदेश के निजी ऑप्रेटर्ज़ के साथ मिल करके, बातचीत करके सारा रास्ता सुलझाएंगे।

**13.03.2018/1125/जेके/वाईके/2**

अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि पूर्व सरकार के समय हिमाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों को हर तरह से नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। तालमेल से सब चलें और बेरोजगार लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो और एच0आर0टी0 में ठीक प्रकार से काम हो, बहुत जल्द हम यह प्रयास करेंगे । बहुत जल्द इन बसों को हम सड़कों पर उतारेंगे और प्रदेश की जनता को सुविधा प्रदान करेंगे।

**श्रीमती आशा कुमारीः** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि इन्होंने कहा कि JNNURM की लगभग 325 बसें खड़ी हैं। मैंने पहले भी आपसे यह मसला उठाया था। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी और वैसे भी आपसे मिल कर यह मसला उठाया था। ये जो रूट्स थे, जिनमें JNNURM की बसें चली हुई थी, ये out of cluster routes पर चल रही थीं। मैंने आपसे निवेदन किया था कि जब आपने out of cluster routes पर JNNURM की बसिज़ बन्द कर दी है, तो ये जो out of cluster routes हैं, इनके लिए आपने बसों का प्रावधान किया या नहीं किया? क्योंकि वे रूट्स जो कि अधिकृत रूट्स हैं और डिपार्टमैंट द्वारा पास्ड रूट्स हैं, उन पर दूसरी बसिज़ चलनी हैं, I don't know about other districts. मगर चम्बा जिला में जो एच0आर0टी0सी0 और आर0टी0ओ0 डिपार्टमैंट्स हैं, दोनों में उन रूट्स को दूसरी बसिज़ other then JNNURM बसिज़ चलाने के लिए एस0टी0ए0 को परमिट के लिए लिखा है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई क्योंकि JNNURM की बसिज सही चल रही थी या गलत चल रही थी, यह एक दूसरा विषय है? मगर रूट्स बन्द हो गए, लोगों को असुविधा हो रही है। वहां पर न प्राइवेट रूट चल रहा है और न ही एच0आर0टी0सी0 का रूट चल रहा है। मैंने आपसे तीन महीने पहले भी यही निवेदन किया था और आज भी यह

निवेदन कर रही हूं कि JNNURM की बसिज़ तो आप जब भी फैसला करेंगे वे आप क्लस्टर में ही चलाएंगे। Out of cluster जो रूट्स चल रहे थे, जो बन्द हो गए हैं, उनके बारे में आपने क्या निर्णय लिया?

**13.03.2018/1130/SS-AG/1**

**प्रश्न संख्याः 65 क्रमागत**

**वन मंत्रीः** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या का प्रश्न उचित है। इसमें यह है कि जो आपकी जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की बसें चल रही थीं तो उस वक्त 202 रूट ऐसे थे जहां पर एच0आर0टी0सी0 की बसों की आवश्यकता थी, जिस कारण रूट बंद हो गया था। उसमें से अधिकतर बसों को चलाया है। अभी मैंने कहा कि जो क्लस्टर में बसें चलेंगी उनको भी चलायेंगे। अधिकतर जगहों पर तो बसें चल रही हैं लेकिन क्लस्टर के अलावा जिन जगहों पर बसें नहीं चल रही हैं, मैं तो इस माननीय सदन के सब सदस्यों से कहूंगा कि वे उसकी सूची प्रदान कर सकते हैं और हम एच0आर0टी0सी0 से डिटेल मांगेंगे, जनता को असुविधा न हो इसलिए प्राथमिकता के आधार पर उन बसों को चलायेंगे। अब मैं क्या कहूं, पूर्व सरकार के समय में बहुत गलतियां हुई हैं। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि हमारी सरकार बने लगभग दो महीने का समय हुआ है, अभी हमें उन सब कमियों को ठीक करने में कुछ समय लग रहा है। निश्चित रूप से हमने इसको अच्छे से ठीक किया है और ठीक कर भी रहे हैं। इसको ठीक करके बहुत जल्दी बाकी बसों को भी चलायेंगे और कोई कमी नहीं रहने देंगे।

**अध्यक्षः** अंतिम दो सप्लीमेंटरी, पहले श्री राकेश जी और फिर आदरणीय मुकेश जी पूछ सकते हैं।

**श्री राकेश पठानियाः** आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से केवल यह जानना चाहूंगा, जैसे आपने प्रश्न का जवाब दिया कि 12 मीटर और 9 मीटर लम्बी बसें हैं। अध्यक्ष जी, मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि इसकी जो ग्राऊंड क्लीयरैंस है वह कुछ इंचों की है। ये बसें हिमाचल प्रदेश में चलाने के लिए फिजीबल ही नहीं हैं और जो बसें चल रही हैं वे डैथ ट्रैप हैं। इनका एक्सीडैंट हो सकता है। पहले ऑरिजनल बसें लोहे की बॉडी के साथ आती थीं लेकिन अगर आप इनकी बॉडीज़ देखें तो वे इतनी कमजोर हैं कि ये एक

झटका भी सस्टेन नहीं कर सकतीं। आपने जवाब बहुत बढ़िया दिया है, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आप पूरे सदन को इनका श्वेत पत्र जारी करके बतायेंगे जो घोटाले एच0आर0टी0सी0 में हुए ताकि पूरे प्रदेश को पता लग सके कि पिछली सरकार ने एच0आर0टी0सी0 में कितना घोटाला किया?

**13.03.2018/1130/SS-AG/2**

**वन मंत्रीः** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री राकेश जी ने जो कहा है एक तो इस बात की जांच किये जाने की आश्यकता है कि आखिरकार जब इतने एक्सपर्टस बैठे थे और हिमाचल प्रदेश से डी0पी0आर0 जा रही थी तो इतने टेक्निकल लोगों ने मिल करके जब डिसाइड किया कि 12 मीटर बस हिमाचल में चलेगी, क्या इतने लो फ्लोर की बस चलेगी तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिकार इतनी बड़ी गलती इतने टेक्निकल लोगों ने कैसे की। दूसरा, जो आपने कहा कि एच0आर0टी0सी0 के लिए कहां-कहां पर कौन जिम्मेदार है निश्चित रूप से इस पर सारा श्वेत पत्र जारी करेंगे ताकि कम-से-कम हर चीज़ का पता चले। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है वरना मेरी आदत है कि मैं पीछे मुड़ कर नहीं देखता, मैं आगे बढ़ने में विश्वास करता हूं। लेकिन अब माननीय सदस्य ने कहा है तो हम उन बातों को ठीक प्रकार से सबके समक्ष लायेंगे।

**अध्यक्षः** माननीय मंत्री जी, काफी हो गया। माननीय मुकेश जी, अंतिम सप्लीमेंटरी पूछे सकते हैं।

**श्री मुकेश अग्निहोत्रीः** अध्यक्ष महोदय, सवाल की मंशा अलग है लेकिन इधर मैच फिक्सिंग हो रहा है। हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि मंत्री जी के बार-बार बयान आ रहे हैं कि एच0आर0टी0सी0 के पास फालतू बसिज़ हैं, पूर्व सरकार ने फालतू बसिज़ खरीद लीं। हम इनसे ये कह रहे हैं कि जो आपके पास बसिज़ हैं उसमें जो एच0आर0टी0सी0 की बसिज़ हैं उसमें कितनी बसें फालूत हैं जो रूट पर नहीं चल रही हैं? आपने लिखा है कि मेरे पास 3103 बसें हैं, आप हमें ये बताएं कि क्या 3103 बसें रूट पर चल रही हैं या खड़ी हैं, इनमें से कितनी फालतू हैं। जो आपका अखबारों में सार्वजनिक तौर पर फालतू बसों का बयान आ रहा है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि 3103 में से एच0आर0टी0सी0 के बेड़े में कितनी फालतू बसिज़ हैं और इसमें हमने आपसे जानना चाहा कि क्या अभी तक भी आपके पास

जीरो वैल्यू बसिज़ हैं? यह तो सारी दुनिया जानती है कि एच0आर0टी0सी0 का बेड़ा हिन्दुस्तान में वैस्ट फ्लीट है, यंगैस्ट फ्लीट है। उसके बाद एक्सीटैंड्स घटे भी हैं। लेकिन आप सिर्फ यह बता दें कि 3103 में से कितनी बसें फालूत हैं जो रूट पर नहीं जा रही हैं?

13.03.2018/1135/केएस/एजी/1

**प्रश्न संख्याः 65 जारी**---

## श्री मुकेश अग्निहोत्री जारी...

दूसरे, JNNURM की 325 बसें कब से खड़ी हैं क्योंकि देश में कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि किसी भी संस्था की 325 बसें खड़ी हैं। हम जानना चाहते हैं कि वे कब से खड़ी हैं, इनसे कितना लॉस हो रहा है और आप इन्हें कब तक चला देंगें? बाकी तो आपने हमारे सवाल के बीच में टायरों का डाल दिया, श्वेत पत्र का डाल दिया, यह तो आपकी राजनीति है लेकिन हम तो सिर्फ आपसे स्ट्रेट पूछ रहे हैं कि आपकी कितनी बसें फालतू हैं जो रूट पर नहीं चल रही है और JNNURM कि 325 बसें आप कब तक चला लेंगें और कितना लॉस हो चुका है? छोटी बसें जो शायद प्राइवेट सैक्टर्ज़ से ली हुई हैं, क्या आप इनको बन्द करने का इरादा रखते हैं और क्या आप इस सदन को आश्वस्त करेंगें कि आप एच.आर.टी.सी. की फ्लीट स्ट्रेंथ कितने पर निर्धारित कर रहे हैं?

**वन मंत्रीः** अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं मुकेश जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हम मैच फिक्सिंग नहीं करते। हम तो सीधा चलते हैं। मैच फिक्सिंग वाले न राकेश पठानिया जी हैं और न हम हैं। मुकेश जी, यह शायद आपकी आदत है। फालतू बसें मैंने कभी नहीं कहा। मैंने एक बात कही है कि 325 बसें JNNURM की हमारे पास खड़ी है और लगभग जुलाई, 2017 के आसपास माननीय उच्च न्यायालय ने ये बन्द की थी। जो आपने लॉस की जानकारी चाही वह अभी मेरे पास नहीं है। आपने जो 325 बसों के बारे में कहा, वह जानकारी आपको प्रदान करेंगें। जो आपने घाटे वाली मिनी बसों के बारे में जानकारी चाही तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी इनमें से हम किसी बस को बन्द करने वाले नहीं है। जो

बसें एच.आर.टी.सी. के लिए लाभदायक होंगी, वे बसें चलाएंगें और अगर कहीं लगता है कि किसी से सरकार को घाटा हो रहा है तो उन बसों पर विचार किया जाएगा । आपने पूछा कि कब तक लाएंगें? इस बात का उत्तर हम

**13.03.2018/1235/केएस/एचके/2**

अभी नहीं दे सकते क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय बीच में है। भारतीय जनता पार्टी, जय राम ठाकुर जी की सरकार माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करती है और जो बात हमें करनी है, वह वहां पर करेंगें लेकिन मैं इस माननीय सदन में यह जरूर कहूंगा कि इनको बहुत जल्दी चलाने वाले हैं।

**अध्यक्षः** मंत्री जी, एक प्रश्न छूट रहा है कि 3103 बसों में से कितनी बसें ऐसी हैं जो अभी चल नहीं रही हैं? आप इसका उत्तर बाद में दे दीजिएगा।

**वन मंत्रीः** अध्यक्ष महोदय, ज़ीरो वैल्यू की 170 बसें अभी हमारे पास हैं। बाकी हमारी सभी की सभी बसें चल रही है।

**13.03.2018/1235/केएस/एचके/3**

**प्रश्न संख्या- 66**

**श्री बिक्रम सिंह जरयालः** अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने विस्तृत उत्तर दिया है परन्तु वैसे तो धांधलियां सभी भर्तियों में हुई है परन्तु यहां पर जिला चम्बा के तीन व्यक्ति रखें और तीनों सिहुन्ता से ही हैं। क्या चम्बा में बाकी क्षेत्र से कोई आदमी नहीं था जिसको प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कार्य दिया जा सकता था? मैं आश्वासन चाहूंगा कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी जांच करवाएंगें?

**13.3.2018/1140/av/dc/1**

**प्रश्न संख्या : 66 ------- क्रमागत**

**मुख्य मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमने इस प्रश्न का विस्तृत उत्तर दिया है। इन सारी अप्वाईंटमैंट्स में थोड़ा सा यह लगता है कि नियमों की परिधि में जिस प्रकार से चीजें होनी चाहिए थीं वह उस प्रकार से नहीं हुई है। यहां पर माननीय सदस्य ने तीन अप्वाईंटमैंट्स का जिक्र किया है जो केवल सिहुंता से हुई है, वह एक अलग विषय है। मैं यहां पर थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं कि इन नियुक्तियों में क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई गई। दिनांक 25.7.2013 को पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड की फुल मीटिंग में 71 खाली पदों को भरने का निर्णय लिया गया। क्लास-II,क्लास-III और क्लास-IV के लिए यह भी निर्णय लिया गया कि इनकी नियुक्तियां पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड खुद करेगा। जबकि रूल्स के हिसाब से यह सारी नियुक्तियां हि0प्र0अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड ने करनी थी लेकिन इसके लिए पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि हम खुद करेंगे। उसके बाद फिर यह निर्णय लिया गया कि पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड के इन पदों की भर्तियां हि0प्र0 विश्वविद्यालय के माध्यम से की जायेगी। युनिवर्सिटी के माध्यम से भर्ती करने के लिए उनको 25 लाख रुपये की धनराशि दी गई। उसके बाद इसमें रिक्रूटमैंट का प्रोसैस शुरू होता है मैं जिसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि यह एक लम्बा प्रोसैस है। उसमें 9 पद क्लर्क के, 3 पद स्टैनो-टाईपिस्ट के, 3 पद लैब असिस्टैंट के और 5 पद जूनियर असिस्टैंट के थे जिसके लिए 12282 लोगों ने अप्लाई किया था। जूनियर असिस्टैंट और लैब असिस्टैंट के पदों के लिए दिनांक 22.3.2015 तथा क्लर्क व स्टैनो-टाइपिस्ट के लिए दिनांक 29.3.2015 को लिखित परीक्षा ली गई। दिनांक 9.9.2015 को पर्सनल इन्टरव्यू रखा गया और दिनांक 22.9.2015 को सलैक्शन करने के बाद उनको ज्वाइनिंग दी गई। अब इसके पीछे मन्शा क्या थी, अगर हम इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो स्वाभाविक रूप से इसमें शंका जाहिर होती है। हिमाचल प्रदेश में इन पदों को भरने के लिए एक स्थापित व्यवस्था है और यह नियुक्तियां सबोर्डिनेट सर्विसिस सलैक्शन बोर्ड, हमीरपुर के माध्यम से की जाती है। मगर यह कार्य युनिवर्सिटी

को दिया गया और उसके लिए पैसा भी बोर्ड से दिया गया। हालांकि इसमें 9 जिलों से नियुक्तियां की

**13.3.2018/1140/av/dc/2**

गई हैं मगर उसके बावजूद भी चम्बा जिला के एक ही निर्वाचन क्षेत्र से नियुक्तियां देना और वह कौन-कौन लोग हैं; माननीय सदस्य को ज्यादा जानकारी है क्योंकि ये उनके बहुत नज़दीक है। इस सलैक्शन के प्रोसैस में अपने आप में कई तरह के प्रश्न खड़े होते हैं इसलिए जैसे माननीय सदस्य ने इन तीन नियुक्तियों के बारे में पूछा है तो मैं इस बारे में जानकारी हासिल करूंगा तथा उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या कर सकते हैं।

**13.3.2018/1145/TCV/DC-1**

**प्रश्न संख्याः 67**

**श्री मोहन लाल ब्राक्टाः** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि गत तीन वर्षों में रोहडू विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वन विभाग के कितने विश्राम गृह निर्माणाधीन हैं? माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि दो विश्राम गृह सिन्दासली और रनोल निर्माणाधीन हैं। लेकिन तीसरा विश्राम गृह शील है जिसका निर्माण कार्य काफी समय से लम्बित पड़ा है। विभाग ने शायद जानबूझकर इसका जिक्र नहीं किया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि शील विश्राम गृह, जो मेरे चुनाव क्षेत्र में आता है, इसका निर्माण कार्य कब शुरू होगा और कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा?

दूसरा, मैंने प्रश्न किया था कि वन मण्डल रोहडू के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के कितने पद खाली हैं? इसका जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया है कि कुल 22 पद खाली है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह रहेगा कि जो रिक्तियां इन्होंने बताई है, उनको शीघ्रातिशीघ्र भरने की कृपा करें।

**वन मंत्रीः** अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने शील वन विश्राम गृह के बारे में पूछा है, यह पिछले 3 साल से निर्माणाधीन नहीं है, इसका निर्माण कार्य 2017-18 में प्रारम्भ हुआ और अगले साल तक हम इसको तैयार करके दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो यहां पर पूछना चाह रहे हैं, एक छोटी-सी बात कह करके उत्तर देता हूं। कहते हैं कि एक बच्चे की मां उसकी पिटाई कर रही थी। बच्चे का पिता आया तो उसने कहा कि इसको क्यों मार रही है, इसको छोड़ दे। उसने कहा- देखो जी ये मार्क्सशीट हैं और इसमें यह फैल है। आपका बेटा कितना नालायक है। जब उस बैलेंसशीट को गौर से देखा तो पता चला कि बैलेंसशीट उनकी अपनी (पिता) ही है। आपने जो वन विश्राम गृह सिन्दासली का जिक्र किया है, हैरानी की बात है कि 1992-93 में इसका काम प्रारम्भ हुआ और उसके बाद अब 2018 चला है। कितने साल बीत गये, प्रदेश के मुख्य मंत्री वहां से रहे

**13.3.2018/1145/TCV/DC-2**

और अब जाकर 2018-19 में हमने इसमें धन का प्रावधान किया है तथा इसी वर्ष इस विश्राम गृह को तैयार कर दिया जाएगा। अगला, वन विश्राम गृह, 2007-08 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में इसका निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ और वह भी अब तक पूरा नहीं हुआ है। उसको भी वर्ष 2018-19 में 21 लाख रुपये खर्च करके तैयार किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त जहां तक रिक्तियों की बात है, जो डिटेल मार्क्सशीट आपने दी है, ये आपके समय के ही हैं। लेकिन अब जय राम ठाकुर जी की सरकार ने ये निर्णय लिया है कि सहायक अरण्यपाल की जो पोस्टें हैं, उनको वहां पर भरेंगे। इसके साथ-साथ हिमाचल पब्लिक सर्विस कमिशन ने अपना प्रोसैस प्रारम्भ कर दिया है। हिमाचल पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा डी0एफ0ओ0 के 100 पद और अधीक्षक ग्रेड-II के पदों को भरे जाने की प्रक्रिया भी जारी है। राज्य में लिपिक के जो 124 पद हैं, इनको भी प्राथमिकता के आधार

पर भरा जाएगा और और आवश्यकता के आधार पर रोहडू विधान सभा क्षेत्र के लिए भरेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब मैंने पूछा कि रोहडू विधान सभा क्षेत्र में कितने वन विश्राम गृह है, तो बताया गया कि 11+3=14 होंगे। फिर भी पिछड़ा क्षेत्र है।

मेरा आपसे निवेदन है कि इको-टूरिज्जम के माध्यम से हम कहां, क्या कवर कर सकते हैं, आप हमारे ध्यान में लायें। रोहडू विधान सभा क्षेत्र में जितनी डैवेल्पमैंट हो सकेगी, माननीय मुख्य मंत्री जय राम ठाकुर जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहां का पिछड़ापन निश्चित रूप से दूर करेगी। आप हमें सूची दें।

13-03-2018/1150/NS/HK/1

**प्रश्न संख्याः 68**

**श्री अनिरूद्ध सिंहः** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा और एक सप्लीमैंटरी भी पूछना चाहूंगा कि क्या AMP (Annual Maintenance Plan) डिवीज़न वाईज़ या सब-डिवीज़न वाईज़ दिया जाता है? वर्ष 2017-18 में डिवीज़न नम्बर-1, शिमला, जिसमें पूरा कुसुम्पटी विधान सभा क्षेत्र आता है और शहर के साथ लगता है, इसमें सारे पर्यटन स्थल भी आते हैं जैसे कि चायल, मशोबरा, नालदेहरा, कुफरी और फागू आदि और ये सारे कुसुम्पटी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वर्ष 2017-18 कुल 58 डिवीजन्ज़ में से 55 नम्बर मेरे विधान सभा क्षेत्र का आया है। कुल 89.48 लाख की राशि केवलमात्र शिमला डिवीज़न को दी गई है। मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा कि अभी जो AMP (Annual Maintenance Plan) आपकी (सत्ता पक्ष) सरकार बनने के बाद आया है या अलोट हुआ है, उसमें हमारी मुख्य सड़कें जैसे फागू एक पर्यटन स्थल है और वहां से चियोग को रास्ता जाता है तथा ठियोग विधान सभा क्षेत्र भी इससे कनैक्ट होता है, हम वहां से कुसुम्प्टी और चौपाल को भी जाते हैं लेकिन माननीय मुख्य मंत्री महोदय, वहां पर लगता ही नहीं है कि कोई सड़क बनी है। यह सड़क मैंने AMP (Annual Maintenance Plan) में लिखी थी, परन्तु यह सड़क उसमें शामिल नहीं है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह पांच किलोमीटर सड़क फागू से

बागड़ी जोकि सब-डिवीज़न मशोबरा के अन्तर्गत आती है। सब-डिवीज़न जुन्गा में तकरीबन चार किलोमीटर ए0एम0पी0 ज्यादा की आवश्यकता है। सब-डिवीज़न शिमला जोकि डिवीज़न नम्बर-1 के अन्तर्गत आता है, इसमें लगभग 10 किलोमीटर अधिक की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप इस पर विचार करेंगे। राजधानी होने के नाते शिमला शहर का नाम पूरे राज्यों में आता है और अगर बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको काम मुख्यालय से ही पड़ता है। हमारे यहां अगर पर्यटक आयें और अच्छा इम्प्रेशन ले करके न जायें तो इसका स्टेट के ऊपर भी फर्क पड़ता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इन सड़कों को जल्दी-से-जल्दी पूरा करेंगे।

13-03-2018/1150/NS/HK/2

**मुख्य मंत्रीः** अध्यक्ष महोदय, AMP (Annual Maintenance Plan) के तहत जो माननीय सदस्य जी ने पूछा है और इन्होंने यह जानकारी हासिल करने की बात कही है कि क्या बज़ट की एलोकेशन सब-डिवीज़न वाईज़ या डिवीज़न वाईज होती है? मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूं कि बजट की एलोकेशन डिवीज़न वाईज़ होती है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री अनिरूद्ध सिंह जी ने शिमला डिवीज़न नम्बर-1 की बात की है और कहा है कि शिमला डिवीज़न नम्बर-1 में बहुत कम पैसा दिया गया है। लगभग 89.48 लाख रुपये की राशि दी गई है। मैं देख रहा हूं कि बाकी मण्डलों की तुलना में यह राशि कम तो है लेकिन मैं इसके बावजूद भी माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि अगर हम इसे 31 मार्च तक देखेंगे तो यह फिगर लगभग 1.89 करोड़ तक बढ़ने की संभावना है।

दूसरा, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमने रोड मैंटेनैंस के लिए आगामी वित्त वर्ष यानि वर्तमान वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत AMP (Annual Maintenance Plan) लाने का प्रस्ताव किया है। हमारे प्रदेश में पहले सड़क बनना बहुत बड़ा विषय होता था। गांव में अगर सड़क नहीं है तो वहां के लोग सबसे पहले प्राथमिकता सड़क बनाने को देते हैं।

13.03.2018/1155/RKS/HK-1

**प्रश्न संख्याः 68.. जारी**

**माननीय मुख्य मंत्री... जारी**

अध्यक्ष महोदय, जब सड़क बन जाती है तो उसके बाद स्वभाविक रूप से यह प्रश्न आता है कि सड़क तो बन गई लेकिन सड़क कच्ची है और इसे पक्का किया जाए। इसकी मरम्मत के लिए बजट का प्रावधान किया जाए। इन सारी चीजों की मांग हमेशा रहती है। अबकी बार हमने इसके लिए प्राथमिकता दी है। हमने बजट में भी बड़े विस्तार से ज़िक्र किया है कि गांव को सड़कों से जोड़ा जाए। सड़कों की मरम्मत के लिए भी प्रावधान किया गया है क्योंकि जो सड़कें खराब हैं या सड़क बन गई है और चलने योग्य नहीं हैं तो उन सड़कों का कोई औचित्य नहीं बनता है। अगर सड़क में गाड़ी नहीं चलती है तो उस सड़क का कोई अर्थ नहीं है। सड़कों की मरम्मत की दृष्टि से हमने 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रावधान किया है। सड़कों की मरम्मत बहुत जरूरी है। हम उन सड़कों को प्राथमिकता भी देंगे, जिनकी हालत ज्यादा खराब है।

अध्यक्ष महोदय, हम उन सड़कों को भी प्राथमिकता देंगे जहां देश-विदेश से पर्यटक, पर्यटन की दृष्टि से आते हैं। परन्तु वे सड़कों की हालत देखकर परेशान हो जाते हैं और वापिस चले जाते हैं। इन सड़कों पर भी हमारी प्राथमिकता रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमने इस वर्ष के लिए '1700 किलोमीटर की तुलना में अगले वित्तीय वर्ष में 2500 किलोमीटर सड़कों की वार्षिक मरम्मत का टारगेट रखा है और इस टारगेट को हम पूरा करेंगे। माननीय सदस्य ने शिमला डिवीजन की बात की है, उस बारे में हम चिंता करेंगे। आपने फागू और चियोग दो सड़कों का जिक्र किया कि इनकी स्थिति ठीक नहीं है या इनका थोड़ा पैच खराब है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पैच को ठीक करने के लिए जो होगा वह किया जाएगा। ये दोनों सड़कें पर्यटन और आवाज़ाही की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहां से बड़ी तादाद में लोगों की गाड़ियों का आना-जाना रहता है। टूरिज़्म की दृष्टि से भी ये सड़कें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन सड़कों को हम ठीक करने की कोशिश करेंगे।

13.03.2018/1155/RKS/HK-2

**अध्यक्षः** माननीय मुख्य मंत्री जी, आपने सड़कों की मरम्मत के लिए धन का अलग से प्रावधान किया है। मेरा भी आपसे एक छोटा-सा सुझाव है। जो सड़कों के किनारे नालियां बन रही हैं, उन नालियों को बनाते समय उनके नीचे पक्का गटका डालने का प्रावधान डी.पी.आर. के अंदर शामिल न होने की वजह से, मिट्टी के ऊपर ही सारी नालियों की सी.सी. डल रही है। उसका बेस मज़बूत न होने की वजह से सारी-की-सारी नाली दो महीनों के अंदर ही निकल जाती है। इस पर अगर आप विचार करेंगे तो अच्छा रहेगा।

**मुख्य मंत्रीः** अध्यक्ष जी, इसका पालन किया जाएगा।

13.03.2018/1155/RKS/HK-3

**<u>प्रश्न संख्याः 69</u>**

**श्री जगत सिंह नेगीः** अध्यक्ष जी, केवल दो सब-डिवीज़न, BADP के तहत जिला किन्नौर में हैं। इनमें 60-60 से ज्यादा स्कीम्ज़ नहीं हैं लेकिन माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि सूचना एकत्रित की जा रही है। मेरा यह आरोप है कि सरकार जान-बूझकर BADP की सूचना नहीं दे रही है। क्या इसके लिए मुझे आर.टी.आई. का सहारा लेना पड़ेगा? दूसरा, मेरा प्रश्न यह है कि वर्ष 2017-18 में BADP का बज़ट दिसम्बर महीने में रिलीज़ किया गया क्योंकि उस समय चुनाव नज़दीक थे, इसके क्या कारण थे?

**अध्यक्षः** माननीय मंत्री जी, यदि आपके पास सूचना नहीं है तो आप इस सूचना को भेज दीजिएगा।

13.03.2018/1155/RKS/HK-4

**<u>प्रश्न संख्याः 70</u>**

**श्री सुख राम**ः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पांवटा का बस स्टैंड उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा तीन प्रदेशों को जोड़ता है। । इस बस स्टैंड की हालत बहुत दयनीय है। इसके शौचालय अभी भी काम नहीं करते हैं और वे बहुत गंदे हैं। बरसात के दिनों में यह बस स्टैंड जोहड़ बन जाता है। भारत विकास परिषद् द्वारा जो शौचालय बनाए गए हैं, उनके कनैक्शन भी अभी तक नहीं हुए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से आश्वासन चाहता हूं कि यह तीन प्रदेशों को जोड़ने वाला बस स्टैंड है, क्या आप इस बस स्टैंड को आधुनिक बस स्टैंड बनाने का विश्वास मुझे इस माननीय सदन में देंगे?

13.03.2018/1200/बी0एस0/वाई0के0-1

**प्रश्न संख्याः 70 ......क्रमागत**

वन **मंत्री**ः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता बहुत जायज है। मैं आदरणीय सदस्य से समय की कमी के कारण कहूंगा कि जो-जो आपको इस बस अड्डे में सुविधा चाहिए वह आप लिख कर दें। हमारी सरकार ने इस वर्ष 136 लाख का प्रावधान किया है और आवश्यकता के अनुसार जितना धन चाहिए होगा, हम पूरा पैसे का प्रावधान करेंगे, जिस प्रकार का कार्य आपको चाहिए वैसा हम उस अड्डे में बना करके देंगे।

**प्रश्न काल समाप्त**

13.03.2018/1200/बी0एस0/वाई0के0-2

**कागजात सभा पटल पर**

**अध्यक्ष**ः माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

**मुख्य मंत्री**ः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, इन्कर, वर्ग-III(अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना

---
संख्याःमुद्रण(बी)2-25/97 दिनांक 15.09.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.11.2017 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल रखता हूं।

**अध्यक्षः** अब माननीय कृषि मन्त्री जी कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

**कृषि मन्त्रीः** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियंत्रक महालेखापरीक्षक (डी0पी0सी0) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम सीमित का 33वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2016-17 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

**अध्यक्षः** अब माननीय वन मंत्री जी कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

**वन मन्त्रीः** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2014-15 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

13.03.2018/1200/बी0एस0/वाई0के0-3

## बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2018-2019 पर सामान्य चर्चा

**अध्यक्षः** अब वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट अनुमानों /वार्षिक वित्तीय विवरण पर आगे चर्चा जारी रहेगी। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी माननीय सदस्यों को एक सूचना देना चाहता हूं कि विगत दो वर्षों से लोक सभा में लोक सभा अध्यक्षा महोदय ने एक रेफरेंस सेक्शन माननीय सदस्यों के लिए प्रारम्भ किया है और हमने भी देखा, अति उपयोगी रेफरेंस सेक्शन है। हमारे पास उस प्रकार की बहुत सुचारू व्यवस्था नहीं है। परंतु पिछले एक सप्ताह में प्रयास करके हमारी जो विधान सभा की लाईब्रेरी है उसमें एक रेफरेंस सेक्शन क्रिएट किया है। कोई भी माननीय सदस्य यदि किसी विशेष विषय पर बोलना चाहता हैं और लाईब्रेरी में 24 घंटे पहले कोई नोटिस देते हैं तो प्रयास करेंगे कि उनको

---

उससे सम्बन्धित जानकारी लाईब्रेरी से या नेट के माध्यम से निकाल करके उपलब्ध करवाई जाए ताकि बोलने वाले सदस्य को सुविधा रहे। यह नया प्रयास है, इसमें कुछ कमी रह सकती है, उसके लिए माननीय सदस्यों के सुझाव सदैव आमंत्रित होंगे।

अब माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र बरागटा जी चर्चा में भाग लेंगे।

**श्री नरेन्द्र बरागटाः** धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, गत विधान सभा चुनाव के बाद निर्वाचित हो करके पहली बार सदन में बोल रहा हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई और शुभ कामनाएं देना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आदरणीय जय राम ठाकुर जी के कार्य-काल में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे और वे प्रदेश के सब लोगों को जैसे माननीय मोदी जी ने "सबका साथ सबका विकास" करने का जो लक्ष्य दिया है, इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको भी बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप इस गौरवमयी सदन के अध्यक्ष बने हैं और मैं देख रहा हूं चाहे धर्मशाला में सत्र हुआ हो, चाहे शिमला में हुआ हो। जिस खूबी के साथ आपने इसको निभा रहे हैं मुझे पूरी आशा है कि जो माननीय सदस्य हैं वे इस बात के लिए आपकी प्रशंसा करते रहेंगे। इसलिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको शुभ कामनाएं देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय हमारे नौजवान विजयी हो करके आए हैं, मैं इनको भी शुभकामनाएं देता हूं।

13.3.2018/1205/DT/YK-1

**श्री नरेन्द्र बरागटा .....जारी**

माननीय मुख्य मंत्री जी मैं आप को और आप के मंत्रिमण्डल को भी बहुत- बहुत बधाई देता हूं। माननीय सदस्य जो इस माननीय सदन में चुन कर आए हैं, मैं सभी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। माननीय जय राम ठाकुर जी ने अभी बजट प्रस्तुत किया है। अध्यक्ष महोदय, यह दमदार ही नहीं है बल्कि जानदार और शानदार भी है। इसमें बहुत सोच लगाई गई है। विकास को आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें जोर दिया गया है। इसकी धार गांव, पहाड़ और कन्दौरों की तरफ जा रही है। इसके सकारात्मक परिणाम आएगें। हमें ऐसी आशा करनी चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आर्थिक सर्वेक्षण यहां पर रखा है, उससे मैं थोड़ा

व्याकुल हूं। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं, कोई चुक हुई है। हमारी टोपोग्राफी, हमारी भौगोलिक स्थिति, लगता है कि हम शायद अनजाने में उसका आकलन करने में पीछे रह गए हैं क्योकि हम राष्ट्रीय विकास दर से भी नीचे आ गये हैं। तमाम सरकारें चाहे किसकी भी रही हो जाने-अनजाने में यह हो गया है और जो प्राथमिक क्षेत्र है, कहीं-न-कहीं हमने उसकी अनदेखी की है। ऐसा आर्थिक सर्वेक्षण बोलता है। मै माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रदेश की जनता इनको साधुवाद देगी। जो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी उसको फिल करने का इन्होंने प्रयास किया है। बागवनी और कृषि प्राथमिकता के दो क्षेत्र हैं। चाहे डॉ0 परमार रहे हो, माननीय वीरभद्र सिंह जी रहे हो, माननीय शान्ता कुमार जी रहे हो, ठाकुर राम लाल जी रहे हो, और प्रो0 प्रेम कुमार धुमाल जी रहे हो और अब आप आए हैं, इस तरफ ध्यान तो दिया गया। लेकिन इस क्षेत्र को जितना आगे बढना चाहिए था उतना वह बढ नहीं सका। इस तरफ माननीय मुख्या मंत्री जी ने अपनी चिन्ता भी व्यक्त की है। मैं थोडे आकड़े इस माननीय सदन में प्रस्तुत कारना चाहता हूं। आप देखेंगे कि 50 और 51 के दशक में यह जो कृषि और बागवानी है इसका सबसे बड़ा योगदान जीडीपी में 67 प्रतिशत था। 67-68 के दशक में घटकर 55 हो

13.3.2018/1205/DT/YK-2

गया। 19 90-91 के दशक में यह 26 में आ गया और 2016-17 में ठाकुर महेन्द्र सिह जी मै आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं 2016-17 यह जी.डी.पी. घट कर प्रतिशत आ गई। पिछली बार जैसे सेब की फसल लगी नहीं तो इसमें कुछ प्वाईंट का असर दिखता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सेब के कारण जी.डी.पी. बढ़ सकती है। लेकिन इस को सही करने के लिए मुख्यमंत्री जी मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। आप ने इस को केन्द्र बिन्दु बनाया है। इस बजट में जो सार है वह यह है कि जो हमारा मुख्य विषय है उसकी तरफ हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। आप ने उसकी तरफ ध्यान दिया है। मैं हिमाचल प्रदेश के सारे क्षेत्र के बागवनों और किषानों की तरफ से आप को बधाई देना चाहता हूं। क्योकि

सबसे बड़ी ताकत कृषि व बागवानी की तरफ आप अपनी ताकत संजोने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय अटल जी एक लाइन हम हर वक्त बोलते हैं। मैं उस लाइन को यहां भी कोट करना चाहता हूं;

'सूरज निकेलेगा और अंधेरा छटेगा' ऐसा हमारा स्वप्न है। अटल जी ने इस देश व प्रदेश के लिए एक स्वप्न देखा है। उस स्वप्न को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। उसमें आप अपना-अपना योगदान देंगे। उसके लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मुझे पता है कि आपको बहुत समय लग सकता है जो आपने बजट में दमदार तरीके से यहां पर सुझाव रखे हैं। अध्यक्ष जी ने मुझे बोलने के लिए केवन 15 मिनट दिए हैं।

**13.03.2018/1210/SLS-AG-1**

**श्री नरेन्द्र बरागटा... जारी**

आप जो बागवानी सुरक्षा योजना लाए हैं उसमें सबसे पहले तो प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना है, जिसमें आपने जो यह जोड़ा है, उसका लाभ प्रदेश की जनता और बागवानों-किसानों को मिलेगा। इसमें अच्छी बात यह है कि जो हमारे राष्ट्र के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हैं, उन्होंने इसमें विशेष ध्यान रखा है कि जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं, उनके लिए 90% अनुदान दिल्ली से आने वाला है। इसके अंतर्गत आपको इसका भी लाभ होगा। मैं खास करके आपका और विशेष करके प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो फसल बीमा योजना पहले थी, वह मौसम पर आधारित थी, उसमें ओलावृष्टि और अतिवृष्टि की मद शामिल नहीं थी जबकि इस बार इसको जोड़ दिया गया है। पिछली बार उसके बारे में बैंक से आ करके कोई प्राईवेटली कहा करते थे और वह कम-से-कम 30% तो प्रीमियम ही लिया करते थे, लेकिन अब यह इसमें ही निहित कर दिया गया है और यह बड़ी खुशी की बात है कि इसमें 5% में ओलावृष्टि और ऐसी-ऐसी चीजें जो पहले उपलब्ध नहीं थीं, उनको रखा गया है जिसका बहुत बड़ा लाभ हमारे प्रदेश के बागवानों और किसानों को होने वाला है।

ऐंटि हेलगन में आपने 60% का अनुदान देने की कृपा की है। पहले भी हमने यहां पर यह पायलट प्रोजैक्ट शुरू किया था। उसमें आपने 10 करोड़ रुपया रखा है जिसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

ऐंटि हेलनैट के अंतर्गत पहले 2.27 करोड़ रुपये थे जिन्हें बढ़ाकर आपने 10.00 करोड़ रुपया कर दिया है। मैं ज़रूर इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। केवल मात्र बजट में किसी एक सब्जैक्ट को रखकर उसमें टोकन पैसा डालने का कोई लाभ नहीं है। अगर आप बागवानी मंत्री या कृषि मंत्री जी से आंकड़ें मंगवाएंगे तो जो सब्सिडी देय है, उसकी फाइलें और मामले इतने ज्यादा बढ़ गए हैं जिनकी अभी तक अदायगी नहीं हुई है जबकि मार्च का महीना आ गया है। लोगों को ज़रूरत होती है और आपने पहले ही 2.50 करोड़ रुपये के स्थान पर 10.00 करोड़

**13.03.2018/1210/SLS-AG-2**

रुपया कर दिया है। मुझे लगता है कि आपने इस समस्या का समाधान देने का प्रयास किया है जिसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

शिमला में और कांगड़ा में आपने बागवानी से संबंधित विशेष केंद्रों को खोलने का जो निर्णय लिया है, वह स्वागत योग्य है। एक छत के नीचे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में अगर हमारे प्रदेश के किसानों और बागवानों को उतरना है तो हमको तकनीकी का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। आप यूरोप जाइए या अमेरिका जाइए तो वहां आप देखेंगे कि वहां डीप स्वॉयल है और वहां की टैक्नोलोजी बहुत उन्नत है। उनका मुकाबला हम किस तरह से कर सकते हैं, यह संभव नहीं है। हमारी टोपोग्रॉफी, हमारी स्वॉयल और हमारे यहां जो पद्धति है, उनका मुकाबला करने में उससे हमें बहुत ज्यादा आसानी नहीं हैं। लेकिन आपने जो यह केंद्र खोले हैं, इनका लाभ हमारे प्रदेश के बागवानों को मिलने वाला है। निचले क्षेत्रों में नींबू प्रजाति, आम, संतरा और ऊपर के क्षेत्रों में नाशपाती और अखरोट से लेकर सेव की जो फसल होती है, उनको तकनीकी दृष्टि से हम किस तरह से आगे बढ़ाएं, किस तरह से

हम चीन का मुकाबला कर सकें, यूरोप का मुकाबला कर सकें, अमेरिका का मुकाबला कर सकें, यह केंद्र उसके लिए सहायक सिद्ध होने वाले हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने बजट में इसका प्रावधान किया है।

आपने 100 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश में बागवानी विकास योजना के लिए आवंटित किया है जिसका लाभ होने वाला है। रूट स्टॉक आयात होगा। आप लाखों परिवारों के लिए लाखों रूट स्टॉक्स मंगाने वाले हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वर्ष 1998 में हमने इसको USA और France से मंगवाया था। मुख्य मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है; बागवानी मंत्री जी, मेरा आपसे भी निवेदन है कि जो रूट स्टॉक आप मंगवाएंगे; मैं यह मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना भी चाहता हूं कि वर्ल्ड का सबसे बढ़िया रूट स्टॉक आज के संदर्भ में केवल मात्र USA और France में है। लेकिन मैं देख रहा हूं और मैं कुछ चीजें ओब्जर्व कर रहा हूं कि न जाने यह क्यों हो रहा है, पता नहीं क्यों पुरानी सरकार इटली की तरफ ही भागती रहती थी? सारा

**13.03.2018/1210/SLS-AG-3**

कुछ इटली से ही मंगवाया जा रहा है। वह क्यों मंगवाया जा रहा है, इसका मुझे पता नहीं। लेकिन एक बात तय है; इटली से अभी रूट स्टॉक आए, कुछ प्लांट्स आए, उसको लेकर मेरे नेतृत्व में प्रदेश स्तर पर हमें डायरैक्टोरेट का घेराव करना पड़ा। उसमें वायरस आ गया। मई में जा कर वह रूट स्टॉक रोपे जा रहे हैं। जो दिसम्बर में रोपने हैं, वह मई में जाकर रोपे जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज का बागवान बहुत सक्षम है। आज का बागवान अमेरिका जाकर खुद उस पौध को ला रहा है। आज का बागवान फ्रांस से पौध ला रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि

**13/03/2018/1215/RG/AG/1**
**श्री नरेन्द्र बरागटा-----जारी**

अगर यह रूट स्टॉक अच्छा आएगा, तो हम जल्दी और अच्छी पैदावार करेंगे तथा अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा पर खरे उतरेंगे। आपने जो यह क्रान्तिकारी कदम उठाने का प्रयास किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया फ्रांस और अमरीका से ही रूट स्टॉक मंगवाइए। कृपया मेहरबानी करके इस इटली को छोड़ दीजिए, कहीं आप भी इटली की तरफ न चले जाएं। इसलिए मैं यहां पर आपको आगाह करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आम, लीची, अमरूद, नींबू प्रजाति के फलों का 400 हैक्टेयर का एक क्लस्टर बनाकर हम अलग से एक प्रावधान कर रहे हैं that was really needed. हिमाचल प्रदेश का जो निचला हिस्सा है, उसमें बागवानी की बहुत पोटेन्शियल है और उसको पनपने के लिए आपने यह एक बहुत अच्छा इन्सेन्टिव दिया है। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि अब लेबर की बहुत कमी है। मैं यहां देखता हूं कि इधर भी और उधर भी सारे बागवान हैं, मेरे ख्याल से एक-आध कोई छूटा होगा जो बागवान नहीं होगा। राकेश जी, यदि आप सारी जगह नजर डालेंगे, तो ऐसा लगता है कि माननीय अध्यक्ष जी से लेकर मुख्य मंत्री महोदय से लेकर मेरे ख्याल से यहां कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो बागवानी नहीं करता हो। लेकिन लेबर की समस्या बहुत है, टैक्नॉलॉजी को अपनाने की समस्या है। कहां लाहौल-स्पीति, कहां किन्नौर और कहां ऊना है? इसका फायदा भी है और नुकसान भी है। इसलिए तकनीक को अपनाना बहुत आवश्यक है। टूल्ज ऐसे हों जो लेबर की समस्या भी खत्म करें और हमें उन उन्नत टूल्ज का फायदा भी हो। आपने इसके लिए प्रावधान किया है। आपने पॉवर, स्प्रेयर, टिलर, ग्रेडिंग, पैकिंग और सी.ए. स्टोर्ज एवं सब्जी मण्डियों का विस्तार करने का निर्णय लिया है जिसमें लगभग 150 करोड़ रुपये अलग से रखा है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। इसका हमारे किसानों और बागवानों को बहुत लाभ होने वाला है।

अध्यक्ष महोदय, फूलों तथा सब्जियों पर पूरे प्रदेश में Himachal Pradesh Certain Goods Carried by Road कर को आपने समाप्त कर दिया है। This is a welcome step. मैं माननीय मुख्य मंत्री का इसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। यह जो कदम इस बजट में लिया गया है इसका लाभ भी हमारे किसानों-बागवानों को मिलने वाला है। किसानों को सस्ती बिजली मिलनी वाली है। प्रधानमंत्री कृषि योजना में किसानों और बागवानों को 338 करोड़ रुपये का जो प्रावधान है, उसका लाभ भी

**13/03/2018/1215/RG/AG/2**

हमारे किसान-बागवानों को होने वाला है। 'सड़कों को बनाने व उनका रख-रखाव', इस बारे में आज सुबह एक प्रश्न लगा था और उसका उत्तर भी आपने यहां दिया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन आपने एक अच्छा काम यह किया है कि क्रॉस ड्रेनेज और साईड ड्रेनेज, जिसका अध्यक्ष महोदय ने भी जिक्र किया, इसमें इस बार 50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है और जरूरत के मुताबिक यदि आप इसमें बजट बढ़ाएंगे, तो हम आपके आभारी रहेंगे। इसके अतिरिक्त एक और out of the box आपने काम किया है। यह जो आपने काम किया है इसके लिए धन्यवाद। इसमें कुछ क्षेत्र ऐसे भी जोड़े गए हैं जो बर्फ से लदे रहते हैं और तीन महीने वहां बसें नहीं चलती हैं। छोटी गाड़ियां नहीं चलती हैं। वहां 6-6 फुट बर्फ रहती है और पैदल भी नहीं चला जाता। बहुत असुविधा होती है। शायद आपने कोई स्टडी की होगी और वह स्टडी सही भी है। मैं यहां बता दूं कि रोम में जहां बहुत बर्फ पड़ती है, वहां मुश्किल से एक घण्टे के लिए भी सड़क बंद नहीं होतीं। आपने उस टैक्नॉलॉजी को लाने का निर्णय लिया है। --(घण्टी)---जिसके लिए आप ग्लोबल टैण्डर्ज फ्लोट करने वाले हैं और खड़ा पत्थर या ऊंचे क्षेत्रों में उस टैक्नॉलॉजी को अपनाकर इसके लिए आप प्रयास करने वाले हैं ताकि सड़क कभी अवरुद्ध न हो, । इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मख्य मंत्री सड़क योजना, गांव को जोड़ना, फूलों की खेती, पर्यटन के अनछुए क्षेत्र को इस बार छूने का प्रयास करेंगे। खड़ा पत्थर, गिरी गंगा, हाटकोटी, कूपण, इसमें मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें बागवानी को जोड़ने की आवश्यकता है ताकि लोग देख सकें कि किस तरीके से सेब या अन्य फल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पैदा होते हैं। पर्यटक उनको देख सकें और आनन्द ले सकें। 'देव भूमि दर्शन', 'वन समृद्धि,जन समृद्धि' आजीविका से नौजवानों के लिए नए द्वार खुल जाएंगे। युवाओं के लिए आपने अलग से योजना रखी है। 'मुख्य मंत्री खेल विकास योजना' और एक 'हिमाचल प्रदेश पत्रकार कल्याण योजना' भी इसमें रखी गई है। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने जो पत्रकार कल्याण योजना को इसमें स्थान दिया, बल्कि अहम् स्थान दिया है और यह सच भी है। मैंने देखा है और मैं स्वयं भी शिमला में पैदा हुआ हूं। एक ट्रिब्यून के पत्रकार श्री पी.एन. शर्मा जो हमारे बीच में नहीं रहे,

किस तरह से उनको अपनी जिन्दगी गुजर-बसर करनी पड़ती थी। आपने इस तरफ जो ध्यान दिया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं।

**13/03/2018/1220/MS/DC/1**

**श्री नरेन्द्र बरागटा क्रमागत----**

इससे हमारे प्रदेश के जितने भी पत्रकार साथी हैं उनको इस "पत्रकार कल्याण योजना" के अंतर्गत लाभ होने वाला है। उसके लिए मैं आपको तथा पत्रकार बन्धुओं को भी बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपने जो 2 लाख 50 हजार रुपये की राशि का प्रावधान किया है अगर इस राशि को बढ़ाना भी पड़े तो मेरा भी आपसे निवेदन रहेगा कि यह राशि बढ़नी चाहिए।

बजट में ऑर्गेनिक खेती के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से महिला वर्ग के लिए भी बहुत सारी योजनाएं लाने का आपने प्रावधान किया है। -(घण्टी)- अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपना भाषण समाप्त करने जा रहा हूं।

इससे पहले कि मैं अपने बजट भाषण को समाप्ति की ओर ले जाऊं, मैं एक-दो बातें कहना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, कल मुकेश अग्निहोत्री जी ने यहां दो बातें कहीं। वे इस समय सदन में मौजूद नहीं हैं। वे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। वे बहुत अच्छे वक्ता है और पत्रकार भी रहे हैं। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं और उनकी अबसेंस में मैं आप सबको भी बधाई देना चाहता हूं कि उनको आपने CLP का लीडर चुना है। उन्होंने एक बात कही कि मुख्य मंत्री की पीठ थपथपाई जा रही है। मैं पूछता हूं कि अगर हम मुख्य मंत्री जी की पीठ न थपथपाएं तो क्या लालू प्रसाद जी की पीठ थपथपाएं? अगर वे ऐसा बोलते कि वीरभद्र सिंह जी की पीठ थपथपाओ तो हां, क्यों नहीं, क्योंकि इन्होंने कम-से-कम इतनी कर्टेसी तो दिखाई। इन्होंने कहा कि जय राम जी अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं और इनको मैं इसके लिए 50 प्रतिशत नम्बर देता हूं लेकिन मुकेश जी तो जीरो पर पहुंच गए। मुझे मुकेश जी को इतना निवेदन जरूर करना है कि कम-से-कम अपने लीडर की बात तो सुन लीजिए। इतना अच्छा बजट है आप तारीफ करने में क्यों कन्जूसी करते हो? हम चुने हुए नुमाइन्दे हैं इसलिए हम लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर के हिमाचल प्रदेश

को हिन्दुस्तान में नम्बर वन पर पहुंचाना है और उसके लिए मुख्य मंत्री जी आपने जो यह बजट दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद और बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुकेश जी सदन में नहीं बैठे हैं। उन्होंने यहां

**13/03/2018/1220/MS/DC/2**

कानून-व्यवस्था की बात भी उठाई। मेरे घर में जघन्य अपराध हो गया; गुड़िया कांड हो गया और यहां किस तरह की बात हो रही है? अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उसके बाद बोलने के लिए क्या रहता है? अगर मुकेश जी सदन में मौजूद होते, वैसे मैं उनसे बाद में भी बात कर सकता हूं लेकिन मैं उनसे एक बात जरूर कहूंगा। आप बताइए, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा पानी के टैंक में मिलता है। मेरे गांव का 22 साल का लड़का रोहड़ू में दिन-दिहाड़े मार दिया जाता है और आज तक उसका कुछ पता नहीं चला है। फिर यहां कानून-व्यवस्था की बात की जाती है? मैं ऐसे ही अनेकों उदाहरण दे सकता हूं और मुझे इन सब बातों का दुःख है।

इसी तरह से यहां संस्थानों को बन्द करने की बात आई। ठीक कहा, संस्थान बन्द नहीं होने चाहिए बल्कि उनका एक्सपैंशन होना चाहिए। प्रदेश की जनता को उनका लाभ होना चाहिए लेकिन मैं एक उदाहरण यहां देना चाहता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से हमने एक इंजीनियरिंग कॉलेज प्रगति नगर में खोला। यहां अभी नये संस्थान जिनके पास बिल्डिंग और जमीन भी नहीं है, कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर और बजट नहीं है उनको खोलने की बात जरूर की गई लेकिन यहां तो जिन्दा संस्थान को ही मारने का प्रयास पिछले पांच सालों के अंदर हुआ है। तकनीकी शिक्षा मंत्री वहां जाने के लिए पांच सालों में पांच मिनट नहीं निकाल सके। वह हिन्दुस्तान का तीसरा ऐसा संस्थान है जहां पर बी.टैक. है, पॉलीटैक्निक है तथा जहां पर आई0टी0आई0 है। वह हिमाचल का ऐसा पहला संस्थान है लेकिन वहां पर ट्रेड खत्म कर दिए गए। वहां बच्चे ऊना और चम्बा से लेकर पढ़ते हैं। वहां सबके बच्चे पढ़ते हैं। वहां क्या बी0जे0पी0 वालों के बच्चे पढ़ते हैं?

अध्यक्ष जी, मैंने एक दिन मुकेश जी को टेलीफोन किया। उस समय वे उद्योग मंत्री थे। वे मेरे मित्र भी हैं इसलिए मैंने बड़े विश्वास से उनको टेलीफोन किया। कांग्रेस के एक छोटे से कार्यकर्त्ता, उनका मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने एक रात को मशीन लाई,

**अध्यक्षः** माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

**13/03/2018/1220/MS/DC/3**

**श्री नरेन्द्र बरागटाः** अध्यक्ष जी, मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मशीन लाकर उस कॉलेज की पूरी दीवार को तोड़कर तीन दिन तक पत्थर ढोते रहे और अपना मकान बनाते रहे ताकि वहां पर किराये पर बच्चों को रख सकें। मैंने मंत्री महोदय को टेलीफोन करके कहा कि इस पर ऐक्शन लीजिए लेकिन अभी तक कोई ऐक्शन नहीं हुआ है। यहां आप नये संस्थान की बात कर रहे हो, यहां तो पुराने जीते-जागते संस्थान को आपने मारने का प्रयास किया है। उसका तो कहीं-न- कहीं उत्तर मिलना चाहिए। इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैंने कर्नल शांडिल जी के साथ काम किया है। ये बहुत ही सज्जन पुरुष हैं और मैं तो भावनात्मक रूप से इनके साथ जुड़ा हूं क्योंकि मेरे परिवार में मेरे बड़े भाई जो एयर कमाण्डर के रूप में सेवारत्त थे, वे आपके दोस्त भी रहे हैं।

**13.03.2018/1225/जेके/डीसी/1**

**श्री नरेन्द्र बरागटाः------जारी-----**

आज वे इस दुनिया में नहीं है। आप बहुत अच्छा बोलते हैं,लेकिन दिक्कत एक आ गई है, मैं यहां पर कल नहीं था बल्कि कहीं सुन रहा था। आपने तो सर दिल्ली में ही मोर्चा बांध लिया है। बहुत जल्दी दिल्ली चले गए। पता नहीं दिल्ली में यहां की बात करते तो कितना मज़ा आता। You are a knowledgeable person. आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन दिल्ली में जा करके मोर्चा बांध लिया। इंदिरा गांधी की बात क्यों नहीं करनी चाहिए, राजीव गांधी की बात क्यों नहीं करनी चाहिए? बल्कि सभी की बात करनी चाहिए। क्या अटल बिहारी वाजपेयी की बात नहीं करनी चाहिए, जिन्होंने इस प्रदेश को प्रधानमंत्री सड़क योजना दी?

क्या नरेन्द्र मोदी जी की बात नहीं करनी चाहिए,जिन्होंने फसल बीमा योजना ला करके आपके जिला के टमाटर को सक्सैस कर दिया? क्या यह बात नहीं करनी चाहिए कि इस प्रदेश में हमारे प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने 50 हजार करोड़ के 69 नेशनल हाई वेज़ दिए हैं, हमें यह बात भी करनी चाहिए? इसको आप अन्यथा मत लें। हमें सबकी बात करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, समय के अभाव के कारण मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अंत में, मैं इस बजट के समर्थन में जितने भी मेरी जुबान में शब्द है, इसकी प्रशंसा करना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद के साथ-साथ इनको बधाई भी देना चाहता हूं। आपने मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**13.03.2018/1225/जेके/डीसी/2**

**अध्यक्षः** अब श्री रामलाल ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे।

**श्री रामलाल ठाकुरः** माननीय अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने वर्ष 2018-19 का जो बजट पेश किया है, मैं उस चर्चा में अपने आपको शामिल करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को मुबारकवाद भी देना चाहूंगा कि प्रदेश में नौज़वान, सुन्दर और बड़ी सहनशीलता वाले मुख्य मंत्री और उनका मंत्रिमण्डल यहां पर बैठा है और पहला बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है। अध्यक्ष महोदय, हम इधर-उधर की जो दिवारें हैं उनमें बंध के रह जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक प्रदेश की बात है, प्रदेश के बनने के बाद जो-जो घटनाएं घटी हैं, प्रदेश ने कहां से चलना शुरू किया और आज कहां पर पहुंचा है एक बहुत बड़ा लम्बा सफ़र हिमाचल प्रदेश के लोगों ने तय किया है। आज प्रदेश यहां पर खड़ा हुआ है यह कोई दो साल, चार साल, दो महीने, चार महीने का परिश्रम नहीं है इस बारे में मैं कहूंगा कि यह सदन की महान परम्पराएं रही हैं। इस सदन में शुरू से ले करके अनेक विद्वान  रहे हैं जो यहां से गए हैं और प्रदेश में आज की तारीख में जहां पर आज हम खड़े हैं , हम अगर केवलमात्र आगे को देखें और पिछली तरफ ध्यान भी न दें कि हमने

कहां से चलना शुरू किया तो मैं यह कहूंगा कि शायद उसमें न हम अपने से और न प्रदेश के आने वाले दिनों से न्याय करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जबसे हमने प्रजातंत्र में कदम रखा, तब से हमने हिमाचल प्रदेश को छोटे रूप से ले कर विशाल हिमाचल प्रदेश, पूर्ण राज्य के दर्ज़े तक देखा है और आज की तारीख में हम सारे बड़े-बड़े राज्यों की तुलना में अपने आपको खड़ा करते हैं । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज यह भी देखने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि प्रदेश के अन्दर कितनी जगह पर रोशनी होती थी? कितना विद्युतिकरण प्रदेश का था, कितना बिजली का उत्पादन हमने किया, कितने स्कूल प्रदेश के अन्दर थे और

13.03.2018/1230/SS-HK/1

**श्री राम लाल ठाकुर क्रमागतः**

कितने स्वास्थ्य संस्थान थे और कितनी सड़कें बनी थीं, आज की तारीख में जहां पर हम खड़े हुए हैं, अध्यक्ष महोदय, बड़ा अन्याय होगा अगर हम पीछे के सफ़र की बात न करें और केवल मात्र एक वर्ष आगे और एक वर्ष पीछे जा कर हम अपने विचारों को वहीं तक सीमित रखेंगे तो मैं कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के लिए हमारा व्यवहार न्यायपूर्ण नहीं होगा। यहां पर माननीय सदन में जितने भी सदस्य बोले, कहते तो सारे हैं कि राजनीति से ऊपर उठ कर प्रदेश के सर्वांगीण विकास की बात करें लेकिन होता यह है क्योंकि प्रजातंत्र है, पार्टियों की परिधि है, सीमाएं हैं और उन सीमाओं में रह कर चाहे जुबान से जो मर्जी कहो लेकिन फिर उसी राजनीतिक परिवेश में आ कर हम बात करते हैं। लेकिन सिर्फ कहने के लिए लोग बड़ी-बड़ी बातें मुंह से कर देते हैं। अगर शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो वहीं-के-वहीं आ कर खड़े होते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले इस माननीय सदन में जो बजट हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने यहां पर प्रस्तुत किया है मैं उसके बारे में थोड़े शब्दों में बात करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि यह एक प्रक्रिया है। अगर आप इस साल के बजट को देखें, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर पढ़ा तो हिन्दी में 84 पन्नों का यह बजट है। अगर आप पिछले साल का माननीय वीरभद्र सिंह जी का बजट भाषण देखें तो 78 पृष्ठों में वही सारी चीज़ें हैं। यहां पर किसी ने कहा कि पुरानी शराब नई बोतलों में डाल दी। अध्यक्ष महोदय, नई बोतलों में नहीं डाली, बोतल भी वही है

लेकिन उसका बाहर से लेबल बदल दिया। मुख्य मंत्री जी, मेरा निवेदन यह है कि ये जो सारी चीज़ें हैं क्योंकि मुझे सरकार में रहने का बहुत वर्षों तक मौका भी मिला है मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सारा काम वही प्रिंट करने वाले लोग हैं, वही टाइपिस्टस हैं, ये थोड़ा ज्यादा व्हाइट है, पिछले साल थोड़ा-सा पीले रंग पर था, वैसे व्हाइट ही था, लेकिन इतना ज्यादा सफेद नहीं था। अगर हम दोनों बजटस को देखें तो हमारे जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं --(व्यवधान)-- गुड्डू जी, मैं एक बात बताऊं आप कृपा करके गुड्डू बन के ही रहो। छेड़ोगे तो मैं ज्यादा बोलूंगा। वहां से घंटी बजेगी, मुझे शांतिप्रिय वातावरण में अपनी बात कहने के लिए इनको कहो। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि वही अधिकारी हैं जोकि यहां पर गैलरी में बैठे हैं, उन्होंने ही धूमल साहब का बजट तैयार किया था। उन्होंने ही माननीय वीरभद्र सिंह जी का पांच सालों तक बजट तैयार किया। उन्होंने ही आज बदली हुई

**13.03.2018/1230/SS-HK/2**

परिस्थितियों में पहला बजट जय राम जी का भी तैयार किया। मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें कुछ जो जोड़ा गया, वह यह जोड़ा गया क्योंकि चुनाव से पहले और आज की तारीख में आप क्या लोगों में संदेश देना चाहते हैं कि नई सरकार क्या कर रही है। मेरा आपसे एक निवेदन है कि यह जो बजट है इस बजट में मैं नहीं कहूंगा कि सब कुछ गलत ही गलत है। जहां तक सरकार ने बजट दिया है वह परिधि में रह कर दिया है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि जितने भी हमारे फॉरेन ऐडिड प्रोजैक्ट्स हैं, जितना भी विदेशों से पैसा आता है या हिमाचल प्रदेश को जो केन्द्र सरकार पैसा देती है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस मुल्क के अंदर आप देखें तो सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय में एक रोलिंग प्लान चली थी। कहा था कि पंचवर्षीय योजनाओं की ज़रूरत नहीं है और कोई एनुअल टारगेट्स की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम रोलिंग प्लान चली कि हम काम करेंगे और देखेंगे कि आगे के लिए क्या काम रहता है।

**13.03.2018/1235/केएस/एचके/1**

**श्री राम लाल ठाकुर जारी----**

अगले वर्ष उसके मुताबिक काम करेंगें लेकिन अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच नहीं है कि साल के बाद रोलिंग प्लान को वापिस अपनी पटड़ी पर आना पड़ा है। इस मुल्क के अंदर भी और उसी कड़ी में प्रदेश में भी पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं के माध्यम से, क्योंकि हमारा टारगेट होता था इसीलिए तो प्रदेश यहां पर खड़ा हुआ है। बड़े-बड़े राज्यों की तुलना में पहली पंक्ति में हमारा प्रदेश आता है। वर्ल्ड बैंक की टीम आयी थी, उन्होंने शिमला में प्रैस काँफ्रेंस की कि जितना शिक्षा का विस्तार और जितना अच्छा ढांचा प्रदेश में हैं, हिन्दुस्तान में शायद बाकी जगह पर नहीं है। गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग हैं उनको उभारने के लिए प्रदेश सरकार ने जो कार्यक्रम चलाए शायद बाकी राज्यों में वो इतने नहीं है। उन्होंने यहां के लॉ एण्ड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में भी प्रैस काँफ्रेंस में कहा और साथ में स्वास्थ्य सेवाएं जो प्रदेश के अंदर हैं, उनके लिए भी प्रदेश की पीठ थपथपाई थी।

अध्यक्ष महोदय, कारण यह है कि राजनीतिक परिधि में रहकर, पांच साल में सरकार ने कुछ भी नहीं किया, हमारी परफोरमेंस ज़ीरो रही, इस प्रकार के राजनीतिक भाषण हमने प्रदेश के अंदर दिए। दिल्ली की सरकार ने पिछले वर्षों में चाहे विद्युतिकरण हो, चाहे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाने की बात हो, चाहे सामाजिक सेवाओं का कार्यक्रम हो, स्वास्थ्य सेवाएं हों या स्कूल हों, उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अच्छा काम किया गया है। यहां तक कि प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने भी यह कहा है। आप लोग यहां पर ट्रांसपोर्ट के ऊपर चर्चा कर रहे थे। जो इस वक्त इस माननीय सदन में नहीं हैं, उनके ऊपर भी कटाक्ष कर रहे थे लेकिन मैं रैफर करना चाहूंगा , भारतवर्ष की पार्लियामैंट के अंदर सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने हिमाचल प्रदेश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का जिक्र किया था जो कि रिकॉर्ड के अंदर है कि जितना अच्छा काम हिमाचल प्रदेश के ट्रांसपोर्ट विभाग ने, वहां के मंत्री ने किया है, I put on record कि वहां पर सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने अपने भाषण में कहा कि हिमाचल प्रदेश

**13.03.2018/1235/केएस/एचके/2**

पूरे भारतवर्ष में आगे हैं और उसका अनुसरण बाकी राज्यों को करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर हम अपना राजनीतिक गुब्बार निकालने का प्रयास करते हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपैयी जी ने इस मुल्क के प्रजातंत्र को बहुत कुछ दिया है। पं0 जवाहर लाल नेहरू जी के समय से ले कर वे इस मुल्क के प्रधान मंत्री पद तक पहुंच गए। लेकिन मैं यह पूछना चाहूंगा कि आज कुछ नेताओं के हालात क्या है? आज कारण क्या है कि कुछ नेता 75 साल की उम्र में रिटायर हो गए? कहा जा रहा है कि 75 साल की उम्र हो गई इसलिए उनको राजनीति में रहने की जरूरत नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। सभी को मालूम है कि कौन-कौन से नेता हैं जिनसे किनारा किया गया। उनमें माननीय शांता कुमार जी भी पहली पंक्ति में हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के वाईस प्रैज़िडैंट रहे हैं लेकिन मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह राजनीतिक द्वेष की भावना नहीं है। प्रश्न कोई कांग्रेस, कम्युनिस्ट या भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या हम व्यक्तिगत स्वार्थ से अपनी पार्टी के अंदर भी, अपनी विचारधारा के अंदर भी क्या इस प्रकार का खोखलापन पैदा नहीं कर रहे हैं? माननीय अटल बिहारी वाजपैयी जी ने इस मुल्क को, प्रजातंत्र को बड़ा मज़बूत आधार दिया और उसको नकारा नहीं जा सकता परन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार से जो हिमाचल प्रदेश को मिला, उसको भी नकारा नहीं जा सकता। यह प्रदेश न होता, हमारा स्वरूप न होता अगर भारतवर्ष के प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू नहीं होते।

**13.3.2018/1240/av/yk/1**

**श्री राम लाल ठाकुर------- जारी**

हम 18वें राज्य के तौर पर नहीं आ सकते थे अगर श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारतवर्ष की प्रधान मंत्री न होती। बरागटा जी, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 90 व 10 के अनुपात के हिसाब से जो पैसा आने की बात है उसके लिए हमें श्रीमती इंदिरा गांधी को नहीं भुलाना चाहिए। जब हिमाचल प्रदेश 18वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था तो श्रीमती इंदिरा गांधी माल रोड पर आई थीं और उस दिन बर्फ पड़ी थी। हम उस दिन 18वें राज्य के तौर

पर निकले और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हिमाचल प्रदेश को विशेष केटेगरी स्टेट में रखा जिसमें केंद्र सरकार का 90 प्रतिशत तथा हिमाचल प्रदेश का 10 प्रतिशत शेयर था। वह भी एक सोफ्ट लोन था, उसको अगर किसी भी मुख्य मंत्री ने अदा किया है तो आप रिकार्ड में देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से सौ प्रतिशत ग्रांट मिली है। अब हम पलटी क्यों मार रहे हैं? पलटी इसलिए मार रहे हैं क्योंकि नया कार्यक्रम आ गया है। अब पंचवर्षीय योजनाएं गौण रूप में आ गई है, वार्षिक योजनाएं भी किनारे कर दी गई है। अब जो नीति आयोग बना है और नीति आयोग में जो हिस्सा देते हैं शायद यह उनको भी मालूम नहीं है कि किसको कितना पैसा देना है, यह फैसला पी0एम0ओ0 करता है। दिल्ली से कोई पैकेज लेने की बात आई तो हमारे भोले से मुख्य मंत्री प्रधान मंत्री से मिलें, फाइनैंस मिनिस्टर से मिलें, सर्फेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से भी मिलें और राष्ट्रपति महोदय से भी मिलें। मैं यहां पर यह पूछना चाहूंगा कि क्या उनकी सोच में हिमाचल प्रदेश के बारे में कोई परिवर्तन आया? केवल यह कह देना कि जी0एस0टी0 और सी0एस0टी0 की वजह से हिमाचल प्रदेश को ज्यादा पैसा आया (---व्यवधान---) अध्यक्ष महोदय, अभी तो गला भी नहीं खुला है।

**अध्यक्ष :** आपको बोलते हुए 15 मिनट हो गये हैं।

**श्री राम लाल ठाकुर :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे थोड़ा और टाइम दे दीजिए।

**13.3.2018/1240/av/yk/2**

आज हिमाचल प्रदेश और इस भारतवर्ष के अन्दर जिस प्रकार से हो रहा है, आप कह रहे हैं कि हमें केंद्र सरकार से कुछ मिलेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि लोक सभा के चुनाव की घोषणा फरवरी, 2019 में होगी। मान लो, अगर फरवरी महीने में घोषणा होगी तो हमारा प्रदेश तो एक छोटा सा राज्य है और हमारी केवल चार सीटें हैं। देश में कई दूसरे जो बड़े-बड़े राज्य हैं जिनकी 40-40, 50-50 या 60-60 पार्लियामैंट मैम्बर की सीटें हैं उनकी तरफ

ज्यादा देखा जायेगा और हमारी वही हालत हो जायेगी कि *'चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर'*; हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। यहां पर सभी माननीय सदस्यों को जो बजट डॉक्युमैंट दिया गया है उसमें 3786.55 करोड़ रुपये का घाटा दर्शाया गया है। इसमें यह कहा गया है कि साल के अंत तक यह घाटा 7061.52 करोड़ रुपये हो जायेगा। क्या यह चिन्ता का विषय नहीं है, यहां पर पैसा कहां से आयेगा? आप तो कर्ज लेने के विरोधी हैं और आपसे पहले जो मुख्य मंत्री थे वे भी कर्ज लेने के विरोधी थे। उनका कहना था कि प्रदेश को कर्ज में डूबा दिया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि भारतवर्ष में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर फंडिंग एजैंसियों से पैसा नहीं लिया गया और प्रदेश का विकास नहीं हुआ है। आज की तारीख में आपका जो यहां पर डॉक्युमैंट पेश किया गया है उस डॉक्युमैंट के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे पास केवल 39.56 करोड़ रुपये बचते हैं जिसमें विकास सहित हमें लोगों की इच्छाओं के मुताबिक भी काम करना है।

**13.3.2018/1245/TCV/YK-1**

## श्री राम लाल ठाकुर ...... जारी

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये चिन्ता का विषय हैं और ये आंकड़े बताते हैं। ये जो बजट प्रस्तुत किया गया है, इसको अगर लागू करना है, आज एक ओर ऋण का विरोध हो रहा है और दूसरी तरफ मैं यह कहना चाहूंगा कि 26.64 प्रतिशत् जो हमारी प्राप्तियां/खर्चा है, उसके लिए कर्ज़ लेना पड़ेगा। हमें कर्ज़ लेना पड़ेगा, यदि हमें हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाना है। वह भी फार्मूले के मुताबिक, ये नहीं कि आप जहां कहीं से पैसा ले लो। भारत सरकार ने हर राज्य के लिए जो फार्मूला तय किया है, उसमें प्रदेश का मुख्य मंत्री लोगों से किए वायदों को पूरा करने के लिए ऋण ले सकता है। अध्यक्ष महोदय, ये सारी बातें करनी पड़ेगी अगर आपने नौज़वानों का ध्यान रखना है।

**अध्यक्षः** माननीय सदस्य, कृपया वाईंडअप कीजिए।

**श्री राम लाल ठाकुरः** अध्यक्ष महोदय, मैं 5 मिनट में वाईंड़अप कर रहा हूं। मैं एक बात और करना चाहूंगा। यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में स्पोर्ट्स पॉलिसिज़ का जिक्र किया है। अध्यक्ष महोदय, क्या इस साल नये कोचिज़ लगाने का कहीं पर कोई जिक्र हुआ है। पिछले वर्षों में पूर्व मुख्य मंत्री, राजा वीरभद्र सिंह जी ने 50 कोचिज़ हिमाचल प्रदेश में लगाने के लिए बजट में प्रावधान किया था। मैं माननीय मुख्य मंत्री और मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया ये जो हमारे आर0एण्ड0पी0 रूल्ज़ हैं, इनको बदलने की आवश्यकता है। इसके बारे में मैंने पीछे बात की थी, अध्यक्ष महोदय, मैं किसी अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि ये बड़े पुराने रूल्ज़ हैं। यहां पर 2 साल का एन0आई0एस0 किया हुआ व्यक्ति भी वहीं पर और उसके जगह पर 4 हफ्ते का कन्डेंस कोर्स करके आये हुए व्यक्ति को कोचिज़ लगा दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मुख्य मंत्री और मंत्री जी से निवेदन है, कृपया जो आर0एण्ड0पी0 रूल्ज़ हैं, उनमें परिवर्तन करें ताकि सही तरह से जिन्होंने 2 साल का एन0आई0एस0 का कोर्स कर रखा है, उनको स्थान मिल सकें।

**13.3.2018/1245/TCV/YK-2**

अध्यक्ष महोदय, मैं 1-2 बातें और करना चाहूंगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अली खड्ड है। वह अली खड्ड 15-20 फुट नीचे चली गई है। मैं यह भी नहीं कहूंगा कि उसके लिए कौन दोषी है? चन्द चांदी के टुकड़ों के लिए हम सब बेईमान हो जाते हैं। अगर जंगल कटते हैं, तो चंद चांदी के टुकड़ों के लिए, राजनैतिक तौर पर नहीं, राजनैतिक दीवारों से हट करके, लोग इक्ट्ठे होकर इस काम को करते हैं। मेरा निवेदन है कि जो अली खड्ड है, आज लोगों के क्यार ऊपर रह गये हैं और खड्ड 15 फुट नीचे चली गई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से इसके तटीयकरण करने के लिए आग्रह करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, फोरलेन बन रही है, लेकिन उसका काम रूका हुआ है। वहां के लोग 10 सालों से मिट्टी खा रहे हैं, कम्पनियां भाग गई हैं। मेरा माननीय मुख्य मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि वे नेशनल हाईवे अथोरिटीज़ को इस बारे में निर्देश जारी

करें। क्या कारण है कि गोविन्द सागर पर बनने वाला पुल पिछले डेढ़ साल से रूका हुआ है। जितनी भी सुरंगें बननी है, उन सबका काम रूका हुआ है। लोगों को पैमेंट नहीं हुई है। ये किसकी जिम्मेदारी है? हम कह रहे हैं कि नेशनल हाईवेज़ आ जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ये चुनाव के लिए घोषणा थी। बिलासपुर का जो एम्ज़ है, चुनाव से कुछ दिन पहले भारत वर्ष के प्रधान मंत्री आये और बिलासपुर में हमारा जो इंडोर स्टेडियम है, वहां पर उसकी आधारशिला रखी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं रिकार्ड में लाना चाहता हूं, जितने भी नेशनल इन्स्टीच्यूशन्ज़, जिस भी प्रदेश को मिलते हैं, हिमाचल प्रदेश को भी मिला और उस समय मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंह जी थे। बिलासपुर के लोग आये कि आपने चम्बा,मण्डी,कांगड़ा और सिरमौर को इंस्टीच्यूशन्ज़ दे दिए।

13-03-2018/1250/NS/AG/1

श्री राम लाल ठाकुर-------जारी

हमारा क्या कसूर है? अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने फैसला करना था कि एम्ज़ कहां पर खुलेगा? हिमाचल प्रदेश की केबिनेट ने फ़ैसला किया और ज़मीन भी दी। प्रदेश सरकार के फ़ैसला को लेकर कुछ लोग आज भी विरोध कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस बारे में मैंम्बर ऑफ पार्लियामैंट का बयान भी आया था।

**अध्यक्षः** माननीय सदस्य कृपया वाईंड अप करें।

**Shri Ram Lal Thakur:** Sir, I am winding up. मुझे मैम्बर पार्लियामैंट के बयान से बड़ा दुःख हुआ है। वे कह रहे हैं कि कोई भी राशि अभी एम्ज़ के लिए नहीं आई है। यह मुझे मालूम नहीं है। इसके बारे में तो माननीय मुख्य मंत्री और माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ही बता सकते हैं कि क्या कारण हैं? आपके ही दायें बाजू को मालूम नहीं है कि बायां बाजू क्या कह रहा है? आपके मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट इस प्रकार की अनाउंसमैंट कर रहे हैं।

**अध्यक्षः** माननीय सदस्य 25 मिनट हो रहे हैं और आप कृपया वाईंड अप कीजिए।

**श्री राम लाल ठाकुरः** मैं दो मिनट में वाईंड अप कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे एक निवेदन गौ सदन के बारे में है। हाई कोर्ट ने कह दिया है कि गौ सदन प्रदेश की हर

पंचायत में बनेंगे। अगर किसी भी पंचायत में पशु ऐसे ही घूमता हुए पकड़े गये तो पंचायत प्रधान के ऊपर एक्शन होगा। लेकिन यह एक्शन हाई कोर्ट ने नहीं करना है। कोई भी प्रधान पशुओं को ले करके नहीं आता है, इन पशुओं को लोग छोड़ देते हैं। अगर आप छोटे गौ सदन खोलेंगे तो इन गऊओं की रक्षा नहीं हो सकती है। हर जिले में 300-400 बीघा जगह पर कलस्टर बनाये जायें ताकि लोगों ने जितने भी पशु छोड़े हैं, उनको एक जगह के अंदर इक्ट्ठा किया जा सके, इसमें चाहे फिर मंदिर ट्रस्ट का पैसा लगे। लेकिन मंदिर ट्रस्ट का पैसा सही जगह पर लगना चाहिए। मेरे हिसाब से 15 प्रतिशत राशि कम नहीं है। आपने बोतल के ऊपर भी सैस लगाया है। मैं इसके लिए कहना चाहता हूं कि चाहे और ज्यादा सैस लग जाये लेकिन ये गौ सदन चलने चाहिए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इन सारी बातों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। अंत में, मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने बज़ट में आनन्दपुर साहिब से नैना देवी के लिए रोपवे की बात कही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ ही अपनी वाणी को विश्राम दूंगा।

13-03-2018/1250/NS/AG/2

पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकार में समझौता हुआ था कि नैना देवी को आनन्दपुर साहिब से रोपवे बनेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी, क्या आपको मालूम है कि आनन्दपुर साहिब टोबा से कितना दूर है? टोबा संगवाणा जहां से बिलासपुर शुरू होता है वहां से 176 मीटर दूर पंजाब के साथ एग्रीमैंट हुआ है। वहां पर लोगों ने जमीनें खरीद ली हैं क्योंकि वहां से रोप वे आना है। माननीय अध्यक्ष जी, इस रोप वे में पंजाब सरकार का पूरा दख़ल होगा। We will be on receiving end, Sir. जो भी आदमी वहां से आयेगा हम उसका नैना देवी में स्वागत करेंगे। मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या 176 मीटर पंजाब के अन्दर रोपवे लगाने से हिमाचल प्रदेश के हित की रक्षा होगी? मेरा आपसे यह निवेदन है कि 176 मीटर से इस तरफ को टोबा बिलासपुर में पड़ता है। इसके लिए जिस व्यक्ति को ये निविदायें दी गई थी या काम दिया गया था, वह भाग गया था। पर्यटन विभाग की तरफ से तीन या चार बार निविदा के लिए अखबार में दिया गया लेकिन इसके लिए कोई पार्टी आगे नहीं आई। मेरा आपसे निवेदन है कि आप या तो इसे आनन्दपुर साहिब से बनाओ या फिर इसे छोड़कर बनाया जाये। यह रोपवे आनन्दपुर साहिब से नहीं है। यह रोपवे पंजाब में 176 मीटर कोलां वाले टोबे से आगे प्रस्तावित है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसकी तरफ ध्यान दें और

जो हमारा बार्डर एरिया है, वहां पर पुलिस बल की जरूरत है, इस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने यहां पर मुझे अपने विचार रखने का सौभाग्य दिया है। अब मैं इसका समर्थन करूं या न करूं, यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं या माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी के ऊपर छोड़ता हूं। जो मैंने कहा है वह कटु सत्य है और इसको बर्दाश्त करने की कृपा करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**अध्यक्षः** अगले सदस्य माननीय चौधरी सुख राम जी चर्चा में भाग लेंगे।

13.03.2018/1255/RKS/AG-1

**श्री सुख रामः** आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी ने जो 9 फरवरी, 2018 को माननीय सदन में बज़ट प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। 20 दिसम्बर, 2012 को प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। बहुत ही अनुभवी मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के रूप में हिमाचल प्रदेश को मिला। हिमाचल प्रदेश के लोगों को उस सरकार से बड़ी आशाएं थीं। उस समय की सरकार ने जो हिमाचल प्रदेश के लिए विकास कार्य शुरू किए, उसमें मैं भर्तियों पर थोड़ी-सी चर्चा करना चाहता हूं। जब पूर्व में कांग्रेस सरकार थी तो इन्होंने पी.टी. ए. में भर्ती करके बैक डोर एंट्री करने का प्रयास किया। आज पी.टी.ए. के लोग हर मुख्य मंत्री के द्वार में खड़े होते हैं कि हमें रेगुलर कर दो। हमारे लिए कोई पॉलिसी बना दो। इनको सुबोर्डिनेट सर्विस सलैक्शन बोर्ड पर विश्वास नहीं रहा। इन्होंने सुबोर्डिनेट सर्विस सलैक्शन बोर्ड की तर्ज़ पर एस.एम.सी. के माध्यम से भर्तियां करना शुरू कर दी। जिला सिरमौर में पिछले 5 सालों में 455 अध्यापकों के पद एस.एम.सी. के द्वारा भरे गए। पी.जी.टी., 121, डी.पी., 17, एल.टी., 27, ओ.टी.,77, डी.एम., 44 टी.जी.टी.(आट्र्स), 89, नॉन मैडिकल, 32 और मैडिकल में 28 पद भरे गए। मैं एस.एम.सी. की भर्ती का एक उदाहरण देना चाहता हूं। किस तरह से इन्होंने हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के साथ बेईमानी की है। किस तरह से बैक डोर एंट्री करने का प्रयास किया गया। एस.एम.सी. में तीन का पैनल होता है। जिसमें एस.डी.एम, प्रिंसिपल और उस

विषय का एक्सपर्ट होता है, जिस विषय के टीचर का इंटरव्यू वहां लिया जाता है। मैं रेणुका विधान सभा क्षेत्र का एक उदाहरण देना चाहूंगा। वहां पर एक एल.टी. का पद भरा गया। जिसकी कॉपी मेरे पास है और जिसे मैंने विधान सभा पटल पर भी 'ले' किया है। पारूल पुंडीर एक लड़की थी, जिसको 10 में से 9.85 नम्बर दिए गए। एक सन्तोष कुमारी, एल.टी. है जिसे 10 में से 0.83 नम्बर दिए गए। यानी 10 में से प्वाईंट 83 नम्बर दिए गए। इस एल.टी. के पद को भरने के लिए एक को 10 में 0.83 नम्बर दिए गए और जिसे भर्ती करना था उसे 10 में से 9.85 नम्बर दिए गए। जितने भी एस.एम.सी. अध्यापक भरे गए, उनमें से कम-से-कम 250 ऐसे हैं जिनको भरने के लिए, जो दूसरे नम्बर में स्टूडैंट था, उसे फेल किया

13.03.2018/1255/RKS/AG-2

गया। उसे 10 में से 3 से भी कम नम्बर दिए गए। इसका सारा डाटा मेरे पास है। ऐसा एक केस नहीं है। रेणुका विधान सभा क्षेत्र में ऐसे 40 केस हैं। 40 केस रेणुका विधान सभा क्षेत्र के हैं जिन्हें 10 में से 3 से कम नम्बर दिए गए। मैं माननीय मुख्य जी से कहना चाहूंगा कि इसका रिकॉर्ड मंगवाया जाए। दूध-का-दूध और पानी-का-पानी हो जाएगा। (...व्यवधान...) ।

**अध्यक्षः** माननीय सदस्य, श्री विनय कुमार जी आपको बोलने के लिए समय दिया जाएगा।

**श्री सुख रामः** अध्यक्ष जी, मैं तथ्यों पर आधारित बोल रहा हूं। आर.टी.आई. से जो रिपोर्ट मुझे मिली है, मैंने उस कागज को 'ले' किया है। प्वाईंट 83 नम्बर उसको दिए गए। मैं इस माननीय सदन में यह बात बोल रहा हूं। अगर यह बात झूठ हुई तो आप मेरे ऊपर केस कर सकते हैं। सारी बैक डोर एंट्री भरने का ठेका कांग्रेस की सरकारों ने ले रखा है। पी.टी.ए. के आधार पर भर्ती कर लो और बाद में नीति बना लो। एस.एम.सी. के माध्यम से भर्ती कर लो और बाद में नीति बना लो। फिर हिमाचल प्रदेश स्टाफ सलैक्शन कमीशन क्यों रखा है? मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहता हूं, जिसका रिकॉर्ड/कागज़ मेरे हाथ में है।

13.03.2018/1300/बी0एस0/डी0सी0-1

**श्री सुख राम .........जारी**

पौंटा में बी0डी0ओ0 कार्यालय में कॉंट्रेक्ट पर ड्राइवर की पोस्ट भरी गई। जो लड़का एक नम्बर पर था उसे डेढ़ नम्बर 1.5 दिया गया, और जो दूसरे नम्बर का था जिसे इन्होंने भर्ती करवाना था उसे 9.5 नम्बर दिए गए। जिस लड़के को भर्ती से रोका गया, उसके 74.7 नम्बर बने है और जो भर्ती किया गया उसके नम्बर 74.8 बने हैं। एक दूसरे नम्बर का लड़का उसको भी 2 नम्बर दिए गए। इस प्रकार से आपने पहले नम्बर वालो को रोका। ये सैंकड़ो उदाहरण मैं आपको जिला सिरमौर के दे सकता हूं। मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि जब हमने सर्विस स्लेक्शन बोर्ड बनाया है, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया है, उसके माध्यम से भर्तियां क्यों नहीं की गई? क्यों बैक डोर एंट्री से आप मोका देते हो? इससे हिमाचल प्रदेश का जो नौजवान था, वह उस सरकार से दुखी हो गया । इन्होंने आपने घोषणा पत्र में एक और बात कही थी कि हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देंगे। कितना विरोधाभास उस बेरोजगारी भत्ते के नाम पर हुआ। कांगड़ा से स्टेटमैंट आती थी, अगले सत्र में अगले बजट में हम बेरोजगारी भत्ता देने जा रहे हैं और उस समय के मुख्यमंत्री कहते थे, हमने कोई घोषणापत्र नहीं बनया। हमारी कोई कमिटमेंट नहीं है, बेरोजगारी भत्ता देना है या नहीं देना है यह हमारे प्रदेशाध्यक्ष जानें । जब पांच साल पहले इन्होंने सरकार बनाई तो हिमाचल प्रदेश के लाखों बेरोजगारों के साथ धोखा किया। जब जाने की बारी आई तो 22 सौ बेरोजगारों को बेराजगारी भत्ता दे दिया। हिमाचल प्रदेश की जो सर्विस चयन समिति है उस पर भी विश्वास नहीं रखती। यह अपने नियम बना कर बैक डोर एन्ट्री से भर्तियां करने का प्रयास करती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों पर भी विश्वास नहीं है। जब एक व्यक्ति रिटायर हो गया तो उसे दोबारा भर्ती करने की क्या जरूरत है? एक्सटेंशन देने की क्या आवश्यकता है? उससे हिमाचल प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी, हिमाचल

प्रदेश के अधिकारियों में काम करने की क्षमता कम होती है। एक छोटा सा अधिकारी मैं बड़े अधिकारी की बात नहीं करना चाहता। एक सेवादार भी

13.03.2018/1300/बी0एस0/डी0सी0-2

होता है वह भी चाहता है कि मैं लिपिक बन जाऊं। एक अधिकारी जो इन्तजार करता है कि मेरे से वरिष्ठ अधिकारी जब रिटायर होगा तब मेरा नम्बर आएगा। परंतु में उसे पता नहीं था कि पूर्व सरकार उससे वरिष्ठ अधिकारी को दो वर्ष की एक्सटेंशन दे दी जाएगी और उसका कभी नम्बर नहीं आएगा। उस अधिकारी पर क्या गुजरती थी जिसका नम्बर, नम्बर एक पर होता था। उससे नम्बर दो वाला भी परेशान होता था। इस कारण अधिकारियां और बेरोजगारों में इतनी निराशा का वातावरण बन गया था कि वह कांग्रेस की सरकार को देखना तक नहीं चाहते थे। इसलिए 09 नवम्बर, 2017 को जब यह चुनाव हुआ और 18 दिसम्बर, 2017 को जब चुनाव परिणाम निकला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के आम नागरिक ने आपसे से तंग हो करके बनाई है। मैं आदरणीय जय राम ठाकुर जी को बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। पूर्व की सरकार बहुत सी बाते करती हैं। हम इस बात को भूला नहीं सकते, हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में गुड़िया जैसा कांड होता है, पूरे भारतवर्ष में हिमाचल प्रदेश की इमेज खराब होती है। हिमाचल प्रदेश शांत प्रदेश है, आज हमारे पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारी सलाखों के पीछे हैं। इससे ज्यादा कानून व्यवस्था के बारे इस विधान सभा में बोलने की आवश्यकता नहीं है। यह कहा जाता था, हमारे तो बहुत अनुभवी मुख्य मंत्री इस प्रदेश में बने हैं, इस बार नारा भी लगा था "सातवीं बार" लोगों ने उसको झूठला दिया। क्या यह सच नहीं है, जितना ऋण हिमाचल प्रदेश ने लिया उसका साढ़े 40 प्रतिशत ऋण पिछले पांच सालो में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लिया है? क्योंकि हमारा जो पिछला ऋण था वह 18787 करोड़ रुपये था और अब बढ़ कर 46385 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। 18787 करोड़ रुपये का ऋण 40 प्रतिशत बनता है जो पिछली सरकार ने लिया है। जब से हिमाचल प्रदेश बना है तब से 60 प्रतिशत ऋण लिया गया और पिछले 5 सालों में 40 प्रतिशत ऋण लिया गया। उसमें 35 करोड़ रुपये हमारी सरकार को ब्याज के रूप में अदा करना पड़ेगा।

श्री डी.टी. द्वारा जारी....

13.3.2018/1305/DT/DC-1

श्री सुख राम ...जारी

इसलिए जो ऋणों पर अधारित सरकार थी मैं इस माननीय सदन के माध्यम से यह पुछना चाहता हूं कि आपने हिमाचल प्रदेश में कौन से संसाधन पिछले 5 साल में पैदा कर दिए जिससे हिमाचल प्रदेश की इनकम बढ़ी हो। इन्होंने कोई संसाधन पैदा नहीं किया । इसलिए जो पिछली हिमाचल प्रदेश की सरकार थी वह माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दया दृष्टि पर चली थी। क्या यह सच नहीं है कि हमें जो 90:10 में विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, वह बन्द हो गया था। हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 28 अक्तूबर, 2015 को हिमाचल प्रदेश को 90:10 के अनुपात में पैसा देने का निर्णय लिया। सर्वशिक्षा अभियान में 65 प्रतिशत,राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय अनुदान में 75 प्रतिशत, नैशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोगाम में 50 प्रतिशत, विशेष पोषण कार्यक्रम में 50 प्रतिशत दिया गया। यह पैसा यूपीए कि सरकार के समय इस प्रतिशत के हिसाब से इस सरकार को मिलता था। लेकिन हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेद्र मोदी जी ने इस को 90:10 में देने का निर्णय लिया है। यह कोई झूठी बात नहीं है। मैं सच्ची बात आपके सामने रख रहा हूं। आप सुनने का मादा रखिए। प्रदेश के विकास को गति देने के लिए हमारे देश के प्रधान मंत्री ने 69 नैशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश को दिए। 3 मैडिकल कॉलेज चम्बा, नाहन, हमीरपुर में दिए। आई.आई.एम. संस्थान जिला सिरमौर, धोला कुआं में दिया। वर्ष 2016 में 2110 करोड़ का बजट धर्मशाला में समार्ट सीटी के लिए दिया तथा जून 2017 में समार्ट सीटी शिमला के लिए 2905 करोड़ रूपये दिए। जिला बिलासपुर कोठीपुरा में आखिल भारतीय अनुसंधान संस्थान 1 हजार 351 करोड़ रुपये दिए। प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत लाखों घर हिमाचल प्रदेश के लोगों को बनाने के लिए सीधा पैसा हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने दिया। प्रधान मंत्री ग्रामीण स्वस्थ्य योजना के तहत 12 हजार के शौचालय की सब्सिडी कम से कम हिमाचल प्रदेश के लाखों घरों को प्रधान मंत्री जी ने दी है। आज अगर हिमाचल प्रदेश को स्वच्छ हिमाचल

प्रदेश का दर्जा मिला है तो इसके पिछे हमारे देश के प्रधान मंत्री की सोच है। प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना में 338 करोड़ रूपये दिया गया है। मैं आप के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने गैर योजना से मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम बनाया और वहां पर 10 स्कूलों की मांग कर दी।

13.3.2018/1305/DT/DC-2

मुख्यमंत्री जी ने बोला 10 तो कम है 20 ले लो। पटवार र्सकल 2 मांगे उन्होंने चार दिए। पटवार र्सकल क्या सब-तहसील ले लो। सब-तहसील की जगाह एस0डी0एम0 कार्यालय ले लो। लेकिन बजट का कोई प्रोविजन नहीं किया। हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा स्कूल खोल दिए हैं। लोगो की डिमांड नहीं है परन्तु आप स्कूल खोल रहे हैं। वहां पर बच्चे नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश का एजुकेश्न स्तर इतने नीचे क्यों गिर गया है? यह माननीय सदन में चर्चा का विषय है। आज एक रिक्शा चालक जो रिक्शा चलाता है, एक मजदूर, खिचड़ी बनाने वाली महिला भी चाहती है कि मैं अपने बच्चों को निजी स्कूल में भेजूं। यह चिंता का विषय है। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहता है। उसके पीछे कोई-न-कोई कारण तो है। आज क्या हो गया है? जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनमें कोई नीति नहीं बनाई गई। जहां 60 बच्चे हैं और पांच क्लासें हैं, वहां पर दो टीचर रख दिए हैं। एक टीचर डाक बनाने के लिए व्यस्त है और आपके पास एक ही टीचर बचा परन्तु वह 5 क्लासों को कैसे पढ़ायेगा?

**13.03.2018/1310/SLS-HK-1**

**श्री सुख राम... जारी**

पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवीं क्लास वाले सब अगर वहीं बैठेंगे तो क्या इस तरह शिक्षा का स्तर बढ़ेगा? आपने तो स्कूल खोलने का ठेका ले लिया था। अगर कमरे बन भी गए तो एक अध्यापक कहां-कहां घूमेगा; क्या वह पांचों कमरों का चक्कर लगाता रहेगा? इसलिए जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, मैं इसके बारे में माननीय शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं कि आप बेशक स्कूलों की संख्या कम करिए। जहां पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्र है वहां के स्कूलों के लिए एक अलग क्राइटेरिया तय कीजिए और वहां कम बच्चों पर भी स्कूल

दीजिए। लेकिन जहां प्लेन क्षेत्र है, जहां केवल आधा किलोमीटर चलना पड़ता है, पिछली सरकार ने वहां के लिए भी नए स्कूल दे दिए जबकि वहां पर अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए अगर आपने शिक्षा का स्तर अच्छा करना है, निजीकरण की ओर अभिभावक बच्चों को न भेजें, इस बात को देखना है तो इसका युक्तिकरण करके कम-से-कम जिस स्कूल में 40 से अधिक बच्चे हैं, वहां आप कम-से-कम 5 अध्यापक उस स्कूल में दीजिए ताकि हर क्लास के अनुसार उन बच्चों को शिक्षा मिले। ऐसा करके ही शिक्षा का स्तर बढ़ सकता है नहीं तो अभी इन स्कलों में बच्चों की जितनी संख्या है, आने वाले दिनों में वह भी कम हो जाएगी।

हम अटल बर्दी योजना की बात करते हैं। अटल बिहारी वाजपेई के नाम पर हमारी पूर्व की सरकार ने साल में बच्चों को 2 बर्दियां देने का निर्णय लिया था। उसमें साथ में सिलाई भत्ता देने का भी निर्णय किया गया था। हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने इस वर्ष पहली, तीसरी, छठी और नौंवी कक्षाओं को स्कूल बैग देने का निर्णय किया है। क्या यह निर्णय स्वागत योग्य नहीं है? एक बैग को 3 सालों तक चलाना है।

मुख्य मंत्री लोक भवन के नाम पर मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र को हम 30 लाख रुपया देंगे। अगर कोई सांसद या एम.एल.ए. भी अपनी सांसद या विधायक निधि से पैसा देना चाहता है तो वह उस राशि में अपनी धनराशि जोड़ सकता है। बाकी भी 2 और लोक भवन बन सकते हैं जिनमें 15 लाख रुपया सरकार देगी और 15 लाख रुपया विधायक दे सकता है। इस तरह विधायकों के लिए विधायक निधि में 1.25 करोड़ रुपया नहीं हुआ; अगर वह 2-2 जगह पैसा दे देंगे तो वह 1.50 करोड़ रुपया बन जाएगा। यह हमारे माननीय मुख्य मंत्री की सोच है।

**13.03.2018/1310/SLS-HK-2**

कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए हमारी सरकार ने बहुत पैसा रखा है। हिमाचल प्रदेश का किसान बहुत कमज़ोर है। हिमाचल प्रदेश में कृषि योग्य ज़मीन बहुत कम है। इस बजट में उनके लिए प्रदेश के मुख्य मंत्री ने बहुत पैसा रखा है। कमांध क्षेत्र के लिए 180 करोड़ रुपया, और 5 सालों के लिए 500 करोड़ रुपये की योजना है। सौर सिंचाई योजना के लिए 200 करोड़ रुपया रखा है ताकि हमारे किसानों को बिजली पर निर्भर न रहना पड़े। ये

हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री ने बहुत अच्छी योजना दी है। बोर वैल निर्माण हेतु 10.00 करोड़ रुपया, प्रधान मंत्री कृषि योजना में 277 करोड़ रुपया और जल से कृषि पर 250 करोड़ रुपया रखा गया है। जहां तक ट्यूब वैल की बात है,जब किसान उसकी बिजली का बिल देता है; पहले ही कहीं फसल नहीं होती, कहीं पानी नहीं लगता, कहीं उसके साथ प्राकृतिक आपदा घट जाती है और किसान को बिजली के बिल जमा करवाने मुश्किल हो जाते हैं। हरियाणा में बिजली फ्री है यानी केवल उन्होंने 25 पैसे प्रति युनिट रखा है। पंजाब में फ्री है। लेकिन पूर्व की सरकार ने यहां पर 50 पैसे प्रति युनिट से बढ़ाकर एक रुपया प्रति युनिट कर दिया था। अब हमारी सरकार ने एक रुपये से घटाकर 75 पैसे किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं। ...(व्यवधान)... समय आने पर हम फ्री भी करेंगे लेकिन आपकी बात भी बतानी पड़ेगी क्योंकि आपने 50 पैसे से एक रुपया प्रति युनिट कर दिया था। आपने तो किसानों के ऊपर बोझ लाद दिया था।

पशु धन के लिए हमने कहा कि देशी गाए खरीद पर हम 50% सब्सिडी देंगे। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि अवारा पशुओं के लिए योजना बननी चाहिए। हमने गौसदन के लिए एक रुपया लीज पर ज़मीन देने की बात कही है। फिर दूध पर भी

एक रुपया प्रति किलो रेट बढ़ाने की बात की गई है। साथ ही, भाड़े पर भी एक रुपया बढ़ाने की बात कही गई है।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट में बहुत-सी बातें हैं। मैं केवल 2 मिनट और अपनी बात कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा।

पंचायत प्रतिनिधियों, नगर निगम और नगर परिषद के सभी जन-प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया गया है।

**13/03/2018/1315/RG/HK/1**

**श्री सुख राम-----जारी**

मिड डे मील कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायक और पार्ट टाईम वाटर कैरियर्ज का मानदेय भी हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने बढ़ाया है। मजदूरों की दिहाड़ी भी बढ़ाई गई है। आपने 150/-रुपये से 210/-रुपये की थी। इस प्रकार से पांच

सालों में इन्होंने सिर्फ 60/-रुपये बढ़ाए थे। लेकिन हमने पहले ही वर्ष में 15/-रुपये बढ़ाकर दिए हैं। अभी तो पहला ही साल है। इनके समय में मात्र 12/-रुपये प्रति वर्ष बनता है। हमने अभी 15/-रुपये बढ़ाए हैं। --(व्यवधान)--इनसे ज्यादा बढ़ांएंगे। इनकी सरकार मजदूर विरोधी सरकार रही है। सब कुछ करेंगे, --(व्यवधान)--आप चिन्ता क्यों करते हैं? अभी तो सिर्फ दो महीने का ही समय हुआ है, पूरे पांच साल बचे हैं। सभी का मानदेय इस बजट में बढ़ाया गया है, लेकिन एक कैटागिरी इसमें छूट गई है। सिलाई अध्यापकों का मानदेय नहीं बढ़ा है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि कम-से-कम उनका मानदेय भी बढ़ाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं औद्योगिक नीति के बारे में कुछ कहकर सिर्फ एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में जो उद्योग लगे हैं। वे परम श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। अगर उस नीति के तहत हिमाचल प्रदेश में करों में छूट न मिलती, तो शायद एक भी उद्योग हिमाचल प्रदेश में नहीं लगता। लेकिन इनकी सरकार ने तो पहले भी इस पैकेज के तीन वर्ष घटा दिए थे। मैं चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा मिलना चाहिए। हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने जो कहा है कि नए उद्योगों को हम साढ़े चार रुपये प्रति यूनिट बिजली देंगे, पांच वर्ष तक उनके ऊपर बिजली का कोई भी शुल्क नहीं लगाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि उद्योगपति 15-20 वर्षों से यहां अपने उद्योग लगाकर रह रहे हैं, लेकिन उनको किराये के मकान में ही रहना पड़ता है। वह हिमाचल प्रदेश में करोड़ों-अरबों रुपयों का निवेश करता है। वह या तो देहरादून या चण्डीगढ़ में जाकर रहेगा। अच्छी अकोमोडेशन उसको हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलती है। बद्दी से वह चण्डीगढ़ के लिए रोज अप-डॉऊन करता है। क्या हम इस तरह की नीति बनाने पर विचार करेंगे कि जब हम उनका उद्योग यहां शामिल करें, तो नगर परिषद या नगर निगम में अगर पांच बिस्वे की जमीन 118 में अनुमति देकर उसको दे दी जाए, तो कम-से-कम वह हिमाचल प्रदेश का वासी तो बनेगा और वह हिमाचल प्रदेश में रहेगा। उसके बच्चे भी यहां रहेंगे और वह ज्यादा विश्वसनीय तौर से हिमाचल प्रदेश

**13/03/2018/1315/RG/HK/2**

में औद्योगिक प्लांट लगाएगा। इस तरह की नीति बननी चाहिए ताकि इस तरह की छूट उसको मिले। इसके अतिरिक्त जो हमारे नए उद्योग हैं, आपने जो छूट इसमें नए उद्योगों

को दी है, कम-से-कम पुराने उद्योगों को भी देनी चाहिए। आज प्रतिस्पर्धा का युग है। पंजाब की औद्योगिक नीति अलग बन गई और हरियाणा भी छूट दे रहा है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में भी उद्योगों को छूट मिलनी चाहिए ताकि हिमाचल प्रदेश के लोगों को अधिक-से-अधिक रोजगार मिले।

अध्यक्ष महोदय, मैं खनन नीति के बारे में एक मिनट बोलना चाहूंगा। यहां खनन नीति की बहुत चर्चा होती है। --(व्यवधान)--आज हरियाणा में जितने खनन से पैसे कमाए जाते हैं वह उनकी आर्थिक आधार का कारण बन गया है। आप यमुना पर देख लें, कम-से-कम 2000 स्टोन क्रशर्ज हरियाणा सरकार ने लगाए हैं। आप खनन नीति की एक योजना बनाइए। वैज्ञानिक तरीके से खनन हो, सरकारी जमीन के पट्टे बनाइए और हिमाचल प्रदेश के लोगों को नीलामी पर दीजिए ताकि वे वहां स्टोन क्रशर्ज लगाएं। दिक्कत कहां आ रही है? उससे राजस्व भी प्राप्त होगा और हिमाचल प्रदेश को टैक्स भी मिलेगा। दूसरी बात यह है कि यह चोरी भी बचेगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि ठोस खनन नीति बनाने की आवश्यकता है। हम सारे लोग खनन वालों को यदि चोर-चोर कहना शुरू कर देंगे, तो इससे बहुत गलत संदेश हिमाचल प्रदेश में जाता है। बल्कि यह हमारे प्रदेश की कमाई का साधन होना चाहिए। हमारे प्रदेश में इतनी नदियां हैं। यहां 66.5% जंगल हैं। हमारे पास थोड़ी जमीन है। खड्डों पर आधरित हमारा प्रदेश है। इसलिए सारा मलबा निचले प्रदेशों में चला जाता है और वे खनन करके उससे पैसा कमाते हैं। हमारी जमीन बहकर नीचे चली जाती है। हमारे यहां खनन करने पर आप इतनी पाबन्दी लगाते हैं और छोटी-छोटी बातों में टीका-टिप्पणी करते हैं। इसलिए मेरा माननीय उद्योग मंत्री जी से निवेदन है कि इसका सरलीकरण कीजिए और इस बारे में एक ठोस नीति बनाइए। यह हिमाचल प्रदेश का एक साधन बनना चाहिए ताकि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। जैसा मैंने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश में 66.5% वन हैं। --(व्यवधान)--हम लकड़ी काट नहीं सकते। एक मिनट मैं अपनी बात समाप्त करुंगा।

**13/03/2018/1320/MS/DC/1**

**श्री सुख राम जारी-----**

66.50 प्रतिशत जमीन हमारी वन भूमि है। इसलिए इस वन नीति को कारगर बनाने की आवश्यकता है। हमारे पास 66.50 प्रतिशत फॉरेस्ट है बाकी नदी-नालों में हमारी जमीन चली जाती है तो किसानों के पास कितनी जमीन बची? आप महिला-मण्डलों, नवयुवक मण्डलों और गांवों की वन समितियां बनाकर उनकी सांझेदारी सुनिश्चित करके फॉरेस्ट में कोई फलदार पौधे लगाओ या कोई और काम शुरू करो ताकि लोगों की भागीदारी उसमें सुनिश्चित हो और उससे लोगों की आमदनी हो यानी उनकी आमदनी का वह साधन बने। तो इस तरह की योजना बनाकर आप वन नीति बनाइए ताकि हिमाचल प्रदेश के लोगों को उसका लाभ मिल सके।

**अध्यक्षः** माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए।

**श्री सुख रामः** अध्यक्ष जी, प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने जो अपना पहला बजट प्रस्तुत किया है, देखिए, इस प्रदेश में सीमित साधन हैं और उसके बावजूद भी इन्होंने बिना कर के बजट प्रस्तुत किया है। किसी भी प्रकार का कर इन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों के ऊपर नहीं लगाया है। उनका यह पहला बजट है जो बिल्कुल पारदर्शी बजट है। अभी हमारे मित्रों को इस बजट में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन एक साल के बाद सब-कुछ दिखाई देगा और ये इस बजट की प्रशंसा भी करेंगे। मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**अध्यक्षः अब इस मान्य सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए 2.30 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।**

**13.03.2018/1430/जेके/एजी/1**

**सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत अपराह्न 2.30 बजे पुनः आरम्भ हुई।**

**अध्यक्षः** इससे पहले कि अगले सदस्य को मैं चर्चा में भाग लेने के लिए पुकारूं, आज हमारे पास Officials of National Assembly of Afghanistan के अत्यन्त महत्वपूर्ण मेहमान गैलरी में विराज़मान हैं । इनके ग्रुप लीडर Mr. Jan Ali Wafa हैं। यह लगभग 35 लोगों

का ग्रुप है जो हिमाचल प्रदेश की विधान सभा को देखने, हमारी कार्य प्रणाली को देखने के लिए और विशेष तौर पर ई-विधान प्रणाली को देखने के लिए आए हैं। इनका जो लोअर हाउस है, जैसा मुझे बताया है उसे Wolesi Jirga कहते हैं। अफ़ग़ानिस्तान के लोअर हाउस से ये लोग पधारे हैं। हम इनका हार्दिक अभिनन्दन करते हैं, स्वागत करते हैं। अब इस चर्चा में माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी भाग लेंगे।

**13.03.2018/1435/SS-AG/1**

**श्री जगत सिंह नेगीः** माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2018-19 का इस माननीय सदन में पेश किया है, मैं उस पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने बोलने के लिए समय दिया, आपका धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं इनके प्रथम बजट के लिए बधाई देता हूं। इसके अलावा इस बजट में कुछ विशेष नहीं है। यह इनका पहला बजट था। इसमें इन्होंने बहुत समय भी लिया। इसमें मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगाः-

***"बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का,***
***जो चीरा तो इक कतरा खून तक न निकला।"***

**अध्यक्षः** शेरों-शायरी काफी जोर से हो गई है।

**श्री जगत सिंह नेगीः** नई सरकार आने के बाद हिमाचल की जनता को बहुत उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, इनके दृष्टिपत्र ने और जो ये लगातार केन्द्र सरकार का नाम लेकर यहां पर सत्ता परिवर्तन की बात की, वे सारी आशाएं इस बजट में धराशायी हो गईं। कुछ भी इसमें नया नहीं है। कर्ज़ का विरोध करने वाले लोग आज 2 महीने में 2200 करोड़ का कर्ज़ ले चुके हैं। जैसे मुझ से पूर्व यहां पर हमारे दल के नेता ने कहा कि साल के अंत में ये रिकॉर्ड तोड़ कर्ज़ा लेने जा रहे हैं। एक वित्तीय मिस-मैनेजमैंट की जो बात करते थे, आप उससे उभर नहीं पाए हैं। आप नया क्या दे पा रहे हैं? आप खुद ही उलझे हुए हैं आपको भी समझ नहीं है। जहां तक आपने यहां पर युवाओं को अपने साथ लिया, आपको याद है कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और राजा वीरभद्र सिंह जी हमारे माननीय

मुख्य मंत्री थे तो इन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया था। पूरे देश में पहली बार हुआ था कि युवाओं को, जोकि बेरोजगार हैं जिनको सरकारी नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता देने की शुरूआत की थी। 1500 रुपये एक सम्मानजनक राशि उसके लिए तैयार की गई थी। आप कहते हैं कि 21000 युवाओं को उसका फायदा भी हुआ। क्या 21000 हजार युवा कम थे? आपने इलैक्शन कमिशन के साथ मैच फिक्सिंग करके चार महीने पहले इलैक्शन करवा दिए। चार महीने पहले आपने हमें काम करने से रोक दिया। डेढ़ महीने से

**13.03.2018/1435/SS-AG/2**

ज्यादा समय आपने इलैक्शन रिजल्ट निकालने में लगवा दिया। यह कहिए कि आपने कम-से-कम छः महीने हमारी सरकार के काम को रोक दिया। इतना बड़ा अन्याय आपके केन्द्र में बैठे आकाओं ने ऐसा काम करके हिमाचल प्रदेश के लोगों को बहुत पीछे धकेला है। अब इस बजट के अंदर हम बड़ी बारीकी से देख रहे थे और माननीय मुख्य मंत्री जी को सुन भी रहे थे कि कब बेरोजगार युवाओं के बारे में कहेंगे। एक भी शब्द युवाओं को सरकारी रोजगार देने के बारे में इस बजट में नहीं है और जो 1500 रुपये एक सम्मानजनक राशि बेरोजगार को देने का प्रावधान हमने किया था आपने उसका भी कोई ज़िक्र नहीं किया है। उसके लिए एक पैसा बजट में नहीं रखा है। आपके अंदर यह कहने की हिम्मत नहीं थी कि हमने यह स्कीम खत्म कर दी है परन्तु आपने चुपचाप से इस स्कीम को खत्म कर दिया है क्योंकि एक पैसा बजट में नहीं है। जब हमारी सरकार सत्ता में थी तो उस समय माननीय मुख्य मंत्री, राजा वीरभद्र सिंह जी ने 150 करोड़ रुपये के प्रावधान से इस बेरोजगारी भत्ते को शुरू किया था। आपके ऊपर एक गम्भीर आरोप है कि आपने हिमाचल के युवा-युवाओं से बहुत बड़ा धोखा किया है। सरकारी नौकरियां नहीं हैं। आप कहते हैं कि आपने एक नई स्कीम लाई है। आप जिस नई स्कीम की बात कर रहे हैं यह स्कीम पहले भी थी। यह प्रधान मंत्री बेरोजगार योजना के तहत भी था। उस समय लोन दिया जाता था। उस समय इंट्रस्ट सबसिडी दी जाती थी और आपने बजट कितना रखा है? हिमाचल में अगर 30 लाख रुपया लोन एक को दे पायेंगे तो उससे मेरे ख्याल में हिमाचल के 100 नौजवानों का स्व-रोजगार का काम होने वाला नहीं है। इतना बड़ा धोखा आपने हिमाचल के युवाओं से किया

है। इसके लिए हिमाचल के युवा आपको बख्शने वाले नहीं है। समय आपका भी आयेगा, आपको भी जवाब देना पड़ेगा, आप बड़ी-बड़ी बातें कहने में, बातों को घुमा-फिराकर कहने में, जुमलेबाजी में आपका मुकाबला नहीं है। झूठ बोलने में भी आपका मुकाबला नहीं है। दोबारा कोई क्रिकेट की तरह वर्ल्ड कप का टूर्नामैंट करवाया जाए।

**13.03.2018/1440/केएस/डीसी/1**

**श्री जगत सिंह नेगी जारी----**

झूठ बोलने वालों का कोई टूर्नामैंट करवाया जाए और हिन्दुस्तान का नेतृत्व बी0जे0पी0 को दिया जाए तो सौ प्रतिशत हम ट्रॉफी जीत जाएंगें। झूठ बोलने की ट्रॉफी हम जीतकर आएंगें। आप लोगों को गौ-वंश की बहुत चिन्ता है। आदमी की चिन्ता नहीं है, बागवानों की चिन्ता नहीं है। कृषि भूमि को बंदरों व आवारा पशुओं से जो नुकसान हो रहा है उसकी चिन्ता नहीं है। 17 करोड़ रुपया आपने गौ- वंश के लिए रखा है। आपने गायों का चारा खाने का इन्तज़ाम कर लिया है। मंदिरों का पैसा भी आपने गाय को देने का इन्तज़ाम किया है और शराब का पैसा भी आप गाय को दिलाने की सोच रहे हैं । आपकी पार्टी का नाम तो भारतीय जनता पार्टी की बजाय भारतीय गौ-वंश पार्टी रखना चाहिए क्योंकि आपको गायों की चिन्ता है। आदमी की चिन्ता नहीं है। (व्यवधान) आप लोग बैठे-बैठे हमें नहीं रोक सकते। यह मेरा बोलने का अधिकार है और आप लोग मेरे बोलने के अधिकार को नहीं छीन सकते। आप जब मनचाहा बोलना चाहते हैं तो मनचाहा सुनने की शक्ति भी रखनी चाहिए। आज देखने में आ रहा है कि हिन्दुस्तान में आज जो भी आवाज आपके खिलाफ उठती है, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। टी.वी. में भी आपके प्रवक्ता इसी प्रकार चिल्लाते हैं जिस तरह से आप चिल्ला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की विधान सभा की बहुत गरिमा है। आप उस गरिमा को खत्म मत कीजिए। शांत हो कर सुनिए और शांत हो कर जवाब दीजिए। (व्यवधान) कर्नल इन्द्र सिंह जी, जब आप बोल रहे थे तो हमने कोई टोका-टाकी नहीं की। आप काफी सीनियर मैम्बर हैं और अनुशासित फोर्स के आदमी हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से डिसप्लिन करना है।

अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने बंदरों की समस्या के बारे में अपनी चिन्ता ज़ाहिर की कि बंदरों से, आवारा पशुओं से किस

तरह से हम कृषि और बागवानी को बचाएं परन्तु माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने ढाई घण्टे से ज्यादा के बजट भाषण में इस बारे में एक शब्द भी कहना मुनासिब नहीं समझा। दिखाने के लिए तो आपने आते ही एक कमेटी का गठन कर दिया। सब कमेटी बनाई परन्तु पता नहीं उसकी कोई मीटिंग भी हुई या नहीं, उसकी कोई प्रोसिडिंग भी हुई या नहीं। अगर सब कमेटी ने कुछ किया होता तो बजट में आना था। यह बहुत ही चिन्ता का विषय है।

**13.03.2018/1440/केएस/डीसी/2**

यह सरकार कृषि और बागवानी के बारे में चिन्तित नहीं है। गाय के पीछे पड़ी है। राजनीतिक लाभ के लिए और लोगों की धार्मिक भावनाओं को गुमराह करने के लिए इस किस्म की स्कीम आप यहां पर ला रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी आपने कहा कि सूरत बदल देंगें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है आपको सूरत बदलनी चाहिए परन्तु सूरत के साथ सीरत बदलने की भी ज़रूरत है क्योंकि अच्छी सूरत के साथ अच्छी सीरत भी होनी चाहिए और दिलों को जीतने का हुनर भी आपको आना चाहिए तभी आप लोगों के दिल जीत सकते हैं। खाली शेरो-शायरी से काम नहीं कर सकते। अभी यहां पर शिक्षा के बारे में मेरे साथी अपने विचार रख रहे थे। शायद इनकी बातों में कुछ वजन हो परन्तु जहां तक एस.एम.सी. की बात है, अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी बाहर एस.एम.सी. वालों के जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और अंदर आप ही के दल के लोग एस.एम.सी. का विरोध कर रहे थे। दोहरे मापदण्ड है। बेचारे जो फूल-मालाएं ले कर नारे लगा रहे थे उन्हें क्या पता कि सदन में उन्हीं के खिलाफ साजिश रची जा रही है। एस.एम.सी. को पूर्व मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने इसलिए शुरू किया था क्योंकि जब आपकी पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो आपने जनजातीय क्षेत्रों से, बैकवर्ड एरियाज़ से विद पोस्ट टीचर हटाकर निचले क्षेत्रों में ला दिया था और आपके क्षेत्रों में एक ही पोस्ट पर तीन-तीन टीचर बैठ गए और हमारे जन-जातीय एरियाज़ में सारे स्कूल खाली हो गए थे। उनको एकदम लगाने का कोई तरीका नहीं था और एस.एम.सी. ही सबसे बढ़िया तरीका था। आप कहते हैं कि उसमें रोस्टर नहीं लगा। उसमें रोस्टर लगाने की क्या जरूरत थी? एस.एम.सी. के अंदर यह प्रावधान था कि उसी गांव का, उसी पंचायत का अगर कोई वहां पर पात्र व्यक्ति है तो वह उस स्कूल में लगेगा। इससे बड़ी योजना और क्या हो सकती थी? आज

एस.एम.सी. के माध्यम से हमारे कई सौ स्कूल चल रहे हैं। आज उसका बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। आप यह दोहरी नीति अपनाना छोड़ दें और आज जो बेचारे बाहर नारे लगा कर आपको धन्यवाद करके आपको फूल-मालाएं पहना कर गए हैं, उनको बोल दीजिए कि आपका चेहरा किस किस्म का है? आपका मुखौटा कौन सा है? वह भी उनको पता लगना चाहिए।

13.3.2018/1445/av/डीसी/1

**श्री जगत सिंह नेगी जारी-------**

यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में आपने नौजवानों को रूसा के नाम पर गुमराह किया। ए0बी0वी0पी0 जो आपका छात्र संगठन है उसको आपने गुमराह किया कि जैसे ही आप आयेंगे रूसा को हटायेंगे। आज आपकी सरकार बने दो महीने का समय हो गया है मगर आपने रूसा हटाने की कहीं पर भी बात नहीं की है। ए0बी0वी0पी0 वाले आपको हर रोज ज्ञापन सौंप रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि आप रूसा को खत्म करो। आप रूसा को खत्म नहीं कर सकते क्योंकि रूसा एक बहुत बढ़िया शिक्षा प्रणाली है। इसमें अध्यापक को भी काम करना पड़ता है, उसको भी अपना रिपोर्ट कार्ड देना पड़ता है इसलिए कुछ शिक्षकों ने भी बच्चों को गुमराह किया है। इस बारे में बच्चों को गुमराह करने में आपकी पार्टी भी पहले नम्बर पर थी। अब बताइए, आप रूसा में क्या करने जा रहे हैं? अब रूसा आपके अपने गले की फांस बन गई है। इसके साथ में, हमने भी अपनी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में यहां बहुत बार कहा कि आज सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बहुत कम हो रही है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। हर व्यक्ति अपने बच्चे को अंग्रेजी मीडियम वाले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है। इसलिए जब हम आर्थिक रूप से सम्पन्न हो गये तो आज हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। वहां पर चाहे टीचर की क्वालीफिकेशन नहीं है, हमारे सरकारी स्कूल में एक जे0बी0टी0 की नियुक्ति भी एंट्रैंस के

माध्यम से होती है। उसकी दो साल की ट्रेनिंग होती है और वह नैट क्वालिफाईड होता है। हिन्दी-हिन्दी की बात की जाती है, मेरा यह कहना है कि हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है और उसका महत्व भी होना चाहिए। परंतु आज इस देश में अंग्रेजी की जरुरत है, यह एक इन्टरनेशनल लैंग्वेज है और आप इसको कम नहीं आंक सकते। हमारे सबके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं। अधिकारियों के बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं और आज हमारे टीचरों के बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं। आप एक नीति बनाइए कि

**13.3.2018/1445/av/डीसी/2**

किसी विधायक, मंत्री, अधिकारी या किसी टीचर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ेगा फिर देखना कैसे हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ती है। (---व्यवधान---) हमने शुरू किया है। हमने जिला किन्नौर में सरकारी स्कूल में पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम शुरू किया है। बहुत सारे स्कूलों में आज बच्चों की संख्या बढ़ी है। हम लोग संकीर्ण विचार वाले नहीं है। आप लोग दिखाने के लिए हिन्दी-हिन्दी की बात करते हैं और सारे अपने बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं। आपको प्रदेश में अगर शिक्षा का स्तर बढ़ाना है तो इस बारे में चिन्तन करना होगा और इस ओर कोई कदम उठाना होगा। आपने एक काम अच्छा किया है। आपने जो रेजिडैंशियल स्कूल की बात की है मैं उसके लिए आपकी तारीफ करता हूं। रेजिडैंशियल स्कूल आज की आवश्यकता है। हमारा पिछले बजट में इस प्रकार का एक सुझाव था कि तहसील स्तर पर आप प्लस वन और प्लस टू के लिए रेजिडैंशियल को-ऐजुकेशन अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलिए जिसमें मैडिकल, नॉन-मैडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स इत्यादि की सारी सुविधाएं हों तो इस तरह से हम अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दे सकते हैं। उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए और यह कदम आपने उठाना है। मगर आपने अभी इसके लिए प्लानिंग नहीं की है और अभी यहां पर आपके शिक्षा मंत्री जी भी नहीं बैठे हैं। शिक्षा मंत्री जी बाहर एस0एम0सी0 के नारे सुनने में खुश हो रहे हैं। लेकिन यहां पर अधिकारी लोग बैठे हैं तो आप रेजिडैंशियल स्कूल की बात को नोट कर लें। आपने एकलव्य स्कूल के बारे में झूठ बोला है, आपने कहा है कि एकलव्य

स्कूल खोलेंगे। दिल्ली के अन्दर आपके वित्त मंत्री जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि एकलव्य स्कूल की शुरुआत करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एकलव्य स्कूल यू0पी0ए0 की देन है और हिमाचल का पहला एकलव्य स्कूल मैंने राजा वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद से जिला किन्नौर के अन्दर शुरू किया हुआ है। वह स्कूल आज किसी भी बोर्डिंग स्कूल के बराबर है जिसमें ढाई सौ से ज्यादा लड़के-लड़कियां अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे हैं। आज उस स्कूल के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी तथा मैथेमैटिक्स ओलम्पियाड स्तर की प्रतियोगिताओं में आगे बढ़ रहे हैं। आप स्कूल खोलिए,

**13.3.2018/1445/av/डीसी/3**

आप गलत मत कहिए। एकलव्य स्कूल ट्राइबल एरिया में खुलना है। यहां पर लाहौल-स्पिति से राम लाल मंत्री जी बैठे हैं, आपके वहां दो स्कूल खुल सकते हैं। यहां पर माननीय सदस्य जिया लाल जी बैठे हैं, आपके चार खुल सकते हैं। आप शुरू कीजिए, ये झूठ बोल रहे हैं। इसके लिए पैसा पड़ा हुआ है, आप अपने ट्राइबल एरिया में यह स्कूल खोल सकते हैं। यह हमारी यू0पी0ए0 सरकार के प्रधान मंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह जी की देन है। श्रीमती सोनिया गांधी जी की देन है। (---व्यवधान---) हां, किया है। इसमें हंसने की क्या बात है? यह स्कीम हमारे समय में बनी है। आप हमारी सरकार द्वारा बनाई हुई स्कीम को अपनी स्कीम कहते हैं। (---व्यवधान---) वह तो मैं कह ही रहा हूं कि झूठ बोलने का तो आपको ईनाम मिलना चाहिए। मुख्य मंत्री जी प्रैस वालों को बताते-बताते थके नहीं कि हमने 28 नई स्कीमें शुरू की है। यहां पर माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी ने सारी स्कीमें गिनाई और उसमें से एक भी स्कीम नई नहीं है। हमारी सारी-की-सारी स्कीमों को आपने नया नाम दिया है क्योंकि नाम देने में आप माहिर है और आप जो मर्जी नाम दे सकते हैं। आज आप पोर्टब्लेयर का नाम बदलने वाले हैं। आप चाईना का नाम भी बदल दो ताकि कम-से-कम वह हमें आंखें न दिखाएं।

13.3.2018/1450/TCV/YK-1

**श्री जगत सिंह नेगी..... जारी**

आप पाकिस्तान का नाम भी बदल दो ताकि रोज़-रोज़ हमारी सेना के जो नौज़वान शहीद हो रहे है, उससे भी बच जायें। लेकिन नाम बदलने से काम नहीं बदल जाता है। ---(व्यवधान)--- माननीय अध्यक्ष जी अभी तो मैंने शुरू किया है, जन जातीय इलाका है, हर जगह रिजर्वेशन है, हमें बोलने में भी छूट दी जाये। मुझे उम्मीद है कि मुझे आपका संरक्षण मिलेगा। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ मोटी-मोटी बातें यहां जरूर कहूंगा। आप कह रहे हैं, हम वर्दी दे रहे हैं। क्या आप हर चीज में नाम डाल देंगे? वर्दी में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं उनका सम्मान करता हूं। परन्तु अब हमें सलवार कमीज़ को भी छोड़ना पड़ेगा। हमारे बच्चों को भी पैंट, कोट और टाई मिलनी चाहिए। आर0एस0एस0 वालों ने भी अब निक्कर छोड़कर पैंट पहनना शुरू कर दिया है। हमारे बच्चे क्यों न पहने? आप इनको टाई, पैंट सब कुछ दो पर उसमें किसी का नाम मत डालिये। पड़ौस का बच्चा टाई, कोट, पैंट पहनकर प्राइवेट स्कूल में जाता है और हमारे बच्चों के लिए आपने जो वर्दी लगा रखी है, वह पहनने लायक भी नहीं होती है। इसलिए उसको बदल दीजिए। ---(व्यवधान)--- पांच साल में नहीं हुआ, अब तो आप करो। ---(व्यवधान)---आप सुनने की शक्ति रखो। आपका समय आयेगा तब बोलना आपने---(व्यवधान)--- आपने अभी बस्ता देने की बात की है। स्कूल में जो लैपटॉप दिया जा रहा था, उसके लिए आपने बज़ट में जीरो पैसा कर दिया है। आपने बच्चों को उस लैपटॉप से भी वंचित कर दिया है। अब आप एक बस्ता देंगे, उसमें पता नहीं आपके किस लीडर का फोटो छप जाएगा। अगर उसमें फोटो छापना है, तो उसमें राष्ट्रध्वज लगाईये, उसमें महात्मा गांधी जी का नाम लगाईये। ---(व्यवधान)--- श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश के लिए शहीद हुई है, उनका फोटो छाप दीजिए। ---(व्यवधान)-----उसमें गोडसे का फोटो नहीं लगेगा। ---(व्यवधान)--- आप कहते हैं इंस्टीच्यूशन्ज़/स्कूल नहीं खुलने चाहिए। आप तो स्कूल विरोधी है, हैल्थ विरोधी है। आप कहते हैं स्वास्थ्य के इंस्टीच्यूशन्ज़ नहीं खुलने चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जी अभी हाऊस में नहीं हैं। आप कहते हैं ---(व्यवधान)---

**अध्यक्षः** माननीय सदस्य, आप चेयर को रैफर करके बात करिए, उधर को नहीं। आप अपनी बात कहिए। हम सारा रिकार्ड कर रहे हैं।

13.3.2018/1450/TCV/YK-2

**श्री जगत सिंह नेगीः** माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन उधर से आवाज़ ज्यादा आ रही है, इसलिए मैं आपको देख ही नहीं पा रहा हूं। आप 103 मैडिकल सेंटरों को बन्द करने जा रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि पिछली सरकार ने 103 हैल्थ इंस्टीच्यूशन्ज़ खोल कर दिए हैं। इनकी नोटिफिकेशन्ज़ हुई हैं, पोस्टें स्वीकृत हुई हैं, आपको तो इनके ऊपर काम करना है। कौन-सा काम ऐसा होता है कि पहले बिल्डिंग बन जाये और बाद में इंस्टीच्यूशन खुलेगा? ---(व्यवधान)--- आपका चेहरा ज्यादा सुन्दर है इसलिए मुझे उधर देखने में ज्यादा खुशी हो रही है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरा जो टाईम लिया है, मुझे वह टाईम भी दीजिए। ---(व्यवधान)--- जहां तक स्कूल खोलने की बात है, चाहे जन जातीय क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, जब राजा साहिब ने ये फैसला दिया था कि एक किलोमीटर के अंदर बच्चों को चलना न पड़े, छोटे-छोटे बच्चों को स्कूल के लिए दूर न जाना पड़े और कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे। इस बात को ध्यान में रखकर इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया और आज शिक्षा के क्षेत्र में हम हिन्दुस्तान में अग्रणीय बने हैं। इसमें यदि कमी हैं, तो उसको सुधारने की ज़रूरत है। स्कूलों में यदि अध्यापक कही कम या ज्यादा है, तो उनको रैशनलाईज कीजिए। सरकार आपकी है, आप डाटा मंगवाईये। जहां एक है, उसको दो कीजिए और जहां बच्चे कम है, वहां कम कीजिये। एक बात मुझे बड़े अफ़सोस के साथ कहनी पड़ रही है, किसी माननीय सदस्य ने कहा कि स्कूल में नेपाली है, बिहारी है। क्या नेपालियों को पढ़ने का अधिकार नहीं हैं? आज हिन्दुस्तान में, बॉम्बे में जाओ, मैट्रोसिटी में जाओ, सारे में चौकीदारी का काम नेपाल के लोग ही करते हैं। नेपाल के लोगों की आज भी हिन्दुस्तान के अन्दर गोरखा रेजीमेंट हैं। जिसमें परमवीर चक्र विजेता, वीरचक्र विजेता और महावीर चक्र विजेता हैं, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। आप उनको इस तरह से देखते हैं। ये आपकी छोटी व संकीर्ण सोच को दर्शाता है। बिहारी कौन है? आज हिमाचल प्रदेश में जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है,

13-03-2018/1455/NS/HK/1

श्री जगत सिंह नेगी-------जारी।

अगर बिहारी न हों तो हमारे यहां कन्स्ट्रक्शन का काम भी नहीं होगा। क्या हिमाचल के लोगों का बिहार के लोगों को पढ़ाना गलत काम है? आप अपनी सोच बदलिये। ये जो आपकी संकीर्ण सोच है उसी के कारण आज देश को खतरा पैदा हो रहा है। हमारे देश के अंदर लगभग 600 के करीब राजा/महाराजा थे, उन्होंने देश को कश्मीर से ले करके कन्याकुमारी तक एक बनाया है। उनमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल एक हैं। (घण्टी) आज आप उनकी मूर्ति लगभग 3000 करोड़ रुपये की वोट के लिए तो लगा रहे हैं परन्तु आपने उनके विचार को दरकिनार किया है। आप सोच बदलिये, सूरत बदलने से कुछ नहीं होगा, सीरत बदलिये। समय हो रहा है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा।

**अध्यक्षः** समय हो गया है।

**श्री जगत सिंह नेगीः** मैं अपनी एक बात और यहां पर रखना चाहूंगा। आप उज़ाला बांटने की बात करते हैं और आप उज़ाला कैसे बांट रहे हैं? आप उज़ाला ऐसे बांट रहे हैं जैसे अंधा बांटता है और सब अपने पास ही रखता है, वैसे ही आप उज़ाला बांट रहे हैं। आपने जनजातीय क्षेत्रों में ऐसा ही किया है। हमारे जनजातीय क्षेत्र लाहौल और स्पिति, पांगी भरमौर और किन्नौर हैं। इस बार पहली बार 30 सालों के अंदर ऐसा हुआ है कि दो स्थानों से भाजपा के विधायक और एक स्थान से कांग्रेस का विधायक जीत कर आया है। इससे पहले यह परंपरा या नियम रहा है कि ट्राईबल एरियाज़ में एडवाईज़री कमेटी का चेयरमैन विधायक ही होता है। ---(व्यवधान)--- आपमें सुनने की शक्ति नहीं है। मैं वही कह रहा हूं क्योंकि आप अभी भी यही सोच रहे हैं कि आप विपक्ष में बैठे हैं। अब आप मंत्री बन गये हैं तो थोड़ी इस सदन की गरिमा रखिये।

**अध्यक्षः** माननीय सदस्य आप मेरे से बात करें।

**श्री जगत सिंह नेगीः** सर, आप इनको भी रोकिए। आपके संरक्षण की जरूरत विधायक को ज्यादा होती है और मंत्री को कम होती है। ये मंत्री हैं तो इनको अनुशासन में रहना पड़ेगा।

**अध्यक्षः** आप बीच में मत बोलिये, माननीय सदस्य ने अपनी बात खत्म करनी है।

13-03-2018/1455/NS/HK/2

**श्री जगत सिंह नेगीः** सर, अगर ये बोलने नहीं देंगे तो मैं अपनी बात कहां खत्म करूंगा। आप जनजातीय लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। आप जहां से भाजपा के विधायक जीत कर आये हैं, उनको एडवाईज़री कमेटी का चेयरमैन बना रहे हैं और किन्नौर से कांग्रेस का विधायक जीत कर आया है तो उसके सिर पर जिलाधीश को बैठा रहे हैं। आप किन्नौर के जनजातीय लोगों/ बोर्डर के लोगों से अन्याय कर रहे हैं। वर्ष 2006 से ले करके आज तक चाहे कांग्रेस या भाजपा का विधायक रहा हो, लाडा का चेयरमैन विधायक रहा है। लेकिन आज आपने जिलाधीश को बैठा दिया। प्रोटोकोल में विधायक, जिलाधीश से ऊपर है और आप उसको नीचे कर रहे हैं। आप विधायक की शक्तियों को कम कर रहे हैं। आप विधायक की संस्था को खत्म करने जा रहे हैं। आपने साडा का चेयरमैन भी जिलाधीश को बनाया है। आप बिल्कुल अन्याय कर रहे हैं। आपके हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि

**"खुशबू आ नहीं सकती कमल के फूलों से,**
**विकास हो नहीं सकता भाजपा के जुमलों से।"**

आपकी जो ये जुमलेबाज़ी है, आप इसको छोड़ दो। मैं नहीं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी की सोच इतनी संकीर्ण या छोटी होगी कि आते ही जनजातीय लोगों से अन्याय करना शुरू कर दिया। आपके जंजैहली क्षेत्र में पिछले दो महीने से आग लगी हुई थी।

**अध्यक्षः** माननीय सदस्य वाईंड अप करें।

**श्री जगत सिंह नेगीः** सर, मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। जो समय इन्होंने मेरा लिया है आपसे निवेदन है कि वह समय आप मुझे ग्रेस में दें।

**अध्यक्षः** आप चर्चा ही करते रहेंगे और मैं अगले सदस्य को बोल दूंगा। आप अपनी बात कहिए।

**श्री जगत सिंह नेगीः** मैं अपनी बात कह रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी की सोच संकीर्ण नहीं हो सकती है।

**श्री वीरभद्र सिंहः** अध्यक्ष महोदय, मैं अपना समय माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी को देता हूं।

13-03-2018/1455/NS/HK/3

**श्री जगत सिंह नेगीः** धन्यवाद सर। क्योंकि राजा साहब हमेशा ही जनजातीय लोगों के हितैषी रहे हैं। वर्ष 1983 में राजा साहब पहली बार प्रदेश के मुख्य मंत्री बने थे। तब से जनजातीय क्षेत्र का विकास हुआ है। इन्होंने अन्य इलाकों का भी विकास किया है। लेकिन जनजातीय विकास के ये महान योगी रहे हैं। इन्हीं के समय में विधायकों को जनजातीय क्षेत्र के एडवाईज़री कमेटी का चेयरमैन बनाने का नियम शुरू हुआ है। यह नियम आज भी है। जो नोटिफिकेशन आपने हस्ताक्षर करके छिपा कर रखी है, उसमें आपने किन्नौर के विधायक को बाहर किया हुआ है। यह किन्नौर के ही नहीं बल्कि किन्नौर के जनजातीय और बोर्डर एरियाज़ के लोगों के साथ आप अन्याय करने जा रहे हैं। आपने जंजैहली में दो महीनों तक लोगों को आंदोलन करने के लिए विवश किया और आज आपने उसको बदल दिया। अब कहते हैं कि 12 दिन वहां रहेंगे और 12 दिन यहां रहेंगे। आपने फेरी वाला एस0डी0एम0 ऑफिस खोल दिया है। एस0डी0एम0 फेरी लगायेगा। वह न तो इधर देखेगा और न ही उधर देखेगा। लोग पूछेंगे जंजैहली में है, वह कहेगा थुनाग में है और थुनाग में पूछेंगे तो जंजैहली में है और यह अधिकारी आपका शिमला में डटा रहेगा।

13.03.2018/1500/RKS/YK-1

श्री जगत सिंह नेगी.. जारी

इस किस्म की व्यवस्था आप कर रहे हो। आपको इस किस्म की व्यवस्था से बचने की जरूरत है।

**अध्यक्षः** माननीय सदस्य, कृपया वाइंड-अप करें।

**श्री जगत सिंह नेगीः** सर, ये लोग मुझे बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं।

**अध्यक्षः** माननीय सदस्य, आप मेरे से बात कीजिए। आप चेयर से बात कीजिए। आपके 25 मिनट हो गए हैं। मैं आपको एक मिनट और बोलने का समय दूंगा।

**श्री जगत सिंह नेगीः** माननीय अध्यक्ष जी, पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने अपने बोलने का समय भी मुझे दिया है।

**अध्यक्षः** माननीय श्री वीरभद्र सिंह कितना भी समय ले सकते हैं। उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। वे तो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। लेकिन आप अपनी बात कीजिए।

**श्री जगत सिंह नेगीः** अध्यक्ष जी, यहां पर होर्टिकल्चर के बारे में बहुत बड़ी बात हुई। यहां पर इस तरह से बताया गया कि जैसे दो महीनों के अंदर आपने बहुत बड़ी होर्टिकल्चर की स्कीम लाई हो। आप भूल रहे हैं और माननीय सदस्य जी को भी शायद याद नहीं रहा होगा कि वर्ल्ड बैंक के माध्यम से हार्टिकल्चर का जो प्रोजेक्ट आया है, वह पूर्व मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है। 1300 करोड़ रुपये के बजट का यह प्रोजैक्ट राजा वीरभद्र सिंह जी के समय में आया है। चाहे आप पिछला बजट देख लीजिए। आप कह रहे हैं कि इटली से रूटस्टॉक मंगवा रहे हैं। दुनिया के अंदर अगर बैस्ट रूटस्टॉक है तो वह इटली का है, यू.एस.ए. का नहीं। आपको हर चीज़ में गलत दिखता है। आप राफेल के 350 करोड़ रुपये वाले जहाज को 1450 करोड़ रुपये में खरीदने वाले लोग हैं। आपको रूटस्टॉक में भी गलती दिखती है।

**अध्यक्षः** माननीय सदस्य, कृपया आप वाइंड-अप कीजिए। मैं अगले वक्ता को बुला लूंगा।

13.03.2018/1500/RKS/YK-2

**श्री जगत सिंह नेगीः** माननीय अध्यक्ष जी, आप मुझे बोलने के लिए समय नहीं दे रहे हैं जबकि राजा साहब ने अपने बोलने का समय भी मुझे दिया है। दूसरा, आपने किन्नौर में 'प्रोजैक्ट एडवायज़री कमेटी' के चेयरमैन, विधायक को हटाकर डी.सी. को नियुक्त किया है। मैं उसका भरपूर विरोध करता हूं। यह जनजातीय क्षेत्र के लोगों से अन्याय है। यह किन्नौर के लोगों के जनमत का अपमान है। इसलिए मैं विराध दर्ज़ करते हुए सदन से वाक आउट करता हूं। धन्यवाद।

**(माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह नेगी, सदन से बहिर्गमन कर गए।** )

13.03.2018/1500/RKS/YK-3

**अध्यक्षः** अब माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार जी चर्चा में भाग लेंगे।

**श्री विनोद कुमारः** माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2018-19 के लिए जो बज़ट अनुमान हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी ने 9 मार्च, 2018 को माननीय सदन में पेश किए, मैं उस पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री आदरणीय जय राम ठाकुर जी को, जिन्होंने एक ऐतिहासिक बजट, सर्वहित बजट पेश किया है, उसके लिए मैं उन्हें हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से बधाई देता हूं और साथ में उनका धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने नई सोच के साथ लकीर से हटकर एक चमत्कारी बज़ट पेश किया है। इस बज़ट में समाज के हर वर्ग का हित रखा गया है। इसको समझने के लिए सोच बदलने की जरूरत है। अगर इस बज़ट को राजनीतिक विचारधारा से देखेंगे तो यह सही नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष जी यहां पर वरिष्ठ सदस्य ने कुछ अपनी बात रखी है।

**(माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)**

उस बात पर मैं आगे बात करूं तो इससे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि यहां पर युवाओं को लेकर बहुत सी चिंता व्यक्त की गई है। जब वर्ष 2012 में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उस समय आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि जितने भी बेरोज़गार हैं उन्हें रोजगार के अवसर दिए जाएंगे और जो बेरोजगार रहेंगे उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।

13.03.2018/1505/बी0एस0/ए0जी0-1

**श्री विनोद कुमार .........जारी**

आप कहते हैं कि उन बेरोजगारों को ठगने का कार्य हमारी सरकार ने किया है? मैं इस सदन के माध्यम से आपको कहना चाहूंगा कि आपकी सरकार ने पांच वर्षों में मात्र तीन महीने ही कुल 21,000 बेरोजगार युवाओं को आपने बेरोजगारी भत्ता दिया है। यदि आप इतने ही हितेशी उन बेरोजगार युवाओं के थे तो आपको चाहिए था कि आप पूरे पांच साल उन्हें बेरोजगारी भत्ता देते। आज आपकी सरकार प्रदेश में नहीं है तो आप बेराजगारों की बात कर रहे हैं।

माननीय उपाअध्यक्ष महोदय, यहां पर गाय को ले करके बहुत सारी बातें की गई। मुझे भी नाचन की जनता के आर्शीवाद से दूसरी बार नाचन विधान सभा क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। गाय पर चर्चा न जाने कितनी बार इस माननीय सन में हुई। जब भी हमारा बजट सत्र हुआ या अन्य कोई भी सत्र होता था तो गाय को ले करके हमेशा चर्चा की जाती थी लेकिन चर्चा के बाद कोई भी पग, कोई भी कदम आपकी सरकार की ओर से पांच साल नहीं उठाए गए। मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी सरकार ने पांच वर्षों में गाय की स्थिति को सुधारने के लिए, गौशालाओं के सुधार के लिए कौन से कदम आपकी सरकार की तरफ से उठाए गए? आपने तो सिर्फ बातें की हैं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद अगर मां के दूध के बाद किसी के दूध की बात आती है तो उसे गौ माता के दूध की याद आती है। आज अगर उस गाय के चारे की बात की गई तो कौन सी गलत बात की गई।

माननीय उपाध्यक्ष जी, यहां एक और बात वर्दी के बारे में कही गई । पिछली बार जब हमारी सरकार थी। उस समय "अटल वर्दी योजना" हमारी पिछली सरकार ने

13.03.2018/1505/बी0एस0/ए0जी0-2

2007-2012 तक प्रदेश शुरू की थीं। आपकी सरकार प्रदेश में बनी, आपकी सरकार बनते ही आपने उस योजना का नाम बदल दिया। आज तो आप यहां बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। कहा गया कि वर्दी की आवश्यकता नहीं है। अब पैंट चाहिए, कोट चाहिए और टाई भी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं आप पांच क्या करते रहे? एक चीज भी आज इसके अलावा नहीं दे पाए और हमने बात की थी की उस वर्दी को समय पर और लगातार बच्चों को दिया जाए। लेकिन आपकी सरकार प्रदेश के अंदर थी तो समय पर बच्चों को वर्दियां नहीं दी गई, पैसे नहीं दिए गए। बहुत सारे मामले हमने विधान सभा में भी उठाए लेकिन बच्चों को वर्दियां समय पर आपकी सरकार नहीं दे पाई।

इसके साथ मैं कहना चाहूंगा कि संघ को ले करके या आर.एस.एस. को ले करके इस तरह की टिप्पणियां एक बार नहीं अनेकों बार इस सदन में आपकी ओर से की जा रही है। मैं आपको पूछना चाहूंगा कि पिछली बार जब आपकी सरकार थी, आपके भी एक नहीं अनेकों संगठन थे। हमने कभी आपके साथ उन संगठनों को ले करके चर्चा नहीं की है। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि अगर आज हिमाचल प्रदेश में या देश में सरकार बनी है इसमें प्रदेश की जनता का भरपूर सहयोग हमें मिला है और जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य बैठे हैं ये सारे का सारा प्रोडक्ट राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से निकला है। इसमें आपको किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी करने की आपश्यकता नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर चर्चा की कि दो महीने की सरकार ने 2200 करोड़ रुपये का कर्जा लिया है। मैं कर्जे को ले करके बात करना चाहूंगा। जब-जब भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें रही हैं। अंधाधुध कर्जा लिया गया। जिस कर्जे की आवश्यकता भी नहीं होती थी उसको भी लिया गया। मैं बात करना चाहूंगा कि इतना अंधाधुध कर्जा इन्होंने हिमाचल प्रदेश में लिया है। आज 46386 करोड़ रुपये का कर्जा हिमाचल प्रदेश के ऊपर है, जिसकी ब्याज अदायगी पर 3500 करोड़ रुपये का खर्चा होता है।

13.03.2018/1510/ डी0टी0/ए0जी0-1

**श्री विनोद कुमार ...जारी.....**

मैं कहना चाहूंगा कि पिछली बार जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2007-2012 के बीच में थी तो केवल 7621 करोड़ रुपये का कर्जा प्रदेश के विकास कार्य को करने के लिए लिया था। उस पाचं वर्ष के कार्य काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक नहीं अनेकों विकास के काम इस हिमाचल प्रदेश के अन्दर किए । लेकिन जैसे ही आपकी सरकार वर्ष 2012-2017 में प्रदेश में बनी तो इन पांच वर्षों में आपने 18,787 करोड़ रुपये का ऋण लिया । यानि हमने पनी सरकार के कार्यकाल में 7621 करोड़ रुपये और आपकी सरकार ने अपने कार्यकाल के पांच वर्षों में 18,787 करोड़ रुपये का ऋण लिया है। हमारी सरकार की अपेक्षा आपने 11,166 करोड़ रुपये अधिक का ऋण उन पांच साल के कार्यकाल में लिया है। माननीय अध्यक्ष् महोदय, मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि कांग्रेस

की सरकार जब-जब भी हिमाचल प्रदेश में रही है, बहुत भारी मात्रा में इन्होंने ऋण लिया है। इन्हें पता है की इनकी सरकार पांच वर्ष के लिए ही रहती है और आने वाली सरकार उसका खामियाजा भुगतती रहती है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपको इस प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब प्रदेश में आदरणीय जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और जिस तरह से हमारी सरकार ने काम करना शुरू किया है, वह करती रहेगी। हिमाचल प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से यह सरकार कम से कम 20-25 साल तक सभी मतदाताओं के आशीर्वाद से रहने वाली है। इसके साथ-साथ बात आई कि केन्द्र से हिमाचल प्रदेश को कितनी-कितनी मदद और किस-किस कार्याकाल में मिली है। मैं उसके विषय में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष जी, 2013-14, 2014-15 में केन्द्र में यू.पी.ए. की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी और इन तीन वर्षों में

13.03.2018/1510/ डी0टी0/ए0जी0-2

हिमाचल प्रदेश को 28,552 करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश के विकास कार्यों के लिए दिए गए और जैसे ही केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 2015-16 और 2016 से 17 के बीच में इन दो वर्षों में केन्द्र सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने के लिए 46,793 करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश के विकास कार्य को करने के लिए दिया गया। लेकिन आपने कभी केन्द्र सरकार का धन्यवाद करना उचित नहीं समझा। इसके साथ-साथ दो सालों में केन्द्र की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 69 नेशनल हाईवे, चार फोर लेन, तीन मैडिकल कॉलेज और एक AIIMS भी हिमाचल प्रदेश को दिया है। मैं अपनी केन्द्र सरकार का और इस देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि आपने हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया है। जब हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं था तो जितनी भी स्कीमें हमारी बनती थी उन स्कीमों के तहत 50 प्रतिशत पैसा हमारी प्रदेश सरकार को केन्द्र की सरकार से विकास कार्यों को करने के लिए आता था।लेकिन जैसे ही हिमाचल प्रदेश को आदरणीय

नरेन्द्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अब 90/10 की रेशो से 90 प्रतिशत पैसा उन स्कीमों के ऊपर केन्द्र सरकार खर्च करती है और केवल 10 प्रतिशत पैसा हिमाचल प्रदेश को देना होता है। इसके लिए भी मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा

**13.03.2018/1515/SLS-AG-1**

**श्री विनोद कुमार ... जारी**

क्योंकि उन्होंने टैक्स फ्री बजट पेश किया है। केवल एक ही सैस या टैक्स लगाया गया है। इससे भी, मुझे लग रहा है कि विपक्ष के हमारे बहुत से विधायकों को पीड़ा हो रही है कि शराब की बोतल से जो 2 रुपये टैक्स या सैस लिया जा रहा है,...(व्यवधान)... मुझे लगता है कि आपका हिसाब ठीक नहीं है, उसको ठीक कर लें। दो रुपये प्रति बोतल के हिसाब से जो पैसा हिमाचल सरकार ले रही है, उसमें से एक रुपया नेक काम यानी गौसदन के लिए जा रहा है। जब हम उस तरफ होते थे तो आप भी उस गौसदन की चिंता करते थे लेकिन आपकी सरकार ने इसकी चिंता नहीं की, हमारी सरकार ने की। उसका एक रुपया अब 108 ऐंबुलैंस के लिए जाता है जिसकी शुरुआत, जब पिछली बार हमारी सरकार प्रदेश में बनी थी, उस सरकार ने ही 108 ऐंबुलैंस योजना की शुरूआत की थी। ...(व्यवधान)...

**उपाध्यक्ष** : आप सभी सदस्यों से निवेदन है कि कृपया बीच में न बोलें। आपमें से कई सदस्य अपने समय में बोल चुके हैं, इसलिए बीच में न बोलें।

**श्री विनोद कुमार** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस एक रुपये को उस ऐंबुलैंस योजना के लिए ख़र्च किया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इनकी चिंता वाजिब है। वह इसलिए वाजिब हैं क्योंकि यहां से कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि इस बजट में कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा और

माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने जो बजट पेश किया है वह गरीब, किसान, छात्र, युवा, कर्मचारी और उद्योगपति; सबका हित करने वाला है यानी इसमें इन सब वर्गों का ध्यान रखा गया है।

इस बजट में विशेषकर विधायकों का भी ध्यान रखा गया है। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहूंगा कि जब हम 2012 में चुनकर आए थे, मुझे आज भी याद है कि सभी विधायकों ने बार-बार इस बात को कहा था कि हमारी विधायक-निधि बढ़नी चाहिए लेकिन उस समय विधायक-निधि नहीं बढ़ाई गई थी। ...(व्यवधान)...

**13.03.2018/1515/SLS-AG-2**

काजल जी, आप फिर भूल गए हैं कि 2013 में हमारी विधायक-निधि नहीं बढ़ाई गई थी। उसके बाद बढ़ाई गई है, यह अलग बात है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मुख्य मंत्री जी का जिन्होंने सबकी बात सुनी और सबकी चिंता करते हुए 1.10 करोड़ रुपये को, जो हमें विधायक-निधि मिलती थी, उसे 1.25 करोड़ रुपये किया है। इसके साथ-साथ मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो हमें 5.00 लाख रुपये ऐच्छिक-निधि मिलती है उसको भी लगभग 40% बढ़ाकर 5.00 लाख से जो 7.00 लाख रुपये किया गया है।

इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि एक जुलाई, 2017 से कर्मचारियों का आई.आर. 4% की दर से बढ़ाया गया है जबकि आप कहते हैं कि हम कर्मचारी विरोधी हैं। आज सारा कर्मचारीवर्ग इस जय राम ठाकुर सरकार से खुश है। लेकिन विपक्ष के मेरे जितने भी माननीय विधायक हैं उनको लग रहा है कि चाहे किसान की बात हो, बागवान की बात हो, कर्मचारी की बात हो, ये सारे-के-सारे वर्ग आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार से खुश क्यों है। इसलिए आपको दिक्कत है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी भी 210 रुपये से बढ़ाकर 225 रुपये करने की जो घोषणा की है, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। इसके साथ-साथ मैं उनका धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूंगा

कि बिना आय की जो पैंशन थी वह 80 साल की आयु के लोगों के लिए थी। जब भी हम अपने विधान सभा क्षेत्र में जाते थे, बहुत से बुजुर्ग लोग हमसे बार-बार इस बात को पूछते थे कि हमारी पैंशन कब लगेगी। उन्हें पैंशन न लगने का सबसे बड़ा कारण यह था कि किसी के घर में किसी का बेटा सरकारी नौकरी में होता था या किसी के पास जगह ज्यादा होने के कारण उसको पैंशन नहीं लग पाती थी। कुछ मामले तो हमने ऐसे भी देखे कि जब किसी बुजुर्ग के एक्सपायर होने पर हम सांत्वना देने उसके घर जाते थे तो उसके घर वाले इस बात को कहते थे कि पैंशन का फार्म जेब में डाला था, आयु कम होने के कारण उनको पैंशन नहीं लग पाई।

**13/03/2018/1520/RG/DC/1**

**श्री विनोद कुमार------जारी**

आपने जो एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है और जिस आयु सीमा को आपने 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया है, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगा। प्रदेश के 1,30,000 बुजुर्गों को इस पेन्शन योजना का सीधे तौर पर लाभ मिलेगा।

**श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु :** उपाध्यक्ष महोदय, घण्टी भी बजाइए।

**उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य, ऐसा है कि माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी 27 मिनट बोले हैं। हम घण्टी बजाएंगे।

**श्री विनोद कुमार :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान पिछली सरकार के कार्यकाल की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा। यहां पिछली सरकार के कार्यकाल को लेकर बड़ी-बड़ी बातें की जा रही थीं। मुझे आज भी वह दिन याद है कि जब हम उस तरफ बैठे होते थे और आपको बार-बार एक काम के लिए अनेकों बार कहते थे, लेकिन आप हमारी बात नहीं सुनते थे। मैं कहना चाहूंगा कि पिछले पांच वर्षों में यदि सबसे बड़ी दिक्कत रही होगी, तो वह सड़कों को लेकर रही है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि पूरे प्रदेशभर में सड़कों में गढ्डे नहीं, गढ्डों में सड़क हो गई थीं। हमने एक बार नहीं, अनेक बार इस बात को लेकर आपको

कहा भी और यहां चर्चा भी की। इसके साथ हमने पिछली बार एक बात और कही थी कि चाहे मेरे विधान सभा क्षेत्र या किसी भी विधान सभा क्षेत्र में जितना भी टारिंग का काम हुआ है, तो आज टारिंग होती थी और एक हफ्ते के बाद वह सारी-की-सारी टारिंग उखड़ जाती थी। पूर्व मुख्य मंत्री महोदय भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में उस समय आए थे और सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उन्होंने आदेश दिए थे कि जिस तरह के गढ़डे इस नाचन विधान सभा की क्षेत्र की सड़कों पर पड़े हैं, मैं चाहूंगा कि उन सारी सड़कों को ठीक किया जाए।---(घण्टी)---लेकिन माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी की बात शायद इनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी नहीं मानी थी।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र की चैल चौक से गोहर सड़क की टारिंग, गणेश चौक से चामुण्डा मंदिर, कतलोक से भगवानपुर, बाड़ू से नछेद, जाचमोड़ से लोट, कोट से देवीधार सड़क की जो भी टारिंग हुई है, मुझे नहीं लगता कि यह टारिंग 5 से 7 या दस दिनों तक चली होगी। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन

**13/03/2018/1520/RG/DC/2**

रहेगा कि इसकी जांच करवाई जाए और इसमें जो भी चाहे अधिकारी, कर्मचारी या ठेकेदार शामिल हों, जिन्होंने भी इस तरह की घटिया हरकतें की हैं और काम ठीक नहीं किया है, उन्हें दण्डित भी किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, गर्मी के मौसम में लोगों को पानी न मिले या कम मिले, यह बात तो समझ आती है, सर्दियों में लोगों को कम पानी मिले, यह बात भी समझ आती है, ---(व्यवधान)----लेकिन पिछली बार की सरकार में बरसात में भी लोगों को पीने-का-पानी नहीं मिले, यह बात बिल्कुल समझ नहीं आती। पिछली सरकार के समय चाहे सड़क, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की बात हो, किसी भी बात को लेकर सरकार ने किसी भी तरह की गंभीरता नहीं दिखाई। पिछली सरकार के समय में तो शिमला जिले में ही टैंकों के अंदर बच्चे का कंकाल मिला था।

**उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

**श्री विनोद कुमार** : उपाध्यक्ष महोदय, ये सारी चीजें इस माननीय सदन में आपके सामने बताई भी गई हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की चिन्ता या गंभीरता पिछली सरकार ने व्यक्त

नहीं की। अन्त में मैं ज्यादा लम्बी बात न कहता हुआ यही कहूंगा कि जो बजट हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने यहां पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

**13/03/2018/1520/RG/DC/3**

**उपाध्यक्ष :** अब श्री होशयार सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

**Sh. Hoshyar Singh :** Thank you, Deputy Speaker, Sir. This is my first Budget speech. जो भी अभी तक हमने सुना, उससे काफी अनुभव हुआ। लेकिन ज्यादातर जो इस बजट बुक में दर्शाया या बताया गया है, मैं उसमें कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

**13/03/2018/1525/MS/DC/1**

**श्री होशयार सिंह जारी----**

हर कोई अपनी-अपनी प्रशंसा करने में लगे हुए हैं। जो इस बजट बुक के अंदर लिखा हुआ है उस पर अभी तक किसी ने भी ऐसा गहरा कोई सुझाव नहीं दिया है। उपाध्यक्ष जी, मैं समय को देखता हुआ बिन्दुवार बताऊंगा। बजट बुक में क्रम संख्या-15 में "जन अधिकार पुस्तिका" के बारे में लिखा गया है। इस किताब में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा उनमें क्या लाभ दिया जाएगा, की जानकारी होगी। यह बहुत अच्छी बात है और सरकार का यह बहुत अच्छा कदम है। उपाध्यक्ष जी, हमारे विधान सभा क्षेत्र में 99 प्रतिशत लोगों को अभी तक यह पता नहीं है कि किस स्कीम से कैसे सुविधा लेनी चाहिए। चाहे वह किसी गरीब की शादी का केस हो, किसी विधवा, वृद्ध या किसी अपंग का मामला हो। मैं इस निर्णय की तारीफ करता हूं और चाहता हूं कि इस पुस्तिका में हर चीज छापी जाए और हरेक को दी जाए।

इसी तरह से बजट भाषण के क्रम संख्याः 20 में एक नई योजना "मुख्य मंत्री लोक भवन" बारे जिक्र किया गया है जिसके लिए 30 लाख रुपये देने की बात कही गई है। यह बहुत अच्छी स्कीम है और इसमें दो भवनों का निर्माण हो सकता है। उपाध्यक्ष जी, इसके साथ ही मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि हम चुने हुए विधायकों के लिए भी सचिवालय में एक भवन होना जरूरी है। मंत्रियों के लिए वहां कमरे उपलब्ध हैं लेकिन जब

कोई विधायक सचिवालय में जाता है तो उसके बैठने के लिए मेज़-कुर्सी तक उपलब्ध नहीं है। आप एस0डी0एम0 ऑफिस चले जाएं या तहसील के किसी ऑफिस में चले जाएं, हर किसी के पास कुर्सी-मेज़ है लेकिन विधायकों के लिए अभी तक सचिवालय में कोई सुविधा नहीं है। हम जब सचिवालय में जाते हैं तो देखते हैं कि मंत्रियों के कमरों में लोगों की भीड़ लगी होती है और हम वहां गलियारों में घूमते रहते हैं क्योंकि हमारे लिए वहां बैठने के लिए कोई प्रौपर व्यवस्था नहीं है। मेरा सुझाव है कि सचिवालय में एक भवन या एक बड़ा हॉल विधायकों को बैठने के लिए होना चाहिए।

**13/03/2018/1525/MS/DC/2**

जो "विधायक क्षेत्र विकास निधि" की राशि को 1.25 करोड़ रुपये बढ़ाया गया है उसकी हम तारीफ करते हैं। यह एक बहुत बढ़िया कदम है। क्रम संख्या-27 पर "सिंचाई पर बल" का जिक्र किया गया है यह भी बहुत ही अच्छा कदम है। इसमें जो सौर पम्प की बात की गई है यह भी बहुत सराहनीय कदम है। जहां बिजली उपलब्ध नहीं है वहां पर सौर पम्प इन्स्टॉल करना उन क्षेत्रों के लिए अच्छा रहेगा। यह इस सरकार द्वारा उठाया गया बहुत ही बढ़िया कदम है।

इसी तरह से क्रम संख्याः 36 में "मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना" के बारे में कहा गया है कि इसके तहत सौर बाड़ लगाई जाएगी और इसके लिए जो बजट का प्रावधान है वह 35 करोड़ रुपये रखा गया है। मैं नहीं समझता कि 35 करोड़ रुपये में आप किसी क्षेत्र को कवर कर पाएंगे। इसके लिए अधिक बजट का प्रावधान होना चाहिए। जो हम आवारा पशुओं और बंदरों की बात कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश बहुत बड़ा है इसलिए 35 करोड़ रुपये में ये काम नहीं हो सकता है। इसलिए इसके बजट को बढ़ाना चाहिए और ज्यादा-से-ज्यादा क्षेत्रों को कवर करना चाहिए।

क्रम संख्या-51 में लिखा गया है कि "प्रदेश में जलाश्य प्रबन्धन में मत्स्य बीज संग्रहण तथा प्रभावी संरक्षण" पर जोर दिया जाएगा। मेरा सुझाव है कि जो हैचरीज हैं उनकी हिमाचलियों के लिए शुरुआत करनी चाहिए जिससे यहां के युवाओं को रोज़गार मिले। ये जो हैचरीज हैं ये डैम के किनारे होनी चाहिए।

13.03.2018/1530/जेके/एचके/1

**होशयार सिंहः--------जारी--------**

अब जो सीड्ज़ आप लाते हैं उसको आप दूसरे राज्यों से इम्पोर्ट करते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि वह सीड यहां पर आते-आते 70 प्रतिशत मर जाता है। वह सीड जब डैम में डाला जाता है, उससे फिशिज़ नहीं होती क्योंकि वह 70 प्रतिशत खत्म हो चुका होता है। ये जो हेचरीज़ हैं ये डैम के किनारे खोली जानी चाहिए और यहां के युवाओं को इन हेचरीज़ के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फिशरमैन्ज़ का 3 से 4 महीने सीज़नल काम होता है बाकी समय ये बेरोज़गार रहते हैं। मैं यहां पर सुझाव दूंगा कि फिशरमैन्ज़ को फिशिंग टूरिज्म में जोड़ा जाए और उनकी जो नाव हैं, उन्हें आप शिकारा में कन्वर्ट करें, क्योंकि शिकारा और फिशिंग बोट में ज्यादा फ़र्क नहीं है। फिशिंग टूरिज्म का नाम दे करके इसे भी प्रोत्साहित किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए इम्प्लॉयमैंट जनरेट होगा और स्टेट के लिए भी रेवन्यू जनरेट होगा। यह मेरा सरकार के लिए सुझाव है।

प्वाइंट नम्बर-59 में कहा गया है कि मोक्ष धाम की हर पंचायत में कन्स्ट्रक्शन की जाएगी लेकिन इसके लिए बजट का कोई प्रावधान नहीं है। मोक्ष धाम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हर पंचायत में हम देखते हैं कि जब हम किसी डैड बॉडी को ले जाते हैं तो वहां कोई रास्ता नहीं होता और डैड बॉडी को कई जगह 10 बार नीचे रखा जाता है। अधिकतर शमशान फोरैस्ट लैंड पर है। सरकार फोरैस्ट डिपार्टमैंट से इस मोक्ष धाम के लिए बजट उपलब्ध करवाएं और हर मोक्ष धाम की कन्स्ट्रक्शन फोरैस्ट डिपार्टमैंट करें। उसमें सड़कों की मुरम्मत भी फोरैस्ट डिपार्टमैंट करें। उस मोक्ष धाम में ऐसा प्रोविज़न हो कि जहां पर लकड़ी रखी जाती है, जैसे एक डैड बॉडी को तीन क्विंटल लकड़ी लगती है तो उसका रिकॉर्ड रखा जाए, जिससे कि जो वन माफिया है, जो एडवांटेज लेता है, कई बार गाड़ी पकड़ी गई तो वे बोलते हैं कि शमशान को लकड़ी ले जा रहे हैं और वे बच जाते हैं। इस तरह से वह menace भी रोका जाएगा और वनों में लकड़ी का कन्ट्रोल भी रखा जाएगा। यह सुझाव है कि जो

**13.03.2018/1530/जेके/एचके/2**

भी wood stock should be kept in the record. मोक्ष धाम के कार्य हेतु सरकार बजट दें और इस कार्य को जल्द से जल्द शुरू करें।

क्रम संख्याः 63 में कहा गया कि फोरैस्ट डिपार्टमैंट चीड़ पत्तियों पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करेगा और 50 प्रतिशत उसके प्लांट एवं मशीनरी के लिए अनुदान प्रदान करेगा। लेकिन यह चीड़ पत्तियों पर आधारित उद्योग क्या है? What is that? फोरैस्ट डिपार्टमैंट को खुद एक बायो मास पावर प्लांट की इन्स्टॉलेशन करनी चाहिए। जैसे कि बताया गया कि 60 से 67 परसेंट फोरैस्ट लैंड है और फोरैस्ट वेस्ट इतना ज्यादा है कि जिसकी कोई कमी नहीं है और as per Indian institute of Science Bangalore, ये दर्शाया गया है कि हिमाचल में 450 मैगावाट बिजली का पोटैंशियल थ्रू बायो मास है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज दिन तक हमने एक मैगावाट बिजली भी नहीं बनाई। यह जो बायो मॉस का प्रोजैक्ट है सरकार इसको पायलट बेस पर बनाएं और बिजली बनाने से सरकार को रेवन्यू आएगा और पाइन कलैक्शन होगी। लैंटाना का जो menace है, लैंटाना जंगलों से निकाला जाएगा और जो वेस्ट वुड है, वह यूज़ होगी। सरकार को बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार और रेवन्यू प्राप्त होगा।

प्वाइंट नम्बरः 80 में कहा गया है कि "to promote industry and tourism" but to promote industry and tourism lot of changes are required in the policy .हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि टूरिज्म जहां है, वहीं थमा हुआ है। वे ही पांच इलाके कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, शिमला और कोई नया क्षेत्र अभी तक टूरिज्म के लिए नहीं आया। तो सरकार का जो इनिशियेटिव है यह बहुत अच्छा है। They will promote industry and tourism but they have to make a policy at the earliest , so that

private investors are called and new sources of revenue are generated in this industry.

**13.03.2018/1535/SS-HK/1**

**श्री होशयार सिंह क्रमागतः**

प्वाइंट नं0-85 में कहा गया है कि बिडिंग ऑफ माइनिंग का प्रोसैस ऑन लाइन किया जायेगा। मेरा मानना है कि आप कितना भी कर लो, जो भी बिडिंग माइनिंग के रिलेटिड होती है वहां पर घोड़े वाले हैल्पर, चाय वाले सारे पहुंच जाते हैं और उनके हाथ में 10-10, 20-20 लाख के ड्राफ्ट होते हैं और सारे डमी होते हैं और जो एक्चुअल होता है वह पर्दे के पीछे होता है। यह बहुत बड़ा स्कैम/रैक्ट है, जिसे आज दिन तक कोई छू नहीं सका। इसमें बहुत सारे लोग इंवोल्वड हैं। अगर इस menace को आपको हटाना है तो हर बिडिंग में आपको एक क्लॉज डालना है वह है आई0टी0आर0, Income Tax Return of the person who is participating in the bidding and his net worth कि उसका नैट वर्थ क्या है। अगर वह एक करोड़ की माइनिंग में पार्टिसिपेट करता है और उसका नैट वर्थ सिर्फ दो लाख रुपये का है तो how can he participate in that bidding? He cannot participate. आज हिमाचल में हाइड्रो प्रोजैक्टस क्यों फेल हुए उसका मुख्य कारण एक था कि 10 लाख वाले को प्रोजैक्ट मिल गया और जो 10 करोड़ वाला था उसे प्रोजैक्ट नहीं मिला। यह सबसे मुख्य कारण failure of the industry and hydro projects in Himachal Pradesh था। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अंदर बहुत गहराई है। आप सोचें और इस बारे में नई पॉलिसी बनाएं, जिसमें ITR and net worth certificate is must और उसी को प्रोजैक्ट मिलना चाहिए जिसका नैट वर्थ 25 से 30 परसैंट हो। He is only eligible to take that project. नहीं तो बैंक भी कर्जा नहीं देता है। जो प्रोजैक्ट 10 करोड़ का है और आपका नैट वर्थ 10 लाख का है तो कौन-सा बैंक आपको लोन देगा? कोई बैंक आपको लोन नहीं देगा और वह 10 लाख का प्रोजैक्ट एक से दो, दो से तीन, तीन से चार साल शिमला के गलियारों में बिकता है। पांच साल से नहीं बल्कि दस साल से बिक ही रहा है। मेरा यह सुझाव है कि जब भी कोई पॉलिसी बने तो उसमें आई0टी0आर0 एंड नैट वर्थ सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी हो।

प्वाइंट नं0- 91 में कहा गया है that government will identify the virgin sites for the development of the tourism. मेरा सुझाव है कि a District Tourism Officer of District Kangra जिसके अंडर 15 कांस्टीचुऐंसीज़ हैं क्या वह अकेले कैपेबल है to find the sites? इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है जिसमें 15 कांस्टीचुऐंसीज़ हैं, हम भी जब अपनी कांस्टीचुऐंसी में घूमते हैं तो एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए पांच दिन लग जाते हैं

**13.03.2018/1535/SS-HK/2**

तो क्या a District Tourism Officer is capable to find the virgin sites? No. It is not possible. यह होना असम्भव है। यह सम्भव तभी है जब कांस्टीचुऐंसी का लोकल एम0एल0ए0 साइट्स फाइंड आउट करे। लोकल एम0एल0ए0 पांच साइटें दे और उन साइटों को कमेटी जल्द-से-जल्द वैरीफाई करे और उसे आइडेंटीफाई करके इको टूरिज्म या जिस मर्जी टूरिज्म में लाना चाहे तो ला सकती है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में अकेला टूरिज्म ऑफिसर नहीं कर सकता। हजारों साइटें हैं लेकिन वह ऑफिसर वहां पहुंच ही नहीं सकता। For that a policy is to be framed, जिसमें लोकल एम0एल0ए0 की डयूटी होनी चाहिए कि वह वर्जिन साइट्स को सरकार तक पहुंचाए बजाय कि टूरिज्म ऑफिसर। यह मेरा एक छोटा-सा सुझाव है।

सर, प्वाइंट नं0-92 में हैली सर्विसिज़ के बारे में कहा गया है। ये हैली सर्विस कई वर्षों से सुन रहे हैं। जबकि हैली सर्विसिज़ का बहुत बड़ा पोटैंशल है। शिमला टू मनाली, मनाली टू धर्मशाला अगर यह हैली सर्विस शुरू होती है तो मुझे लगता है कि टूरिज्म में चार चांद लगेंगे और हिमाचल सरकार को बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा।

Point No. 94 - There is a huge potential for bird watching. --(व्यवधान)-- सर, स्पीड तो ठीक है, हम तो पहली बार ही आए हैं।

**13.03.2018/1540/केएस/वाईके/1**

**उपाध्यक्षः** माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप करें।

**Shri Hoshyar Singh:** Point No. 94, there is the huge potential for birds watching. इतने पंछी आते हैं। लाखों के हिसाब से यहां साइबेरियन बर्डज़ आते हैं लेकिन आज दिन तक किसी बर्डज़ वॉचर के लिए एक बैंच या कुर्सी भी नहीं है कि वह किनारे पर बैठ कर बर्डज़ वॉच कर सके या फोटोग्राफी कर सकें। इसके लिए सरकार इनिशियेटिव लें इससे भी इम्प्लॉयमैंट जेनरेशन और रेवन्यू जेनरेशन का फायदा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, पौंग डैम में कई ऐसे स्थान हैं जैसे बाथू टैम्पल जहां पर स्कूबा डाइविंग जैसी सुविधा चालू की जा सकती है, यह भी इन्कम का बहुत बड़ा सोर्स है for income and the revenue generation of the State.

प्वाइंट नम्बर-95 में रोपवे की बात की गई। आप काश्मीर में जा कर देखिए कि रोपवे कैसा होता है। हमारे यहां कोई ऐसी साइट्स आइडैंटिफाइड नहीं है। परन्तु एक साइट आइडैंटिफाइड है, जहां 12 महीने बर्फ होती है और वह है त्रियूंड के ऊपर का इलाका। वहां ग्लेशियर हैं और 12 महीने बर्फ होती है। यदि सरकार वहां पर रोपवे लगाएं तो टूरिज्म का बहुत बड़ा प्वाइंट हो सकता है।

Point No. 99 is a very good idea of this Government to start a skill development और विशेषकर इंगलिश स्पीकिंग। इंगलिश स्पीकिंग की हमारे राज्य में बहुत कमी है जिसके कारण हमारे एम.बी.ए. के स्टूडैंट, नर्सिज़, डॉक्टर्ज़, होटल मैनेजमैंट के स्टूडैंट्स पीछे रह जाते हैं तो सरकार ने स्किल डवैल्पमैंट का जो फैसला लिया है, यह बहुत सराहनीय है। It should be developed at the earliest. सबसे अच्छा प्वाइंट है that is mechanism of third party inspection जो कि बहुत अच्छा प्वाइंट लिया गया है। क्योंकि आजकल जो हमारी सड़कों की दुर्दशा है, उसका कारण यह है कि no inspection, no responsibility and no accountability. यह थर्ड पार्टी इन्सपैक्शन का काम शुरू होता है तो पी.डब्ल्यू.डी. में जड़ से करप्शन खत्म हो जाएगी। अगर इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाता है। यह सरकार का बहुत अच्छा स्टैप है।

**13.03.2018/1540/केएस/वाईके/2**

उपाध्यक्ष महोदय, प्वाइंट नं0- 111 पर टनल्ज़ के बारे में लिखा गया है। मैं सोचता हूं कि टनल्ज़ के माध्यम से चम्बा से धर्मशाला का डिस्टैंस शॉर्ट किया जाए क्योंकि यह बहुत लम्बी दूरी है और सरकार इसके बारे में सोचें और प्रपोज़ल दें।

प्वाइंट नं0-129 पर इन्डोर कॉम्पलैक्स के बारे में कहा गया है। इसमें जिला स्तर पर कहा गया है लेकिन मैं कहूंगा कि यह कन्स्टिट्युअंसी लैवल पर होना चाहिए। क्योंकि कन्स्टिट्युअंसी के ऐसे भी गरीब बच्चे हैं जो डिस्ट्रिक्ट लैवल तक नहीं पहुंच सकते। और ये इन्डोर कॉम्पलैक्स बच्चों के लिए हर कन्स्टिट्युअंसी में होने चाहिए। जिससे हमारा स्पोर्ट्स आगे बढ़े। A very important and special point which I would like to discuss in the last is, a special assistance is to be provided to the kidney transplant and the cancer cases. सर, आज मेरे चुनाव क्षेत्र में 15 केस ऐसे हैं जो कि बहुत ही गरीब हैं और किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है, उनके पास दवाइयों के पैसे नहीं है और एक महीने की दवाई का खर्चा 15 हजार रुपये हैं। 15 हजार वे घर-घर जा कर मांगते हैं तो सरकार इस पर सोचे। किडनी और कैंसर पेशेंट्स के लिए दवाइयों का प्रावधान करें। ज्यादा केसिज़ नहीं है। (व्यवधान) लेकिन वह दवाइयों के लिए नहीं है । ऑप्रेशन और दवाइयों के लिए उसके अंदर सिर्फ 30 हजार हैं केवल।

**उपाध्यक्षः** कृपया बीच में इंटरप्ट न करें। माननीय सदस्य कृपया आप वाइंड अप करें।

**श्री होशयार सिंहः** उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मुद्दा है जिस पर सरकार गौर करें। खासकर जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है।

मेरा आखिरी प्वाइंट यही है कि मेरे चुनाव क्षेत्र देहरा से हर बार भेदभाव हुआ है। पिछली सरकार के समय में बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ है और अगर मैं उसके बारे में कहने लगूं तो पूरा दिन लग जाएगा, बात खत्म नहीं होगी लेकिन मैं ज्यादा विस्तृत न कहते हुए यही चाहूंगा कि अब की बार जो सरकार है यह भेदभाव न करें और देहरा की प्रोग्रैस में रुकावट न आए और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद । मैं इस बजट का पूरा समर्थन करता हूं। यह बहुत ही अच्छा बजट है, धन्यवाद।

**13.3.2018/1545/av/yk/1**

**श्री बिक्रम सिंह जरयाल :** आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

हिमाचल प्रदेश के ऊर्जावान मुख्य मंत्री जय राम ठाकुर जी ने जो 9 मार्च, 2018 को हिमाचल प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया है यह बहुत सराहनीय, ऐतिहासिक और हर वर्ग को फायदा देने वाला बजट है। इसमें कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहा। यह गरीब हित, मजदूर, कर्मचारी वर्ग, किसान-बागवान, व्यापारी, अधिकारी, महिलाओं, युवाओं और जनता के प्रतिनिधियों के मन को लुभाने वाला बजट प्रेषित किया गया है। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

विपक्ष के नेता माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी ने भी इस बजट के लिए मन से धन्यवाद किया है। बाहर जनता से चर्चा की है कि बहुत अच्छा बजट है, सराहनीय है परंतु सदन में इन्होंने एक रस्म को निभाया है। प्रदेश का हर वर्ग इसको पारदर्शी व एक अच्छा बजट कह रहा है। मैं इसके बारे में अखबारों में पढ़ रहा हूं, जनता से इस बारे में बातचीत करते हैं। यह बजट ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि इसमें सुशासन की मदद से बेहतर सेवाएं प्रदान करने की बात कही गई है। खेती-बागवानी के आर्थिक रूपांतरण की बात कही गई है जिसमें कृषकों की आय दोगुनी हो सके। युवा वर्ग के लिए रोजगार सृजन, प्रभावी कानून-व्यवस्था की बहाली, सभी बेघरों को घर, ड्रग्स, खनन एवं वन माफिया के ऊपर नियंत्रण, प्रभावी एवं सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, गुणवत्ता आधारित शिक्षा प्रदान करना, महिला सशक्तिकरण यानि इसमें हरेक चीज/वर्ग के लिए पहले से कई गुणा ज्यादा बजट रखा गया है। शिक्षा के क्षेत्र की बात हो रही थी और इस बारे में यहां पर मेरे से पहले लगभग सभी वक्ताओं ने बात की है। मैंने इस बारे में एक प्रश्न भी लगाया था कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में या चुनाव के दिनों के नजदीक कितनी शिक्षा संस्थाओं को खोला/अपग्रेड किया गया। मैं यहां पर अपने विधान सभा क्षेत्र का जिक्र करना चाहता हूं। चुनाव के दिनों के नजदीक मेरे विधान सभा क्षेत्र में 17 शिक्षण संस्थानों

**13.3.2018/1545/av/yk/2**

को अपग्रेड किया गया। शिक्षा की गुणवत्ता कहां से आयेगी? मैं जहां-जहां गया वहां न कमरों की व्यवस्था थी, न वहां पर अध्यापकों की नियुक्ति थी और न ही कोई इनफ्रास्ट्रक्चर था। मेरे पास उन स्कूलों के लिए लगभग 56 कमरों की डिमाण्ड आई है। वहां पर कन्या पाठशाला में एक गवर्नमैंट डिग्री कालेज खोला गया। उसके लिए बजट, इनफ्रास्ट्रक्चर और अध्यापकों की कोई व्यवस्था या नियुक्ति नहीं की गई। उस कालेज के लिए प्रीवियस गवर्नमैंट ने जो स्थान का चयन किया है वह स्लाईडिंग एरिया है और वहां के लिए रोड कनैक्टिविटी भी नहीं है। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि उस स्थान को डीनोटिफाई किया जाए और एक ऐसे स्थान का चयन किया जाए जहां पर उस कालेज का अच्छा भवन बन सके क्योंकि बाद में वह पोस्ट ग्रेजुएट बनेगा। इन सभी चीजों को देखते हुए वह कालेज एक अच्छी जगह बनाया जाए, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से ऐसा आग्रह करता हूं।

**13.3.2018/1550/TCV/AG-1**

**श्री बिक्रम सिंह जरयाल ...... जारी**

कई स्कूल ऐसे हैं, वहां पर प्राइमरी स्कूल है नहीं और मिडल स्कूल कर दिए। मेरी ग्राम पंचायत बगडार के खुईं गांव में प्राइमरी स्कूल नहीं है, वहां पर मिडल स्कूल खोल दिया। स्कूल बंद करने की बात नहीं है। ये बात है,व्यवस्था की। हम उनको चलाएंगे। लेकिन समय लगेगा। फटे टांग दिए, लेकिन टीचर नहीं है। रंगड और खुईं में मिडल स्कूल खोल दिया। बगडार में +2 का स्कूल है। वहां से एक टीचर इधर आता है और एक उधर जाता है। न पढ़ाई, खुईं में होती है, न बगडार में और न रंगड स्कूल में। मैं आदरणीय मोदी जी और केन्द्र सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पिछड़े जिलों का सर्वेक्षण किया और 115 जिले पिछड़े नोटिफाई किये हैं। हिमाचल प्रदेश में जिला चम्बा को पिछड़ा जिला का दर्ज़ा

मिला है। उसमें बज़ट का भी काफी प्रावधान है। इसमें शिक्षा के लिए 30 परसेंट,स्वास्थ्य के लिए 30 परसेंट, इंफ्रास्ट्रैक्चर के लिए 12 और एग्रीकल्लचर के लिए 10 परसेंट बजट का प्रावधान रखा गया है। इसका काम भी जिला चम्बा में अतिशीघ्र शुरू होने वाला है। मेरी बड़ी बहन श्रीमती आशा जी भी यहां पर बैठी है, पिछले 5 सालों में चम्बा में कोई भी नया काम नहीं हुआ। जहां तक सड़कों की बात है, 5 वर्षों में किसी एक भी सड़क की डी0पी0आर0 तैयार नहीं की गई। यदि विधान सभा में कोई प्रश्न लगाते थे, तो जवाब आता था, सूचनायें प्राप्त की जा रहीं हैं। लेकिन 5 साल खत्म हो गये, हमें सूचना ही नहीं मिली। ---(व्यवधान)--- मैं धन्यवाद करता हूं, लेकिन सूचनायें नहीं दी। सड़क के लिए जो पैसा आता था, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक सड़क है, चवाड़ी- वाया जोत चम्बा। पिछली सरकार के दौरान 2016 में टारिंग के लिए लूक-बज़री और बालण आया। लेकिन लोक निर्माण विभाग ने बेच दिया। मैंने विधान सभा में प्रश्न किया, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं हुई। उस एस0डी0ओ0 को एक्सीयन बनाकर भरमौर भेज दिया। उसकी प्रमोशन कर दी। ऐसे ही एक पुल का शिलान्यास आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी ने किया था, वह पुल बनकर तैयार हो गया। उसमें भी एक जे0ई0 ने 32 लाख का घोटाला किया। मैंने यहां विधान सभा में प्रश्न लगाकर मामला उठाया। लेकिन उस जे0ई0 को प्रमोट कर कहीं और भेज

13.3.2018/1550/TCV/Ag-2

दिया। मैंने जो सूचनायें प्राप्त की थी, वह मैंने ऑडिट डिपॉर्टमैंट से ली थी। उन्होंने मुझे बताया था कि इस पुल में 32 लाख का घोटाला हुआ है। ऐसा ये 5 साल करते रहे। मैं आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, अभी तक बिल्डिंग्ज़ तो बनी नहीं हैं, परन्तु 'स्वस्थ भारत मिशन' के तहत हरेक स्कूलों में शौचालय काफी बन चुके हैं।

हैल्थ के बारे में मैंने पहले इसी विधान सभा में प्रश्न किया था, फटे लटका दिए, मैडम (श्रीमती आशा कुमारी) तो वाकिफ़ है, पहले वह इलाका इनका था। लेकिन परिसीमन के बाद वह मेरे चुनाव क्षेत्र में आ गया। मैल में पी0एच0सी0 और

13-03-2018/1555/NS/AG/1

श्री बिक्रम सिंह जरयाल -------जारी।

चुहण में पी0एच0सी0 को कोई बजट नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई डॉक्टर और नर्स नहीं है। वहां पर कोई चपरासी भी नहीं है। आज अगर मैं वहां जाता हूं तो वहां के लोग मुझे पूछते हैं कि आप पी0एच0सी0 कहां बना रहे हैं? वहां फट्टा बहुत बड़ा लटका दिया है और नाम भी लिख दिया है। उनका मैंने क्यों नाम लेना कि किसने किया है? मैंने वहां पर एक से हाथ जोड़ करके किराये पर कमरा लिया है और उस कमरे में मेल की पी0एच0सी0 चलाई है। चुहण की पी0एच0सी0 के लिए अभी तक कमरा भी नहीं मिला है। मेल में एक डॉक्टर बैठता है। मैंने आदरणीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से आग्रह किया था तो इन्होंने एक डॉक्टर वहां के लिए दिया है। लेकिन चुहण में जगह नहीं है। वहां पर सब-हैल्थ सैंटर किराये के कमरे में चला हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं यहां पर सडकों के बारे में बोलना चाहूंगा। सड़क की क्या बात करनी, यहां पर हमारे पूर्व मुख्य मंत्री जी बैठे हैं और इन्होंने उद्‌घाटन किये लेकिन उन सड़कों के काम नहीं हुए हैं। बगड़ार से छणूह रोड पर बहुत बड़ा फट्टा लगा है, बहुत अच्छा नाम लिखा है लेकिन सड़क का काम शुरू नहीं हुआ है। खूंई रोड का फट्टा लग गया है लेकिन वहां अभी तक कोई गाड़ी नहीं जाती है। आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी जब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने इस सड़क का काम शुरू करवाया था। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सब-डिवीज़न मुख्यालय चुवाड़ी है लेकिन वहां पर जाने के लिए उचित रास्ता नहीं है। मैंने अभी उस रास्ते का काम लगवाया है। वहां पर आर0सी0सी0 की दीवार लग रही है। पूर्व सरकार में वहां पर हैलीपेड की घोषणा हुई थी। वहां पर बहुत बड़ा फट्टा लगा है और माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी का वहां पर नाम लिखा हुआ है। मैं चुवाड़ी हैलीपेड के लिए इनका धन्यवाद करता हूं। वहां के लोग मुझे बोलते हैं कि हमें सारी रात सोने नहीं देते हैं

क्योंकि यहां पर रोज हैलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ आते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र की ऐसी हालत है।

अस्पतालों में डॉक्टर्ज़ नहीं हैं और न ही अन्य स्टॉफ है। अगर मशीनें हैं तो पैरा मैडिकल स्टॉफ नहीं है, मशीनें धूल फांक रही हैं और उनको चलाने वाला कोई नहीं है। पूर्व सरकार वाले कहते हैं कि हमने पांच वर्ष में क्षेत्र का बहुत विकास किया है। अब मैं वैटरनरी की बात करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी और प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी का

13-03-2018/1555/NS/AG/2

धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने समय में हरेक पंचायत में पशुधन औषधालय खोला था। लेकिन पिछली सरकार के समय में इसके लिए एक कमरा भी नहीं बना है। कई औषधालय अभी भी प्राईवेट कमरों में चल रहे हैं। इसके लिए ज़मीन भी विभाग के नाम हो चुकी है और मैंने कई बार आदरणीय पूर्व मुख्य मंत्री जी को लिख करके दिया था और साथ में ज़मीन के कागज़ात लगा करके भी दिये थे। परन्तु एक भी औषधालय नहीं बना। एक फट्टा समौट में जरूर लगा है क्योंकि यह डिस्पैंसरी मैंने एक दुकान में खोली है। वेटरनरी अस्पताल का फट्टा लगा जरूर है पर वह बना नहीं है। इसके लिए जगह नहीं है और यह दुकान में चली हुई है। हमारे वरिष्ठ नेता माननीय नेगी जी बाहर चले गये हैं। वे बड़े गर्मजोशी से बता रहे थे कि पांच साल हमने ऐसा किया और वैसा किया। पांच साल में इनको कोई याद नहीं आई, यह सोये रहे और अब नींद खुली तो वहां से बोलना शुरू कर दिया कि यह नहीं हुआ और वह नहीं हुआ। इन्होंने स्कूलों के बारे में बहुत लम्बा भाषण दिया है। इन्होंने सेना के ऊपर भी एक-दो टिप्पणियां की हैं। मैं उनका उत्तर देना चाहता हूं। यहां पर बताया गया था कि एक मैंटल स्कूल/अस्पताल खोला गया है। आप बुरा मत मानिये क्योंकि इस सरकार में कोई मैंटल नहीं है, पिछली सरकार में कोई होगा इसलिए ज्यादा स्कूल खोल दिये होंगे। इन्होंने यहां पर सेना के लिए भी कहा है। मैं इनको बींग ए सोलज़र बताना चाहता हूं कि जब आदरणीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी प्रधान मंत्री थी तो मुझे याद है उन्होंने केबिनेट में एक निर्णय लिया था कि रविवार को सैनिकों को खाना-पीना और तनख्वाह नहीं दी जायेगी। उस समय हमारी सेनाओं के जो तीनों ज़नरल थे, उन्होंने कह दिया था कि अगर रविवार को हमारे देश के ऊपर कोई दूसरा देश हमला

करता है तो हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। इन्दिरा गांधी जी कहती कि फिर क्या होगा? उन्होंने बोला फिर देश गुलाम हो जायेगा। तब जा करके इन्दिरा जी की आंखें खुली।

13.03.2018/1600/RKS/DC-1

श्री बिक्रम सिंह जरयाल... जारी

मैं आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का धन्यवाद करता हूं, जो पूर्व में हमारे प्रधान मंत्री रहे हैं। मैं श्रीलंका में अढाई साल तक रहा हूं। वहां पर जब कोई फौजी मर जाता था तो उसकी डैड बॉडी को गाड़ी के टायरों से जलाया जाता था। अटल जी ने इसके लिए एक अच्छा स्टैप लिया है। आज हमारा भाई कहीं देश के लिए शहादत देता है तो उसकी डैड बॉडी सम्मान के साथ घर आती है। सम्मान के साथ उसका दाह-संस्कार होता है। मैं आदरणीय मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने भी बहुत बड़ा स्टैप लिया है। हम लोग रोते रहे कि 'वन रैंक, वन पैंशन' करो परन्तु किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। आदरणीय मोदी जी ने सत्ता में आते ही 'वन रैंक, वन पैंशन' लागू किया और आर्मी से रिटायर्ड लोगों, उनके परिवारों और विधवाओं को इसका फायदा हुआ। आपको फिगर एंड फैक्ट्स के साथ बातें करनी चाहिए। (घंटी..) आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं।

यहां पर माननीय सदस्य जी ने आर.एस.एस. की बात की। आपको आर.एस.एस. से डर क्यों लग रहा है? मुझे लग रहा है कि पूरे हिन्दुस्तान में कॉंग्रेस का सफाया हो रहा है इसलिए आपको सारी जगह आर.एस.एस. दिखाई दे रहा है। आप इतना क्यों डर रहे हो? अभी हाल ही में तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। आप भी अच्छे कर्म करो तभी आप इस तरफ आ सकते हैं।

मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सोलर फैंसिंग के लिए 85 परसैंट उपदान दिया है। आदरणीय सदस्य श्री होशयार सिंह जी कह रहे थे कि जिन दूर-दराज क्षेत्रों में बिजली नहीं है, खेत खलिहान दूर है, वहां पर सोलर फैंसिंग

के लिए 85 परसैंट उपदान दे रहे हैं। इससे किसानों की फसल भी बचेगी और साथ ही बरसात में जो घास तैयार होता है, उस फैंसिंग के साथ वह भी खत्म हो जाएगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

13.03.2018/1600/RKS/DC-2

हमारे 80 प्रतिशत लोग खेती के ऊपर निर्भर हैं। पीने के पानी की बात पहले भी चर्चित हो चुकी है। आप कह रहे हैं कि लोगों को बहुत अच्छा पीने का पानी दिया गया। कई लोगों की मृत्यु पीलिया से हो गई। टैंकों में नर-कंकाल पाए गए। शिमला में सफाई के नाम पर 80 करोड़ रुपये किसी ठेकेदार को दिए गए परन्तु उसने एक भी पैसा खर्च नहीं किया। कागज़ों में ही सफाई होती थी और जेबों की गरमाई होती थी। मैं किसी का नाम तो नहीं ले हो सकता हूं परन्तु हो सकता है कि इसमें सब मिले हों। जो भारतीय जनता पार्टी के समय में पीने के पानी की स्कीमें बनी या सिंचाई की स्कीमें बनी उन स्कीमों की मरम्मत भी आप पिछले पांच सालों में नहीं करवा सके। नई स्कीमें खोलना तो दूर की बात थी।

हैंड पंप रिपेयर घोटाला। कागजों में रिपेयर, ग्राउंड में हैंडपंप फेल। पिछले टर्म में आई.पी.एच., विभाग में जो बड़े-बड़े अधिकारी थे उन्हें भी कोई नहीं पूछता था। पिछले पांच सालों में मैंने पीने के पानी या सिंचाई की जो डी.पी.आर्ज. दी, वे एक भी नहीं बनाई गई। अगर डी.पी.आर्ज बनाकर दे देते तो आदरणीय मोदी जी पैसा दे देते और लोगों की इसकी सुविधा मिल जाती। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो स्कीमें वर्ष 1999 या वर्ष 2000 में बनी थी, वहां पर फट्टे लगा दिए गए कि वर्ष 1999 या वर्ष 2000 की स्कीमें बनकर तैयार हो गई। उनकी पाइपें जगह-जगह टूट रही है और पानी बह रहा है। लेकिन फट्टा लगा दिया गया कि हमारा नाम दिखता रहे। परन्तु काम नहीं दिखा क्योंकि 5 साल में ग्राउंड में तो काम हुआ ही नहीं। भाई नेगी जी एक बात बड़े जोर-शोर से कह रहे थे- 'कौशल विकास भत्ता, कौशल विकास भत्ता।' मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार थी तो एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., के लोग जब किसी चीज़ के लिए प्रशिक्षण लेते थे तो उनको

स्कोलरशिप दी जाती थी। उसी चीज़ को आप लोगों ने कौशल भत्ते में डाइवर्ट कर दिया और नाम दे दिया गया 'कौशल विकास भत्ता'। आपने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा कि जो बेरोज़गार,पढ़े-लिखे युवा हैं उनको रोज़गार दिया जाएगा।

**13.03.2018/1605/बी0एस0/डी0सी-1**

**श्री बिक्रम सिंह जरयाल .....जारी**

आप सत्ता में आ गए, कुर्सी में बैठ गए और उनको अंगुठा दिखा दिया, आप कौन और हम कौन । आपने सिर्फ बेरोजगारों को लुभाया। उसके बाद जब बेरोजगारों की बारी आई तो उन्होंने आपको अंगुठा दिखा दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने लोगों की पॉकेटस गर्म करने के लिए इन्होंने कई बिवरेजिज लिमिटिड खोल रखे थे । मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय मोदी जी का आते ही उस लिमिटिड को खत्म कर दिया। जिससे की एक पैसा का रेवेन्यू नहीं आता था। ऐसी-ऐसी कई चीजें इन्होंने अपने लोगों को खिलाने के लिए की थी तभी तो इतना कर्ज बढ़ा।

गौ सदन पर इनको बहुत गुस्सा आ रहा है। एम्बुलेंस के बारे में विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि हमने यह सब किया, केन्द्र ने यह दिया। मुझे पता है अभी और भी बोलेंगे। यही कहेंगे की केन्द्र से 108 एम्बुलेंस आई, केन्द्र की यह स्कीम थी। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर आपकी सरकार के समय यह स्कीम आई तो आपने इसे क्यों नहीं शुरू किया? यह 108 हमारी सरकार ने अटल स्वास्थ्य योजना के नाम से शुरू की थी। आपने उसे भी बदल दिया। सिर्फ आप लोगों ने स्कीमों के नाम बदली किए और फट्टे लगाए और कुछ भी आपने पांच सालों में नहीं किया।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें।

**श्री बिक्रम सिंह जरयालः** अंत में उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बजट भाषण लिखा गया है इसके बारे में इन्होंने बोला कि आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने पढ़ करके सुना दिया। शायद

इन्होंने अच्छी तरह से नहीं पढ़ा होगा। जितने भी मेरे माननीय वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं, पूर्व मुख्य मंत्री जी भी बैठे हैं। उनसे आग्रह है कि वे इस बजट को अच्छी तरह से पढ़े। आप

**13.03.2018/1605/बी0एस0/डी0सी0-2**

लोगों ने पंचायती राज संस्थाओं को अपंग बना दिया था। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय का जिन्होंने पंचायती राज के लिए बजट का प्रावधान किया है। अब वो भी अपने थ्रू बजट का वितरण कर पाएंगे। मैं फिर से माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यववाद करूंगा कि इन्होंने पंचयत प्रतिनिधियों का मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। जो हमारे कर्मचारी/अधिकारी बैठे हैं उनको भी इस बजट में काफी फायदा हमरी सरकार ने दिया है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनको थोड़ा सा बताना चाहता हूं ये शायद भूल जाते हैं, थोड़ा ऐनक लगा करके अब बाताता हूं। जो योजनाएं आरणीय मुख्य मंत्री जी ने चलाई हैं वे इन्हें नहीं दिखती। दीन दयाल अंत्योदय योजना नहीं दिखाई देती, दीन दयाल ग्रामीण कौशल योजना, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना इनको ये दिखाई नहीं दे रही है मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। National Social Assistance Programme (NSAP), प्रधान मंत्री आवास योजना।

**उपाध्यक्षः** माननीय बिक्रम जी, कृपया समाप्त करें।

**श्री बिक्रम सिंह जरयालः** माननीय उपाध्यक्ष जी, सिर्फ दो मिनट। स्वच्छ भारत मिशन,नेशनल ड्रिंकिंग प्रोग्राम, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, डिजिटल इंडिया बहुत सी योजनाएं हैं। अगर मैं पढ़ने लग जाऊं तो सुबह हो जाएगी। इनको थोड़ा पढ़ो । तब आपके ध्यान में आएगा कि प्रदेश और देश का विकास हो रहा है। बाकी की काफी बातें हमारे माननीय सदस्यों ने कवर कर ली हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे थोड़ा समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इस बजट का मैं पूरे जोर-शोर के साथ समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

**13.03.2018/1605/बी0एस0/डी0सी0-3**

**उपाध्यक्षः** अब माननीय सदस्या श्रीमती आशा कुमारी जी चर्चा में भाग लेगीं।

**Smt. Asha Kumari:** Deputy Speaker, Sir, you have given me time to speak on the Budget Speech delivered by the Hon'ble Chief Minister, Shri Jai Ram Thakur Ji. I don't speak in English normally. But I don't want my learned younger brother Shri Rakesh Pathania Ji, where he has gone? He is missing.

He alternates from black and white and today he is in white. So I didn't realize where he is. I suppose he has made all these dresses to sit on that side. But unfortunately or fortunately he is with us here.---( interruption)--- I am very happy to have you here. Deputy Speaker, Sir, actually I don't think I should speak because this is a non serious Government

13.3.2018/1610/DT/एच.के.-1

**श्रीमती आशा कुमारी...जारी..**

यहां पर बजट पर चर्चा हो रही है और यहां पर न तो मुख्यमंत्री, न मुख्य सचिव, न वित्त सचिव मौजूद है। हम किस लिए चर्चा कर रहे हैं। खाली बैंचिज पड़े हुए हैं। अभी तक मैं देख रही थी कि किश्न कपूर जी पुराने मंत्री हैं वे अकेले यहां बैठे हुए हैं वरन् यह हाउस स्थगित हो जाता and you are singly sitting here. He came inside later. He also went out. I was noticing that. Please don't interrupt when I am speaking. Ok. You all were speaking we were not interrupting. I am simply pointing out you are so non-serious. उपाध्यक्ष जी हम किसको सुनाएं।

**उपाध्यक्षः** बीच में कोई भी माननीय सदस्य इंटरप्ट न करें। मैडम, आप आसन को सम्बोधित करते हुए अपनी बात कहें। माननीय मंत्री जी आप दोनों ही वरिष्ठ सदस्य हैं। (व्यवधान)

**श्रीमती आशा कुमारीः** I said at one stage he was singly sitting here. You are not here, you had gone out he had also gone out, you went out You were the last minister to go out. He was singly sitting here. I am simply pointing out that this is a non serious Government वैसे तो मुकेश अग्निहोत्री जी ने जो बातें रखी उसमें हमारी सारी बातें कवर हो गई है। इस बजट डाक्यूमैंट को देखते हुए

**(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)**

I am very happy that Speaker Sir has also come he is one of the highlights of this present House and I must compliment him the way he is conducting the House. इसलिए अध्यक्ष महोदय, ऐसा बजट का डाक्यूमैंट देखते-देखते बहुत साल हो गए। जो पर्टिकुलर डाक्यूमैंट है जिन लोगों ने इसको बनाया उन्होंने इतना भी नहीं किया कि इसमें पिछले डाक्यूमैंट से भिन्नता लाते। उन्हीं प्वाईंट्स को बदलकर नाम बदल दिए गए। यहां पर बैग्स की चर्चा हो रही थी कि पहली,तीसरी, नौंवी और ग्यारहवीं में बैग्ज देंगे। उसका नाम तो ठीक से रख देते। उसको वर्दी योजना कह दिया। वर्दी तो पहनने की होती

13.3.2018/1610/DT/एच.के.-2

है। बैग वर्दी का हिस्सा नहीं होता है। सुख राम जी आप एस.एम.सी. की भर्ती के बारे में बोल रहे थे। जो आपने कहा है, वह सच भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि कन्फ्यूजन क्यों है? आपने सुबह कहा कि सब गलत है परन्तु लंच ब्रेक में शिक्षा मंत्री उनका 20 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने पर बाजे-गाजे के साथ उन्हीं शिक्षकों से धन्यवाद ले रहे थे।.....( वयवधान)....

**अध्यक्षः** कृपया आपस में चर्चा मत करें।

**श्रीमती आशा कुमारीः** अध्यक्ष जी, इस बजट में कोई नया नहीं है। यह हर वर्ष की तरह रूटीन बजट है। हमारे ब्यूरोक्रेट्स को शेरो-शायरी लिखने का शोक जिस व्यक्ति की वजह

से पड़ा वह आज सदन में नहीं है। उनको यह शोभा भी देता था। उसका कारण भी था। वे मुख्य मंत्री माननीय धूमल जी थे। उनको शोभा इसलिए देता है कि वे शायरी के शौकिन थे। वे off the cuff शरो-शायरी बोलते थे। मगर फाइनैंस विभाग ने तो बजट दस्तावेज को शायरी लिखने का एक दस्तावेज बना दिया। चाहे वह हमारी सरकार थी, चाहे आपकी सरकार थी। वे वही लोग हैं जिन्होंने आपकी पिछली सरकार के बजट लिखे। हमारी सरकार के लिखे। श्री जय राम ठाकुर जी यहां पर नहीं है, वे यहां पर होते तो मैं उन्हें पहला बजट प्रस्तुत करने पर बधाई देती। it is his first Budget. Of course, he is yet inexperienced. But not so inexperienced also. He is fifth turn legislature. He has remained a minister. He is a senior Member of this House. So, he is not that inexperienced, as one would like to think.

**13.03.2018/1615/SLS-HK-1**

## श्रीमती आशा कुमारी ... जारी

पर जब हम इस बजट की किताब को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेसी इन पर हॉबी हो गई है। यहां पर बहुत चर्चा हुई। वह माननीय सदस्य यहां पर नहीं हैं। He speaks well but he is not here just now. I am talking about the young man from Sundernagar. Whatever his name may be. I never remember his name. But during the speech at Dharmashala on Governor's Address, उन्होंने दृष्टि पत्र की बात कही थी । लेकिन दृष्टि इसमें नज़र नहीं आ रही है। यह तो जो पुरानी घिसी-पिटी स्कीमें थीं, हमारी थीं, आपकी थीं और उससे पहले की भी थीं, उनमें ही किसी में 10 रुपये बढ़ा दिए, किसी में 20 रुपये बढ़ा दिए, किसी का नाम बदल दिया गया तथा किसी को कुछ और नाम दे दिया गया है। इसमें कोई दृष्टि नज़र नहीं आ रही है। दृष्टि नज़र आती, कोई नयापन नज़र आता तो हम उस बात का स्वागत करते और कहते कि हां, इसमें कुछ नयापन है, नई सोच आई है और इससे एक नए युग की शुरुआत होगी। यह बात तो तय है कि चाहे आप उधर बैठे हैं या हम इधर बैठे हैं, हम सब हिमाचल प्रदेश के हितैषी हैं। क्या यहां कोई ऐसा है जो यह नहीं चाहता कि हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े। With great pride

you were saying that some officials of Afganistan have come here from the Afganistan Parliament. Is that right?

**Hon'ble Speaker:** Yes.

**Smt. Asha Kumari:** They are from the Parliament. They came here to see the system of e-Governance which has been working in this Vidhan Sabha. We all take pride in that. हमारे जो पूर्व अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल जी थे, आज उनके सपुत्र यहां हमारे साथ बैठे हैं।

**अध्यक्ष** : वह बधाई के पात्र हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है।

**श्रीमती आशा कुमारी** : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने शुरू किया और आप उसको आगे ले जा रहे हैं। इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। आज सुबह ही जो आपने बात रखी कि आपने लाईब्रेरी में Reference Wing का काम शुरू किया है, वह सराहनीय है। मैं समझती हूं कि reference के लिए जिस सदस्य के लिए यह Wing सबसे ज्यादा उपयोगी था, वह मंत्री

13.03.2018/1615/SLS-HK-2

बन गए हैं। वह अभी हाऊस में मौजूद नहीं हैं। मैंने इतना ज्यादा होमवर्क करते किसी व्यक्ति को नहीं देखा है जितना महेन्द्र सिंह जी करते हैं। यह सीखने की बात है। आपने जो यह Reference System शुरू किया है, I am sure you will be able to dovetail it into the app.

जो विधान सभा का ऐप है, उसमें डबटेल करके हम लोग ऑनलाईन भी रिफरैंसिज डालकर निकाल सकेंगे। आपने यह एक अच्छा काम किया है जिसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि किसी ने कुछ नहीं किया है। यहां हम भाषण देते हैं कि आपने 5 साल में यह किया। उससे 5 साल पहले तो आप थे। फिर उससे 5 साल पहले हम थे और उससे 5 साल पहले भी आप थे। यह सिस्टम है और इस सिस्टम में आगे, आगे, आगे ही जाना होता है। यह वही हिमाचल प्रदेश है जिसकी साक्षरता दर, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो केवल 7% थी। आज हम बड़े राज्यों की कैटेगिरी में खड़े हैं। धूमल

साहब थे, तब भी आप लोगों ने अवार्ड लिया, हम थे हमने भी अवार्ड लिया और इस तरह हिमाचल प्रदेश आगे गया है। पहले सड़कें नहीं होती थी लेकिन सड़कें बनाई गईं हैं। हमने भी बनाई और आपने भी बनाई। इसलिए यह कह देना कि आपने कुछ नहीं किया, हमने ही सब-कुछ किया, उससे तो ऐसा लगता है कि विष्णु जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा 'तथास्तु' और सृष्टि की संरचना हो गई। ऐसा नहीं है। सकसैसिव गवर्नमैंट्स ने बहुत कुछ किया है।

सुबह ट्रांसपोर्ट पर चर्चा हो रही थी। I don't know where the young Minister is? He is very energetic, but he is also very contradictory. सदन के बाहर वह कहते हैं कि हमारे पास बसें फालतू पड़ी हुई हैं, रूट्स पर ही नहीं चल रही हैं, फ्लीट ज़रूरत से ज्यादा हो गई है। लेकिन सदन के अंदर जानकारी देते हैं कि एक भी बस ऐसी नहीं है जो रूट पर चल रही है। अब किस बात की सच्चाई मानें? दोनों में से एक ही बात सच हो सकती है। हम तो यही मानेंगे कि जो इन्होंने यहां सदन में कहा कि एक भी फालतू की बस एच.आर.टी.सी. की फ्लीट में नहीं है, वही सही है। वास्तव में अभी नई-नई सड़कें बन रही हैं, रूट्स पास होने हैं जिसके लिए और बसिज की ज़रूरत पड़ेगी; और फ्लीट आपको बढ़नी पड़ेगी। इसलिए हम क्रिटिसिज्म के लिए क्रिटिसिज्म न करें।

**13.03.2018/1615/SLS-HK-3**

I like the speech given by Shri Hoshyar Singh Ji. In fact, I think he is the only one who spoke on the Budget. Everybody else is speaking politically. कोई आर.एस.एस. की गुणवत्ता की बात कर रहा है तो कोई उसके विरोध की बात कह रहा है। Vinod Ji, you are a very bright young man. मुझे यह अच्छा लगा कि आपने कहा कि ये सब आर.एस.एस. के हैं। उसमें आपने अनिल शर्मा जी को भी शामिल कर लिया। ...(व्यवधान)... आपने यह नहीं कहा। आपने कहा कि निकल कर आए हैं।

**13/03/2018/1620/RG/YK/1**
**श्रीमती आशा कुमारी------जारी**

आपने इनको आर.एस.एस. से कहां से निकाल दिया, यह भी एन.एस.यू.आई. से ही आए हैं। तो ऐसा नहीं है। We are not talking about that I am talking to this young man about his remark.

**अध्यक्ष :** आशा जी, आप क्या कहना चाहती है कि अब ये भी उसी रंग में हो गए हैं?

**श्रीमती आशा कुमारी :** ये किस रंग में हैं या नहीं हैं, ये सबसे बेहतर जानते हैं और कब किस रंग में होंगे, यह भी ये ही बेहतर जानते हैं। वैसे हमारे मित्र हैं। --(व्यवधान)---यही तो मैं कह रही हूं। My dear, Pathania Ji, in white today, you alternate between black and white, it is difficult to make out today at your man in white. आपने अपने भाषण में भी कुछ अच्छी बातें कहीं। श्री सुख राम जी ने अच्छी बातें कहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, क्योंकि एक मंत्री यहां बैठे हैं जिनके विभाग के बारे में श्री सुख राम जी ने चर्चा की, कम-से-कम वह मंत्री तो यहां मौजूद हैं, माननीय उद्योग मंत्री। हमारे दल के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, यह भी उद्योग मंत्री थे। इन्होंने अपने समय में एक उद्योग नीति एवं खनन नीति लाई। उस खनन नीति के तहत ऑक्शन करने का प्रावधान है। जो श्री सुख राम जी ने बात कही कि हर खनन अवैध नहीं होता है और हर खनन करने वाला व्यक्ति चोर नहीं होता है। In fact, mining is one of the highest revenue generating activity for any State. अगर आपको रिसोर्स जनरेट करना है, तो जो माइनिंग पॉलिसी श्री मुकेश अग्निहोत्री जी के समय इसी सदन में रखी गई थी, जिसके ऊपर यहां चर्चा भी हुई। जैसा श्री सुख राम जी ने कहा कि बजाय इसके कि हमारे रिसोर्सिज स्क्वैनडर हों, उसको आप गंभीरता से लीजिए। फिर यहां परिवहन मंत्री नहीं हैं। हमने तो सोचा कि बादल सिर्फ पंजाब में ही गरज रहे हैं, ये बादल हिमाचल के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तबाह करने के लिए यहां भी आ गए हैं। I don't understand one thing. How can you sell your permit? आपने परमिट एक इन्डीविजुअल को दिया है, आपने उस फर्म को दिया है, उसे आगे कैसे बेच दिया, यह तो सब-लैटिंग या सब-लीजिंग हो गई और ऊपर से उनको डरा-धमका कर and I will tell you कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पंजाब में they are feeling the heat कहीं से तो उनको अपना बिजनेस चलाना है। हिमाचल की पवित्र देवभूमि में उनको घुसने मत दीजिए, जो अपने नवयुवक हैं उनको दीजिए। आपके यहां से किसी और ने भी यह सुझाव दिया था। I think मंत्री जी, स्वयं ही

**13/03/2018/1620/RG/YK/2**

कह रहे थे कि जो बाहर के लोग थे, उनको ज्यादा वेटेज थी, उसको कम कर दीजिए। Give it to the youngsters of the State.

उनको कोऑपरेटिव बना दीजिए, करिए। आपने तो बादल को भेज दिया। बजट में लिखने से क्या होता है? आपके डॉक्यूमेंट में और आपकी हकीकत में जो विरोधाभास है, उसकी चर्चा करना हमारा फर्ज है। आपको इतना लंबा समय नहीं हुआ है कि हम आपकी आलोचना करें। अभी तो आपको अढ़ाई महीने ही हुए हैं। हम आपकी किस बात की अभी आलोचना करेंगे? जो अभी हुई है, उसी की करेंगे। यह बादल वाला इन्सीडेंट, it has happened after you took over. ये 2-3 और चीजें जो हुई हैं, they have happened after you took over. उसकी हम चर्चा करेंगे। आप उससे तो हमें नहीं रोक सकते। अब हम यह कहें कि वर्ष 1982 में ऐसा हुआ था या वर्ष 1947 में यह हुआ था, तो उसकी चर्चा आज नहीं है। आज हम इस बजट की चर्चा कर रहे हैं। हमारे जुब्बल-कोटखाई के माननीय सदस्य ये मेरे मामे लगते हैं, वहां मेरी ननिहाल है, बहुत पैशनेटली ये बागवानी के बारे में बोल रहे थे। मगर यह भी सच्चाई है कि हार्टिकल्चर मिशन हमारी सरकार के समय में 1300 करोड़ रुपये का आया और आपने भी लिखा है कि उसका सौ करोड़ रुपये इस साल खर्च होगा। उसको आप विस्तृत तरीके से बताएं कि आप कैसे खर्च करेंगे? क्योंकि आप सदन के अंदर कुछ और बोलते हैं और सदन के बाहर कुछ और कहते हैं।
अध्यक्ष महोदय, विपक्ष में कैसे बात करना चाहिए, यह हमने दो लोगों से बहुत सीखा। जैसा कहते हैं कि क्लास में जो सबसे शरारती बच्चा हो, उसको मॉनीटर बना देना चाहिए। कहीं इसलिए तो आपको वहां नहीं बैठा दिया। एक आप और एक आप। आप दोनों ने विपक्ष में रहते हुए बहुत मुद्दे उठाए, बहुत सारी बातें रखीं। खास करके Sh. Mahender Singh Ji, was famous for not seating down. I am going to follow his example.

अध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा कर रही थी कि यदि हम इस बजट में देखें, तो रिजरवॉयर्ज की चर्चा आई। रिजरवॉयर्ज की चर्चा में पौंग डेम एवं कोल डैम का जिक्र है, लेकिन हमारा चमेरा डैम कहां गया? चम्बा का नाम ही नहीं आता।

**13/03/2018/1625/MS/yk/1**

**श्रीमती आशा कुमारी जारी-----------**

मेरे प्रिय श्री जरयाल जी कहां चले गए? ये चम्बा का जिक्र कर रहे थे कि भारत सरकार ने हमें बैकवर्ड जिला का दर्ज़ा दिया है। मैं इनको याद दिला दूं कि यह कोई नई बात नहीं है। इसमें नया सिर्फ यह हुआ है कि पहले दो जिलों चम्बा और सिरमौर को यह दर्ज़ा प्राप्त था और अब सिरमौर को उसमें से हटा दिया गया है। जो अब 115 बैकवर्ड जिले उन्होंने चिन्हित किए हैं उनमें चम्बा शामिल है। चम्बा पहले भी फर्स्ट 50 जिलों में था और आर0एस0बी0वाई0 का बजट पहले चम्बा और सिरमौर दोनों जिलों के लिए आता था। बी0आर0जी0एफ0 का जो पैसा है वह भी दोनों जगह आया। उसके बाद जब प्लानिंग कमीशन वाइंडअप हो गया तब प्लानिंग कमीशन के साथ-साथ यह भी वाइंडअप हो गया और अब नीति आयोग ने नये नाम से कहा कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। चम्बा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। यह शिक्षा के लिहाज से बैकवर्ड है, यहां लिट्रेसी रेट लो है इसलिए बैकवर्ड है और एग्रीकल्चरली बैकवर्ड है इसलिए हम बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में आते हैं but the same was true for Sirmour also. So, I don't why? कि सिरमौर के साथ भेदभाव किया गया। I think Sirmour also deserves. (व्यवधान)-अब हो सकता है कि ऐसा लगा हो लेकिन फिर तो हमारे उपाध्यक्ष जी भी चम्बा से बने हैं।

**अध्यक्षः** मुसाफिर साहब भी थे।

**श्रीमती आशा कुमारीः** तब तक बैकवर्ड था लेकिन अध्यक्ष महोदय आपके सिरमौर आने से वह फॉरवर्ड हो गया। जो आप सोलन से लेगेसी लेकर गए उससे यह जिला फॉरवर्ड हो गया। But, I am just saying सिरमौर और चम्बा हमेशा इकट्ठे रहे हैं और हमेशा रहेंगे। There is no doubt in that. वे कह रहे थे कि बैकवर्ड के लिए धन्यवाद है। बैकवर्डनैस के लिए कोई धन्यवाद नहीं होता है। अध्यक्ष जी, I just take five minutes more. You know, I don't speak out of turn. परन्तु मैं महेन्द्र सिंह जी से सीख रही थी कि यहां बैठना ही नहीं चाहिए। हालांकि डिसीप्लेन को ये मेंटेन करते हैं लेकिन I would like to say one thing कि mere criticism for the sake of criticism ये कह देना कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया और ये नहीं देखना कि आपके अपने पत्र में कोई दृष्टि/विज़न

ही नहीं है। आप तो सिर्फ उन्हीं चीजों की चर्चा कर रहे हैं जिनकी नीव हमने रखी है। किसी चीज को आप खोलने की बात कर

**13/03/2018/1625/MS/yk/2**

रहे हैं और किसी चीज को आप बन्द करने की बात कर रहे हैं। आप महेन्द्र सिंह जी स्कीम्ज की बात कर रहे हैं और अन्य भी स्कीम्ज की ही बात कर रहे हैं। पानी की स्कीम्ज हैं तो आप भी उन्हीं की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह से एक ब्लैंकेट कह दें। फिर बेरोज़गारी की बात आई। I agree with you, and you are the most vital link in that continuity, from many-many years in this Vidhan Sabha as continuity link between parties also. You are a great example of continuity and I admire you for that अध्यक्ष जी.., -(व्यवधान)-

**अध्यक्षः** आपको इस बात का दुःख तो नहीं है।

**श्रीमती आशा कुमारीः** अध्यक्ष जी, इस बात के लिए मैं इनको एडमायर करती हूं कि ये कंटीन्यूटी का लिंक है। Not only, in the Vidhan Sabha, but between parties also, and I admire in for that. .....(Interruption)..... Now that he is saying, I am not saying. .....(Interruption)..... Party or no Party Sh. Mahender Singh Ji, is permanent in this Vidhan Sabha, and I compliment him for that. अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो बजट यहां पेश किया गया है इसमें वास्तव में ही बेरोज़गारी को एड्रैस करने के लिए जिस दृष्टि की आप बात करते थे वैसी कोई दृष्टि नहीं है। हैरानी मुझे तब हुई और मुझे ऐसा लगता भी था कि यहां बजट भी इसी तरह का आएगा जिसमें बेरोज़गारी का जिक्र नहीं होगा क्योंकि आपके जो केन्द्र में मंत्री हैं, जो बेरोज़गारी के आंकड़े होते हैं, उनके बारे में उनका बयान आया था कि आगे से किसी को यह पता नहीं लगेगा कि हिन्दुस्तान में कितने बेरोज़गार हैं। उनसे पत्रकारों ने पूछा कि कैसे? तो उन्होंने कहा कि हमने फैसला कर लिया है कि हम सेंन्सिज ही नहीं करेंगे कि बेरोज़गार कितने हैं। इससे अच्छा तरीका बेरोज़गारी की फीगर को खत्म करने का और क्या हो सकता है? This is not a Government which is sensitive to the problems of the youth. अच्छा होता अगर आप बताते कि आप कहां जॉब जनरेट करेंगे।

यहां पर बहुत शोर मचा कि 50 करोड़ रुपया टूरिज्म के लिए दे दिया। आज की तारीख में 50 करोड़ रुपये में एक भवन तक नहीं बनता और 50 करोड़ रुपये में तो दो सड़कें नहीं बनती।

**13.03.2018/1630/जेके/एजी/1**

**श्रीमती आशा कुमारीः----जारी--------**

आपने राकेश पठानिया जी के कहने पर कन्सल्टैंट हायर करने हैं तो आप उसमें अपनी दृष्टि में बता देते। आपसे अच्छा सुझाव तो होशयार सिंह जी ने दिया कि सभी विधायकों से पूछा जाए कि उनके इलाके में कौन से ऐसे प्वाइंट्स हैं जिनको कि टूरिज्म की दृष्टि से डिवेल्प किया जा सकता है। कन्सल्टैंट की क्या जरूरत है? यहां पर कौन सा ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसको अपने इलाके का चप्पा-चप्पा नहीं पता है? क्या यहां पर चाहे इधर या उधर ऐसा कोई है? सबको मालूम है कि मेरे इलाके में टूरिज्म के हिसाब से ये-ये स्पॉट है जिनको डिवैल्प किया जा सकता है। हमारा इलाका है और उपाध्यक्ष जी अभी यहां पर मौजूद नहीं है, हमारा पदरी जोत is one of the most beautiful areas of Himachal Pradesh. चांशल का एरिया is also one of the most beautiful areas of Himachal Pradesh. मण्डी में शिकारी देवी है और बहुत सारी जगह हैं और सब अपनी-अपनी जगहों के बारे में बता सकते हैं मगर इसका यह मतलब नहीं है कि कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना में भी नहीं हो सकता। आप अध्यक्ष महोदय यह देखिये कि हरियाणा में नेशनल हाई वे पर ही टूरिज्म चल रहा है। टूरिज्म को डिवैल्प करने के लिए सिर्फ सुन्दर जगह ही नहीं लगती है बल्कि दृष्टि भी लगती है। Man-made tourism is also very important tourism. रीलिजियस टूरिज्म की आपने बात की। Religious tourism has always been an important sector in Himachal Pradesh, not from now but from years and years. प्रश्न तो यह है कि हम इसको बढ़ावा देने के लिए और क्या करेंगे? यहां पर गौ-सदन की बात आई। I am all for Gausadans. हमारे जो पूर्व पशु पालन मंत्री थे वे अब आपके पावर मिनिस्टर हैं, इनसे हमने कई बार निवेदन किया और इन्होंने उस वक्त कोशिश भी की। अध्यक्ष महोदय, गौ-सदन को स्थापित करने की ज्यादा समस्या है कि जमीन ट्रांसफर नहीं होती। आज तक यह फैसला नहीं हो पाया कि जमीन किसके नाम ट्रांसफर होनी है। गौ-

सदन तो तब बनेगा जब जमीन ट्रांसफर होगी। लैंड ट्रांसफर किसके नाम होगी उसके ऊपर फोरैस्ट विभाग की सहमति बन ही नहीं पाई और इस बात को आप भी जानते हैं। मंदिर ट्रस्ट भी चलाना चाहते हैं और कुछ चला भी रहे हैं। मेरे ख्याल से कांगड़ा देवी में चल रहा है, डमटाल में चल रहा है और नूरपुर में तो वैसे ही बहुत बड़ा गौ-सदन है। मगर अगर गौ-सदन स्थापित करने है तो सबसे

**13.03.2018/1630/जेके/एजी/2**

पहले आप यह नीति लाएं कि उसकी जमीन कैसे ट्रांसफर होगी और किसके नाम से होगी? Who will be the owner of that land? That is the biggest factor. जिसकी वज़ह से ये गौ-सदन स्थापित नहीं हो पाते। आवारा पशुओं की समस्या रहती है। अध्यक्ष महोदय, आप बड़े प्यार से बैठने के लिए कह रहे हैं लेकिन आप इतने प्यार से खुद मानते नहीं थे। अब मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी बात मानूं?

**अध्यक्षः** माननीय सदस्या जी, मुझे पता है कि आप मानने वाले हैं।

**श्रीमती आशा कुमारीः** अध्यक्ष महोदय, यह जो बजट है क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक कहा मुकेश जी ने और राम लाल जी ने कि शराब भी पुरानी, बोतल भी पुरानी। (व्यवधान) उन्होंने स्वागत नहीं किया। उन्होंने यह कहा कि मुकेश अग्निहोत्री जी ने जो कहा उसको कहते हैं। महेन्द्र जी फिर आप समझने में कमज़ोरी कर रहे हैं देखिए यह आप गड़बड़ कर रहे हैं।

**अध्यक्षः** माननीय मंत्री जी, प्लीज़।

**श्रीमती आशा कुमारीः** उन्होंने जो कहा वह बिल्कुल सही कहा। This is totally old wine in a totally old bottle, filled in rotten bottle with a totally bad-bad label on it. इसका कोई समर्थन किस बात का करें? इस बात का कि जो पुराना बजट था उसको घिस-पिट के फिर से लिख दिया, इसका समर्थन करें? इस बात का कि कहीं 15/-रूपये, कहीं 20/-रूपये और कहीं 2000/-रूपये बढ़ा दिए, नाम बदल दिए और थापी ले ली। इस बात का समर्थन कम से कम आप हम लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हाँ, यहां पर जो

एक यंग मैन ने दृष्टि की बात कही थी, आप कोई दृष्टि ले कर आते। हिमाचल प्रदेश के लिए नई दृष्टि ले कर आते। इनका नाम मुझे याद रखना पड़ेगा because he speaks well. शायद राकेश जम्वाल है। (Interruption) I don't know. But he speaks well. इन्होंने ये बात बहुत सही कही थी कि जो भी आपकी सरकार की दिशा हो वह दृष्टि पत्र पर हो। दृष्टि पत्र कहां पर है? आपने ठीक कहा था कि उसको सदन के पटल पर रखा जाए। इस बजट में ही आप

**13.03.2018/1630/जेके/एजी/3**

आकलन करते कि हमने दृष्टि पत्र में यह कहा था और उस दृष्टि के मुताबिक हम यह कर रहे हैं। आप तो सिर्फ आलोचना करने में ही रह गए। विनोद जी कहां चले गए? वे तो यह कहते रह गए कि जो मैडिकल कॉलेजिज़ हैं, वे इस एन0डी0ए0 सरकार ने दिए हैं। मैडिकल कॉलेजिज़ चम्बा, सिरमौर और हमीरपुर में माननीय गुलाम नवी आजाद जी ने दिए थे। हम उनका धन्यवाद बार-बार करते हैं।

**13.03.2018/1635/SS-AG/1**

**श्रीमती आशा कुमारी क्रमागतः**

और जो आप करेंगे उसमें आपका धन्यवाद। ऐम्स की बात है, अब यहां पर कई बार कई लोगों ने बात कही कि फट्टे पहले लग गए --(व्यवधान)--मैं आपको लास्ट बोल रही हूं। यहां पर यह चर्चा आई कि बिना बजट के यह हो गया, वह हो गया। मैं अखबार में पढ़ रही थी और शायद सांसद महोदय का बयान था और उनके प्रश्न का उत्तर पार्लियामैंट में था। जो ऐम्स का उद्घाटन या शॉर्ट ऑफ फट्टा लगा या बिलासपुर में शिलान्यास हुआ, वह अक्तूबर के महीने में हुआ और ऐम्स की नोटिफिकेशन दिसम्बर के महीने में हुई। यह सांसद महोदय के प्रश्न के जवाब में अखबार में लगा हुआ था। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। Hon'ble Speaker, Sir, before I finish, I would like to say one thing. हम चाहें इस तरफ हों या उस तरफ हों, सब विधायक हैं। ब्यरोक्रेसी अपनों का पूरा साथ देती है, और भी जो कैटेगिरीज़ ऑफ सोसाइटीज़ हैं बैंकर्ज़ इकट्ठे हो जाते हैं, चोर भी इकट्ठे हो

जाते हैं, भगोड़े भी इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर हम विधायक एक-दूसरे पर टीका-टिप्पणी क्यों करते हैं। We should have respect for each other. अगर हम एक-दूसरे की रिस्पैक्ट करेंगे तो दुनिया हमारी रिस्पैक्ट करेगी। हमारे विचारों का मतभेद हो सकता है, हमारी चर्चा में मतभेद हो सकता है मगर एक-दूसरे के बारे में हमें टीका-टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

Speaker, Sir, with that this budget has nothing, nothing and nothing जिसका कि समर्थन किया जाए। मैं तो टोटली इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं।

**अध्यक्षः** अगले सदस्य से पहले माननीय उद्योग मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

**13.03.2018/1635/SS-AG/2**

**उद्योग मंत्रीः** श्रीमती आशा जी ने जो विषय माइनिंग का रखा है उसमें बोल रही थीं कि आदरणीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी पॉलिसी लेकर आए थे। तो आपके ध्यान में रहे कि उस पॉलिसी के माध्यम से ये जो ऑक्शन का इश्यु है हमारी सरकार के समय में कांगड़ा के अंदर 30 साइट्स 8.73 करोड़ की, हमीरपुर के अंदर 14 साइट्स 3.95 करोड़ की, सिरमौर के अंदर 23 साइट्स 30.35 करोड़ की, ऊना के अंदर ऑक्शन का अमाऊंट 3.48 करोड़ है और मंडी के अंदर ऑक्शन अमाऊंट 1.75 करोड़ है। दो महीने का जो हमारा छोटा-सा कार्यकाल हुआ है उसमें हमने यह किया है। आने वाले समय में हम मैक्सिमम ऑक्शन्ज़ करेंगे ताकि इल्लीगल माइनिंग के ऊपर रोक लगाई जा सके।

**श्रीमती आशा कुमारीः** अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो बात कही, मैं इसका स्वागत करती हूं। वह अच्छी बात है। मगर मैं आपसे यह भी कहना चाहती हूं कि इसका यह मतलब नहीं कि जो इल्लीगल माइनिंग कर रहे हैं उनको आप छोड़ दें। उनके ऊपर कार्रवाई सख्त होनी चाहिए।

**उद्योग मंत्रीः** हमने सख्त कार्रवाई की है और जर्माना भी डबल कर दिया है।

**अध्यक्षः** मैं अगले सदस्य के बोलने से पहले थोड़ा सदन से एक इजाज़त चाहता हूं। हमारे पास आज की सूची में जो बोलने वालों के नाम हैं उनमें श्री बलबीर सिंह जी, श्री राकेश

सिंघा जी, श्री लखविन्द्र सिंह राणा जी, श्री किशोरी लाल जी, श्री जीत राम जी और श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी हैं। तो क्या हम आज सदन का समय बढ़ाकर चलाना चाहेंगे या फिर दो सदस्यों को आज बुलवा करके उसके बाद कल के लिए रखेंगे? आज अगर कुल दो बोल लेते हैं तो बाकी कल बोलेंगे। एक बलबीर जी और दूसरे राकेश सिंघा जी, दो नाम मेरे पास टॉप पर हैं इन लोगों को आज बुलवा देते हैं। बाकियों को कल सवेरे बुलवा देंगे। चलो कल मीडिया का साथ मिलेगा बाकी तो कोई बात नहीं है। ठीक है जी, मैं बलबीर जी को अगले वक्ता के नाते आमंत्रित करता हूं।

13.03.2018/1640/**केएस**/**डीसी**/1

**श्री बलबीर सिंहः** माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट अनुमानों पर जो चर्चा चल रही है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी को जहां बधाई देता हूं वहीं धन्यवाद भी करता हूं कि इन्होंने एक ऐसा संतुलित बजट इस प्रदेश में पेश किया है जिसकी गूंज पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में है। इस बजट में आशा वर्कर्ज़ से ले कर इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के पक्ष में कुछ न कुछ लिखा गया है। मैं समझता हूं कि ऐसा बजट वही इन्सान पेश कर सकता है जो गरीब को भी और गरीबी को भी जानता हो। मैंने आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी के क्षेत्र सिराज में इनके चुनाव के दौरान 20-25 दिन इनके साथ रह कर कार्य किया और मैंने वहां इनकी कार्यशैली को देखा है। ये गरीब के हिमायती, गरीब की आवाज बुलन्द करने वाले व्यक्ति हैं। मैं इनको दाद देता हूं और इस बजट को पेश करने के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, नेता कांग्रेस दल ने, वैसे तो विपक्ष सरकार के बजट का समर्थन करता भी नहीं है परन्तु इन्होंने यहां तक कह दिया कि इस प्रदेश का अगर वजूद है, अस्तित्व है तो वह कांग्रेस के नेताओं की वजह से हैं लेकिन मैं इसमें दर्ज करना चाहता हूं कि अगर हिमाचल का अस्तित्व है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से हैं नहीं तो आज यह सारा प्रदेश राजाओ-महाराजाओं के दबाव तले कुचल रहा होता। यह सच्चाई है।

मैं इस बात का गवाह हूं। मेरा वर्ग, मेरा समुदाय उस उत्पीड़न का, उस खिदमत का गवाह रहा है और मैं भी रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यहां पर गपोड़शंख व शेखचिल्ली जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए लेकिन गपोड़शंख होता क्या है? मैं याद करवाना चाहता हूं कि पिछली सरकार के माननीय मुख्य मंत्री, लोग इनको राजा कहते हैं मैं महाराजा कहता हूं, अपने मुख्य मंत्री काल में जब विधायकों के क्षेत्र में जाते थे, वैसे तो बहुत अध्यात्मिक प्रक्रिया के समान मंच पर बैठते हैं, लोग कहते हैं कि इनको नींद आती है लेकिन मैं समझता हूं कि ये सुनते हैं इसीलिए मैं इनको महाराजा कहता हूं, ये छः बार मुख्य मंत्री रहे हैं। विधायक उस मंच से क्या कहे, ऐसी मांग भी रखे जो कभी पूर्ण ही नहीं हो सकती उनका सारा

**13.03.2018/1640/केएस/डीसी/2**

भाषण सुनकर जब इनका नाम पुकारा जाता था तो इनको हिलाकर उठाया जाता था और मंच पर जा कर केवल मात्र इतना कहते थे कि जो विधायक ने बोला है वह सब हो गया। अधिकारी भी इस बात के गवाह होंगें अध्यक्ष महोदय, उनमें से एक भी योजना आज तक सिरे नहीं चढ़ पाई है।

अध्यक्ष महोदय, वहां पर भाजपा नेताओं को गालियां देने के सिवा कोई और काम नहीं होता था। यहां तक भी कुचलने की आदत उनकी नहीं गई। यहां तक कहा जाता था कि मैं बहुत महीन पीसता हूं। किसके लिए कहा जाता था? किसको महीन पीसने की बात कही जाती थी? अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश का दर्जा बना है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से बना है किसी राजा का महत्व नहीं है।

**13.3.2018/1645/av/yk/1**

**श्री बलबीर सिंह जारी**-------

अध्यक्ष महोदय, गप्पें कैसी, गपोड़ शंख। अम्ब में एक बस अड्डा है। जनवरी, 2012 में वहां पर एच0आर0टी0सी0 का एक छोटा सा टूटा हुआ हाऊस और शौचालय था। मैं उस उपमण्डल से बी0जे0पी0 की तरफ से अकेला एम0एल0ए0 था। मैंने वहां पर बात रखी कि

उस बस अड्डे का शौचालय अच्छा नहीं है, कमरा अच्छा नहीं है, वहां बैठने के लिए कुछ-न-कुछ तो बनें। उस वक्त के डी0सी0 ने एस0डी0पी0 के माध्यम से उसके लिए 8.60 लाख रुपये स्वीकृत किए। दिसम्बर, 2012 में हमारी पार्टी की सरकार चली गई। नई सरकार आई और नये विधायक बन गये तथा उसका भी शिलान्यास हो गया। मगर उस 8.60 लाख रुपये की राशि से वहां पर आज तक न तो कोई शौचालय बन पाया और न ही कोई कमरा बन पाया। वहां पर कोई यात्री आए तो कहां बैठे, कोई बहन आए तो शौचालय कहां पर इस्तेमाल करे। वहां पर केवलमात्र एक फर्श बना और उस फर्श का भी उद्घाटन हो गया। मैंने कभी सुना नहीं था कि बस अड्डे के धरातल पर फर्श डालकर एम0एल0ए0 साहब उद्घाटन करें, यह मेरी समझ से परे हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद हमारी सरकार के वक्त में टूरिज्म का पैसा आया था कि होशियारपुर/पंजाब से लाखों पर्यटक माता चिन्तपुरनी, माता ज्वाला जी, धर्मशाला, पालमपुर के लिए जाते हैं। नवरात्रों के दौरान माता चिन्तपुरनी के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में यात्री आते हैं। हमने कहा कि वहां पर गंदगी बहुत फैलती है इसलिए एक-एक किलोमीटर पर रेन शैल्टर बनाये जाएं और वहां पर शौचालयों का प्रबंध भी किया जाए। मगर वह पैसा कहीं नहीं लगाया गया, उस पैसे में से 1.22 करोड़ रुपये बस अड्डे के लिए स्थानांतरित कर दिए गए। मगर उस बस अड्डे में आज तक एक भी ईंट नहीं लग पाई है। मैं इन सब बातों को देखते हुए यह कह रहा हूं कि गपोड़ शंख वाली बातें इस तरफ से नहीं बल्कि उस तरफ से होती रही हैं। यहां पर यह भी कहा गया कि बेरोजगारों के साथ हम धोखा कर रहे हैं। मैं इस बात का भी दावा करता हूं कि अगर बेरोजगारों के साथ इस प्रदेश में कहीं धोखा हुआ तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया जिसने 70 साल की

**13.3.2018/1645/av/yk/2**

आजादी में लगातार 50-55 वर्षों तक सत्ता हासिल की है। उसमें से भी एक ही परिवार ने लगभग 40 वर्ष तक सत्ता हासिल की है इसलिए बेरोजगारों के साथ धोखा/फरेब वहीं से शुरू हुआ है। मैं मानता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री आज एस0एम0सी0 के साथ मिले।

उनकी मांगे सुननी थी और यह मुख्य मंत्री का फर्ज है,उनको सुनना पड़ेगा। मगर पी0टी0ए0 रखते वक्त डिग्री वालों को नजरअन्दाज करके वहां पर अपने परिवार व रिश्तदारों को रखा जाता था। सुखराम जी यहां पर ठीक कह रहे थे कि पक्षपात एक जगह नहीं हुआ मगर मैडम जी कह रही थीं कि कहीं-कहीं हुआ है। नहीं, मैडम जी, कहीं-कहीं नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में भारी पक्षपात हुआ है।

मैं यहां पर धारा 118 की चर्चा में भी हिस्सा लेना चाहूंगा। वैसे तो माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी मेरे भाई हैं और मैं इनका मान-सम्मान करता हूं। मैं इनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि विपक्ष ने इनको अपना नेता माना है। माने, मानते रहे, यह हमारे लिए भी अच्छी बात है। मगर धारा 118 पर बोलते वक्त अपने शरीर के हाव-भाव ऐसे कर देना कि जैसे सबकुछ ही गलत हो गया और हमने ही गलत किया है।

अध्यक्ष महोदय, आपके पास, सरकार के पास रिकार्ड है, इसको चैक कर लिया जाए कि जब-जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो धारा 118 के साथ खिलवाड़ इन्होंने ही किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस की तरफ से, हमारी तरफ से और हिमाचल का कोई भी व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि मेरे हिमाचल के साथ खिलवाड़ हो। परंतु यह कहते थे कि आपने ऐसी बातें चुनाव लड़ने के लिए कही है। आपने भी ऐसी बातें चुनाव लड़ने के लिए की है जैसे हिमाचल ऑन सेल, हिमाचल बिक गया। आपके पास एक भी उदाहरण नहीं, आपने युनिवर्सिटी का नाम ले-लेकर कहा कि हिमाचल सेल कर दिया, हिमाचल बेच दिया।

**13.3.2018/1650/TCV/AG-1**

**श्री बलवीर सिंह ...... जारी**

परन्तु जब आप सत्ता में आये तो आपने एक भी यूनिवर्सिटी को बंद तो क्या करना था, आप विलायती पोशाकें पहनकर वहां पर डिग्रियां बांटने जाते रहे। अध्यक्ष महोदय, ये दोहरा चरित्र, दोहरे मानदण्ड नहीं चलेंगे। अध्यक्ष महोदय, बजट की इस किताब में एक मुहाबरा

लिखा है- "ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत" कांग्रेस पार्टी ने इस मुहाबरें को चरितार्थ किया है। ऋण लेकर घी पीने का काम किया है, धरातल पर कुछ हुआ नहीं। अगर केन्द्र की कुछ योजनाएं न होती, वह काम नहीं होता, वहां से पैसा नहीं आया होता, तो कांग्रेस के लोग आज मुंह दिखाने के लायक भी नहीं होते।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें हर विधान सभा क्षेत्र में 'मुख्य मंत्री लोक भवन' के लिए जो 30 लाख रुपया स्वीकृत किया है, वह बड़ी अच्छी बात है। अमीर लोग तो मैरिज़ पैलेस में चले जाते हैं और जिनके पास पैसा है, वह तो शहरों में जाकर भी शादियां कर रहे हैं। परन्तु गरीब जाये तो जाये कहां? उसके पास पैसा नहीं, उसके पास उतनी हैसियत नहीं। माननीय मुख्य मंत्री ने सोचा, इससे पहले जब हमारी पिछली सरकार थी, तो डॉ0 भीमराव अम्बेदकर के नाम पर भी 10-10 लाख रुपये से भवन बनाये गये थे। ये जनहित की योजना है, इसलिए मैं इनको बधाई देता हूं। इतना ही नहीं अगर दो और भी कोई विधान सभा के विधायक उस क्षेत्र में बनाना चाहे तो 15-15 लाख रुपये सरकार देगीं। मैं कहता हूं, ये बहुत बढ़िया फैसला है, अच्छा फैसला है। इसकी ज्यादा-से-ज्यादा सराहना होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस देश में, जब से देश आजाद हुआ, तब से अब तक, मैं मानता हूं कि अधिकारी लोग बजट बनाते हैं, हम पढ़ते हैं, सरकारें पढ़ती हैं, प्रधान मंत्री, प्रदेशों के मुख्य मंत्री पढ़ते हैं। परन्तु मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूं, उन्होंने 'उज्ज्वला योजना' के अधीन, इस देश के जो समर्थवान लोग थे, उनसे पहली बार इस देश के

**13.3.2018/1650/TCV/AG-2**

प्रधानमंत्री ने अपील की, उन्होंने एम0पीज़0 और एम0एल0एज़0 से भी अपील की थी कि आप एल0पी0जी0 गैस की सब्सिडी छोड़ दो। इस देश के गरीबों को इसकी ज़रूरत है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, उन सब लोगों, भाईयों, बहनों का जिन एक लाख 37 लाख लोगों ने अपना गैस कनैक्शन छोड़ा और उज्ज्वला योजना के अधीन 5 करोड़ महिलाओं को गैस देने का काम किया है। उसी योजना को हमारे मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने

आगे बढ़ाया है, उसका भी विरोध किया जा रहा है और 3 करोड़ और भी बढ़ा दिया है। 8 करोड़ लोगों को वह गैस कनैक्शन दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं, उन्होंने ए0पी0एल0 कार्ड-धारकों से भी निवेदन किया है कि आप भी अनाज पर जो सब्सिडी प्रदेश सरकार देती है, उसको छोड़ दो। मैं तो आज ही वायदा करता हूं कि मैंने तो छोड़ दी है, मैं लेता भी नहीं हूं लेकिन आज ही छोड़ने का वर्वली एफिडेविट देता हूं। ऐसी हिम्मत कोई आसानी से नहीं जुटा सकता।

अध्यक्ष महोदय, गुडिया कांड की चर्चा थी, मैं उस पर नहीं बोलना चाहूंगा। मैं इतना बोलना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने इस प्रदेश में अश्लीलता और असभ्यता को भी बेचा है। मैडम जी (श्रीमती आशा कुमारी) हमें कह रही थी - नॉन सीरियस गवर्नमैंट। मैडम जी आप कितने सीरियस थे? मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैडम जी आप बुरा नहीं मानना मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा।

13-03-2018/1655/NS/HK/1

श्री बलवीर सिंह-------जारी।

आपने मंत्रियों के भी नाम लिये थे और सरकार में हम सब हैं। ---(व्यवधान)--- चलो प्लीज़, आपको जैसा लगे आप वैसा मान लीजिएगा। आप बुरा मत मानना, मैं यहां पर एक उदाहरण देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रदेश में सरकार अश्लीलता और असभ्यता बेचे, वहां पर गुड़िया कांड जैसे कांड तो होंगे ही। आप इनको कैसे रोकेंगे? अगर कोई लगाम नहीं होगी तब इनको नहीं रोका जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, एच0आर0टी0सी0 बसों पर अर्धनग्न महिला, सन्नी लियोन की फोटो मैनफोर्स बेचते हुए पांच सालों तक लगी रही, मैं समझता था कि मैडम आशा कुमारी जी ऐसा देखकर विचलित होंगी और उन बोर्डों को हटवायेंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह जनता में कोई अच्छा संदेश नहीं गया है। आप सुन लीजिये, यह धरातल पर सच है, झूठ नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस विभाग को उस विज्ञापन से कितनी

आमदनी हुई होगी? इसका पता लगाया जाये। एक मंत्री के अश्लील फैसले पर सारी सरकार नतमस्तक होती रही है। इस प्रदेश के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ---(व्यवधान)--- मैं हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं। दिल्ली में तो आप (विपक्ष) ही जाते हैं, आपके लिए ही सब कुछ है, हमारे लिए कुछ नहीं है।

**अध्यक्षः** माननीय सदस्य आप चेयर की तरफ देखकर ही बोलिये।

**श्री बलवीर सिंहः** अध्यक्ष महोदय, यहां पर "आयुष्मान योजना" का ज़िक्र आया था। हमारे प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री जी ने "राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना" के तहत इसको आगे बढ़ाया है। इस देश में पहली बार ऐसे प्रधान मंत्री हुए, जिन्होंने देखा कि गरीब की अस्पतालों में कोई नहीं सुनता है। गरीब के पास पैसा नहीं होता है। तब प्रधान मंत्री जी ने निर्णय लिया और इस वर्ष लगभग 10 करोड़ लोगों को "आयुष्मान योजना" के अधीन पांच लाख रुपये की राशि तक ईलाज़ मुफ्त करवाने की योजना बनाई। उन्होंने अपनी तरफ से भी इस योजना को आगे बढ़ाया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा है कि मैं हिमाचल प्रदेश में किसी भी ऐसे गरीब व्यक्ति को बिना इलाज़ के जाने नहीं दूंगा। ये बात सराहने योग्य है। प्रधान मंत्री जी ने जहां "फसल बीमा योजना" इस देश के लिए शुरू की है, वहीं 12 रुपये की राशि वाला बीमा "प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना" और 330 रुपये की राशि वाला बीमा " प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना" शुरू की है।

13-03-2018/1655/NS/HK/2

अध्यक्ष महोदय, "मुद्रा योजना" जिस पर कहा जा रहा है कि इस प्रदेश को कोई रोज़गार नहीं दिया है। इस देश की छः करोड़ स्माल स्केल इंडस्ट्री को दोबारा रिफाइनैंसिंग की गई है और इसके लिए माइक्रो यूनिट डिवेल्पमैंट रिफाइनैंसिंग एजैंसी के द्वारा प्रावधान किया गया है। इस योजना का बहुत सारे नौजवानों, लोगों और महिलाओं ने लाभ लिया है। इन्हीं सभी योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष वाले दोहरी बात कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि इस बज़ट में कुछ नहीं है और हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। परन्तु दूसरी तरफ कह रहे हैं कि यह वही है जो हम लिखा करते थे। मैं पूछना चाहता हूं कि जो आप लिखा करते थे तो क्या वह गलत था? अगर वह भी गलत था तब तो आप गलत बोलिये। यहां पर ऐसा मसला पेश किया जा रहा है कि हम उसकी क्या चर्चा करें? (घण्टी) अध्यक्ष महोदय, आपने घंटी बजा दी है और मैं वैसे ही

समय का बहुत पाबंद हूं। मैंने पता नहीं क्यों समय पर ध्यान नहीं दिया? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और माननीय वन मंत्री के ध्यान में लाना चाहूंगा कि ऊना क्षेत्र में "स्वां जलागम परियोजना" के लिए 160 करोड़ रुपये की राशि पहले स्वीकृत थी और हमने उसका काम करवाया था। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सब काम हमारे समय में ही अच्छे हुये होंगे। इसमें बहुत सारी करप्शन हुई है। इसके लिए लगभग 90 करोड़ रुपये की राशि बाद में आई है।

**अध्यक्षः** इस माननीय सदन की बैठक 30 मिनट के लिए 5.30 बजे अपराह्न तक एक्सटैंड की जाती है।

**श्री बलवीर सिंहः** जब ये राशि आई तब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जापान भेजा गया कि सीख करके आओ, छोटे-छोटे बांध कैसे बनाये जाते हैं? अध्यक्ष महोदय, यह जापान में सीखा गया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा और

13.03.2018/1700/RKS/YK-1

श्री बलबीर सिंह... जारी

मैंने इस बारे में अपने प्रश्न लगाए हुए हैं और माननीय मंत्री जी इनका जवाब भी देंगे कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जापान भेजने के लिए इस गरीब प्रदेश के ऊपर कितना खर्च पड़ा। इस बज़ट की किताब में एक नई योजना दर्ज़ है- HP Forest Eco System Management and Livelihood Improvement Project, जिसमें 800 करोड़ रुपये लगेंगे। दूसरी है, Integrated Development Project for source Sustainability and Climate Resilient Rainfed Agriculture 665 करोड़ रुपये की।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो फोरैस्ट विभाग करता है, उसमें भ्रष्टाचार के बहुत सारे रास्ते हैं। इनको रोकने के लिए सरकार को अभी से सचेत हो जाना चाहिए। ऊना में ऐसा ही हुआ है कि वन अधिकारियों ने कांग्रेस नेताओं की नर्सरियां लगाकर 'स्वां जलागम परियोजना' के पैसे को लूटा है। मैं लम्बी बात न करते हुए इस बजट

का भरपूर समर्थन करता हूं। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

13.03.2018/1700/RKS/YK-2

**अध्यक्षः** अब माननीय सदस्य, श्री राकेश सिंघा जी चर्चा में भाग लेंगे।

**Shri Rakesh Singha :** Hon'ble Speaker, Sir, I rise to participate in the Budget discussions on the Budget placed by the Hon'ble Chief Minister, the Budget proposals for the year 2018-2019. Hon'ble Speaker, Sir, मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री महोदय को इस मेडन बजट को हाउस में इंटरोड्यूस करने के लिए मुबारिकबाद देनी चाहिए। मुबारिकबाद इसलिए नहीं कि बज़ट के कन्टैंट हिमाचल प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाएंगे। मुबारिकबाद इसलिए देनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री महोदय ने एक डायरैक्शन लैस बज़ट को डायरैक्शन देने की कोशिश की है। मैं इस पर चर्चा करने से पहले माननीय सदस्या श्रीमती आशा कुमारी जी से सहमत हूं कि जिन लोगों ने इस बज़ट को बनाया है, वे आज हाउस में सीरियस नहीं है। हाउस में तो नहीं कहना चाहिए लेकिन उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वे आज यहां पर रहते, इस चर्चा को सुनते। मेरा हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री से निवेदन है कि आइंदा जब इस बज़ट पर चर्चा हो तो हमारे अफसरान साहब इस हाउस में मौजूद होने चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं कि यह एक डायरैक्शन लैस बज़ट है? मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि इसका जो दृष्टिकोण है, इसकी जो दिशा है, इसका जो हिमाचल प्रदेश के प्रति आउटलुक है, मैं समझता हूं कि ये वित्तीय पूंजी द्वारा संचालित एक बजट है। मैं इस माननीय सदन के अंदर इस बात को कबूलता हूं कि इस बज़ट में गंभीर कमियां रहेगी, कमजोरियां रहेगी। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में बहुत ज्यादा आय नहीं हो सकती है। इसका कारण यह है कि जिस समय हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ था, यह इस दृष्टि से नहीं हुआ कि इसकी एक इकॉनोमिक वायबिलीटी होगी। लेकिन यह पहाड़ के रहने वालों की इच्छा थी और इसलिए हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया।

12.03.2018/1705/बी0एस0/ए0जी0-1

**श्री राकेश सिंघा ......जारी**

लेकिन मैं समझता हूं उसके बावजूद इस बजट के resource mobilization के लिए एक गम्भीर कार्य सरकार और सरकारी विभाग का हो सकता था। लेकिन वह गम्भीर कार्य नहीं किया गया है। आज से पहले भी इन बातों को लेकर इस सदन में चर्चाएं होती रही कि किस तरीके से हम सीमित संसाधन होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश के संसाधन बढ़ा सकते हैं लेकिन इस बजट के अन्दर इसके प्रावधानों के अन्दर एक भी जिक्र नहीं किया गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप इस बात को नोट करें, मुख्य मंत्री साहब इस बात को नोट करें कि यह देश के उच्चतम न्यायालय ने 2/1996 के State of Hmachal Pradesh Vs Union of India and Others के अन्दर हमारे 7.19 परसेन्ट के हिस्से के बारे में फैसला दिया। यह फैसला आज से बहुत पहले आ गया है। लेकिन इसका एक नया पैसा हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला है। क्या यह केन्द्र सरकार की जिम्मवारी नहीं बनती थी? सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो किसी राज्य के हक-हकूक को दिलाते हैं। क्या यह केन्द्र सरकार का फर्ज नहीं बनता ? क्या हम देख की युनियन का एक हिस्सा नहीं है। इस संघीय ढांचे के अन्दर क्या हमारे राज्य होने के नाते हमारे हिस्से नहीं बनते। ऐसा ऐहसास मुझे होता है केन्द्र सरकार और जो जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की है उसके प्रति गम्भीर नहीं है, नहीं तो इस फैसले में जो हमारा हिस्सा बनता था वह मिल जाना चाहिए था। इस बजट में भी कोई जिक्र नहीं है कि किस तरीके से इसको दिया जाए। आप जानते हैं अध्यक्ष महोदय, हमारा भाखड़ा बांध में 2.5 परसेन्ट हिस्सा एडहोक के रूप में दिया गया और आज तक उसके ऊपर पुनर विचार भी किया गया जबकि बहुत से कमीशन जो बाद में बैठे हैं, उसमें जिक्र किया है कि हिमाचल प्रदेश को 7.19 परसेन्ट हिस्सा मिलना चाहिए। हमारे साथ ऐसा मज़ाक किया गया है, हमारी जमीने डूब गईं, हमारे लोगों को पीड़ा आई। लाखों-लाख भूमि डूब गई है और डैहर पावर हाऊस से मात्र

12.03.2018/1705/बी0एस0/ए0जी0-2

15 मैगावाट का हिस्सा हमें मिलता है, इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। पौंग डैम में तो हमारा हिस्सा शून्य है। मैंने जिक्र किया आपसे कि 1978 में सुब्रमण्यम कमेटी में इस बात को माना कि हिमाचल प्रदेश को 7.19 परसेन्ट हिस्सा मिलना चाहिए। इस सदन ने आज से पहले जनरेशन टैक्स लगाने के लिए यह प्रस्ताव पारित किया और यह प्लानिंग कमेटी ने माना कि हिमाचल प्रदेश का अधिकार है कि 10 पैसे प्रति यूनिट पावर पर यह चार्ज कर सकता है और यह डॉ0 सी रंगाराजन कमीशन ने भी इस पर सिफारिश की है। हमने अपने सारे के सारे जंगल भारत सरकार के हवाले कर दिए है, यह जो moratorium green felling पर लगा है इसके एवज में माना गया है कि 3800 करोड़ प्रति वर्ष की आय हमें आती थी। उसको भी केन्द्र सरकार ने नहीं दिया। जिसके एवज में हम लगातार हजार करोड़ रुपये मांग रहे हैं । मैं समझता हूं यह सारी-की-सारी बातें इस बजट में resource mobilization के रूप में शामिल होनी चाहिए थीं और उसके अलावा जो मैंने पहले भी जिक्र किया, यह जो 12 प्रतिशत जो कोस्ट हमें मिलने चाहिए थी डिस्ट्रेस कोस्ट के नाम पर जो 2008 तक 5000 करोड़ तक चला गया आज इसकी जो राशि है और भी अधिक बढ़ी होगी इसका भी कोई जिक्र नहीं है। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस बजट की बहुत सीरियत लिमिटेशन्ज हैं। इसमें विकास के लिए कितना पैसा रहता है, मात्र 13 हजारा करोड़ रहता है। यही नहीं ये बहुत खतरनाक सिच्वेशन में हम पहुंच गए हैं। आप पुरानी सी.ए.जी. की रिपोर्ट पर नजर मारेंगे तो उसमें साफ लिखा है कि हिमाचल प्रदेश एक डेबट ब्लैक की तरफ बड़ रहा है।

13-03-2018/1710/DT/AG/1

श्री राकेश सिंघा ------जारी।

यही नहीं, मैं यहां पर यह भी ज़िक्र करना चाहता हूं कि इस सदन को बड़ी गम्भीरता से इस प्रश्न को लेना चाहिए। यह जो संकट आ गया है, इससे हम किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं? मेरी चिन्ता इस बात पर भी है कि हमारा Gross Domestic Product जो है वह

decline की तरफ है। वर्ष 2015-16 का देखें तो वह 8.1, वर्ष 2016-17 में 6.9 और वर्ष 2017-18 में मात्र 6.3 रहा है। हमारे प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जीवनयापन लोग को कृषि से संबंधित हैं और कृषि पर आधारित हैं। उसमें और भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है। वर्ष 2016-17 में हमारे पास Gross Domestic Product की जो आय आ रही थी, वह 3 फीसदी थी। वर्ष 2017-18 में -5.3 चली गई है और यह बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है। इन चुनौतियों के लिए इस सदन को इक्ट्ठे मिल करके आगे चलना है। मैं समझता हूं कि जब तक हम इक्ट्ठा मिल करके नहीं चलेंगे, इन चुनौतियों का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि इक्ट्ठे मिल करके हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री को इसमें पहल करनी चाहिए। पूरे सदन को विश्वास में ले करके जो हमारे हक-हकूक बनते हैं, उसके लिए आगे आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट पर चर्चा कर रहा हूं और बड़े दुःख के साथ कह रहा हूं कि इस पूरे बजट में बड़े खतरनाक किस्म के प्रावधान शामिल किये गये हैं। मेरे हिसाब से सरकार को इन खतरनाक प्रावधानों से बचना है। "Minimum Government and Maximum Governance'' मोदी जी का नारा नहीं है। यह नारा वर्ल्ड बैंक का नारा है। यह नारा IMF का है। इस नारे का क्या मतलब है? इस नारे का मतलब है कि गवर्नेंस के अंदर तो हम काम करेंगे लेकिन सरकार को चलाने का जो कार्य है, ये सारे-का-सारा हम धीरे-धीरे आउटसोर्स कर देंगे, निजी हाथ में दे देंगे। इसलिए यह बजट इस प्रश्न पर चुप्पी साधता है कि जितने भी आज एजुकेशन के अंदर वेकैंट पोस्ट्स हैं, हैल्थ और आई0पी0एच0 के अंदर हैं, आपने उस पर चुप्पी साधी है। सिर्फ एक शब्द में लिखा है कि कार्यमूलक पद के बारे में समय पर सोचा जाएगा। आज मैं हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या आई0पी0एच0 विभाग के अंदर जो पम्प ऑपरेटर है, क्या यह कार्यमूलक पद है कि नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं कि एक स्कूल का अध्यापक, डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट, क्या ये कार्यमूलक पद नहीं हैं?

13-03-2018/1710/DT/AG/2

अध्यक्ष महोदय, ये पूरे-का-पूरा बजट इस पर साइलैंट है। मैं समझता हूं कि ये हिमाचल प्रदेश के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। मैंने ज़िक्र किया था कि जिसने यह बजट बनाया है उसने ऐसे प्रावधान डाले हैं, जो बहुत खतरनाक किस्म के हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा है कि वे और इनका मंत्रिमंडल ए0पी0एल0 की सुविधा को छोड़ देंगे।

लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि ए0पी0एल0 और बी0पी0एल0 क्या है? अगर हम वर्ष 2007 के प्रावधानों से चलें तो जो व्यक्ति प्रतिदिन 26 रुपये देहात के अंदर कमाता है, 32 रुपये शहर के अंदर कमाता है, उसको गरीबी रेखा के अंदर लाया जाता है और उसको बी0पी0एल0 की श्रेणी में मानते हैं। लेकिन जो व्यक्ति देहात के अंदर 27 रुपये कमाएगा या 27 रुपये से ऊपर कमाएगा और अर्बन एरिया में 33 रुपया कमाएगा, वह गरीबी रेखा से ऊपर आएगा। अगर हम उसको इन सुविधाओं से वंचित कर देंगे, तो मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं कि वह बाजार से इन वस्तुओं को नहीं ले पाएगा और एक ऐसा क्राईसिस आएगा जिसको हम Food Crisis कहेंगे। मैं समझता हूं कि यह कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि ये Finance driven budget है, तो Finance driven चाहता है कि ये सारी सब्सिडियां समाप्त हो जायें। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं। जिसको हटा देना चाहिए वह पैरा-24 में है। हमने कहा कि under Essential Services Act, 1955 को हम समाप्त करना चाहते हैं और जो कानून हमने हिमाचल प्रदेश में 1977 में बनाया था, जिसका इसमें जिक्र भी गलत किया है,

**13.03.2018/1715/SLS-AG-1**

**श्री राकेश सिंघा... जारी**

Himachal Pradesh Hoarding and Prevention Order कहां है । ये कोई कानून नहीं है। कानून क्या है? वह है Himachal Pradesh Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977. इसको समाप्त करने की बात कही जा रही है। मैं समझता हूं कि यह बहुत ख़तरनाक है। क्यों ख़तरनाक है? जब हमने यह कानून बनाया था तो हमने क्या कहा था। मैं आपकी अनुमति से यहां पर इसका ज़िक्र करना चाहता हूं। यह हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस समय हमने इसको गज़ट में छापा था तो हमने कहा था - whereas the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary so to do for the maintenance and increase of supplies and for securing the equitable distribution and availability of article or things specified in the schedule at fair price. फेयर प्राईस है जो हमारे लिए चिंता का विषय है। आगे हमने Section 3(2) में क्या लिखा है? आप मुझे इसे पढ़ने की अनुमति दें। The

quantities, price and margin of profit fixed in respect of any article under this paragraph may be different in different localities provided that while fixing the margin of profit the prescribed authority shall take into consideration the nature of the commodity and also all relevant conditions and that such margin of profit shall in no case be less than 1.5 per cent and more than 10 per cent but in the case of fresh vegetables the margin makes to 10 to 25 per cent. मैं क्यों उस पर ज़ोर दे रहा हूं? आज क्या हालात है? आज सी.ए. स्टोर बन गए हैं। आप 2 रुपये किलो में टमाटर लीजिए, आप 2 रुपये किलो में आलु लीजिए और सी.ए. स्टोर में डाल दीजिए। उसके बाद वही आलु बाजार में 40 रुपये किलो मिलेगा। वही टमाटर बाजार में 50 रुपये किलो मिलेगा। दूध का दाम जो किसान को मिलता है वह 14 रुपये है लेकिन जब उसको बाजार से लेना है तो वह 70 रुपये किलो होगा। अगर हम इस कानून को समाप्त कर देंगे तो क्या होगा? एक मोनोपली बन जाएगी और सारा-का-सारा सिस्टम अमीर के हाथ में चला जाएगा। मैं समझता हूं कि जो प्रावधान इसमें दिया है कि इसको समाप्त करना है, मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री से हाथ जोड़ कर विनती करना चाहता हूं कि इस कानून को समाप्त करोगे तो जो उपभोक्ता है, गरीब है वह पिस जाएगा। मेहरबानी करके इसको न

**13.03.2018/1715/SLS-AG-2**

किया जाए। तभी संभव है कि जो हिमाचल प्रदेश का गरीब है वह सांस लेने के काबिल होगा।

यही नहीं, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस बजट के अंदर खेती के बारे में बहुत-सी बातें कही हैं। कुछ बातों से मैं सहमत हूं लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि कुछ प्रावधानों पर पुनर्विचार करना होगा। इस प्रश्न को लेकर, जो बरागटा जी ने भी उठाया है, यह जो हेलगन है, यह हिमाचल की परिस्थितियों में बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। जिन किसानों ने यह हेलगन अपने बगीचों में लगाई है, आप उनका अनुभव पूछिए। जहां पर हेलगन लगाई गई, वहीं पर ओले गिर गए। जो किसानों ने पैसा इकट्ठा करने हेलगन लगाई थीं, वह अब दोबारा सोच भी नहीं सकते हैं कि हेलगन लगाई जाएं। दुनियां के अंदर अभी तक

सिर्फ़ ऐंटि हेल नैट का ही प्रावधान है जो इस्तेमाल की जा सकती है। अभी हमारी साईंस इतनी डवलप नहीं हुई है जो ओले को इस गन के ज़रिए रोक सके। इसलिए मेरी हाथ जोड़ कर विनती है कि आप जनता के अंदर ऐसा भ्रम पैदा न करें जिसके जरिए ऐसा हो कि किसान इस ऐंटि हेलगन की ओर जाए।

अध्यक्ष महोदय, अगर आप अनुमति देंगे तो मैं 5 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अब हमारी कृषि की आय गिरती जा रही है। आने वाले समय में यह और गिर जाएगी। इसलिए आप हिमाचल प्रदेश को बचाएं। मैं समझता हूं कि दिल्ली की सरकार के हस्तक्षेप से हम बच सकते हैं। मैंने प्लानिंग की मीटिंग में भी ज़िक्र किया था कि यह जो रिजनल कम्प्रीहैंसिव इकोनोमिक पार्टनरशिप (RCEP) है इसके आने के बाद, जो आज हम सेव पर आयात कर लगा रहे हैं, वह समाप्त हो जाएगा। चाहे आप कोलोनियल रूट स्टॉक्स लाएं या कोई और किसम की लाएं, वह उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी।

**13/03/2018/1720/RG/DC/1**

**श्री राकेश सिंघा------जारी**

इसलिए उस पर वह जो आयात कर लग रहा है, उसको अगर बढ़ाया नहीं जा सकता, तो उसको उतना ही रहने दीजिए और यह काम दिल्ली की सरकार का है। लेकिन इसका जिक्र इसमें होना चाहिए था। मैं ज्यादा न कहता हुआ यह जरूर कहूंगा कि हमने कहा है कि ruminative price realization लाना चाहते हैं और उसके लिए हमने क्या किया है कि छोटी-छोटी मण्डी खोल रहे हैं। उससे price realization ruminative हो सकता है, नहीं, यह कभी संभव नहीं है। अगर हम यह करना चाहें, तो एक ही तौर-तरीका है और वह डॉ. स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू करने का है। जिस पर यह सरकार चुप है। हालांकि यह दिल्ली की सरकार ने अपने बजट में बोला है, लेकिन हमने चुप्पी साधी है। हमारी चुप्पी अच्छी नहीं है, हमें इसके बारे में बोलना है और अगर किसान को उठाना है, तो मैं समझता हूं कि वह तभी संभव है जब उसकी पैदावार का दाम, उसकी लागत का 50% प्रॉफिट हम उसे दें।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा न कहता हूं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। आपने देशी गाय से लेकर आधुनिक रूट स्टॉक की बात की है। आपने कोशिश तो की है कि सबको खुश करें। जो पिछड़ी सोच का है वह देशी गाय और जो आधुनिक सोच का है वह कोलोनियल रूट स्टॉक पर जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि जो आवारा पशुओं के लिए आपने तौर-तरीका इस्तेमाल किया है, वह अच्छा नहीं है। मैं इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। मैं ऐसा भी समझता हूं कि जब हमने कह दिया है कि बोतल के पीछे एक रुपये लेना है, तो इसके लिए हम एक ब्रैंड ऐम्बैसेडर भी चुन लें। जो इसके बारे में कुछ चर्चा करे। मैंने देखा कि मुकेश जी भी बहुत अच्छी शायरी करते हैं और लोग भी हैं जो बहुत अच्छी शायरी करते हैं। कुछ ढूंढ लें जो ब्रैड ऐम्बैसेडर बने और जिसको आप आदेश देंगे, मैं समझता हूं कि वह मुकरेगा नहीं । लेकिन अभी तो हम statutory warning देते हैं। सिगरेट पीते हैं, तो हम कहते हैं कि वार्निंग दे रहे हैं कि कैंसर हो सकता है। लेकिन हम यहां क्या करेंगे? हमें statutory direction देनी पड़ेगी। अब यह डायरैक्शन क्या हो सकती है? यह तो ऐसी डायरैक्शन देनी पड़ेगी कि एक पीयो, सब पीयो, बच्चे पीयो, बूढ़े पीयो और उसके साथ यह भी लिखना पड़ेगा कि देवियों, तुम भी पीयो।--(व्यवस्था)----अध्यक्ष महोदय, यह बजट तो एक अप्रैल से काम करेगा। लेकिन हमारे डॉक्टर्ज, उन्होंने अखबार खोला, उनकी चिन्ता यह नहीं थी कि क्या होगा, उनकी चिन्ता यह थी कि

**13/03/2018/1720/RG/DC/2**

सरकार के पास आय आए। किस लिए कि जिससे जो गऊ हमारी नकारा या आवारा है। उसके लिए कुछ साधन हो, तो मेहरबानी करके इसमें न करें। क्योंकि यह हल नहीं है और हमें इसका हल निकालना है। मैं 2-3 सुझाव छोटे-छोटे दे रहा हूं। ये आवारा और नकारा पशु क्यों हो गए? पहले हमारी खेती थी जिसमें बैल काम आते थे, लेकिन आज बैल काम नहीं आते हैं। आपने कह दिया है कि अब मशीनें होंगी और हम उनके लिए सब्सीडी देंगे। इसलिए सब लोग उस तरफ जा रहे हैं। इसलिए अब बैल का कोई काम नहीं है। फॉडर हमारे पास नहीं है। फॉडर का इसमें जिक्र किया गया। मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि हमारा फॉडर हाइड्रोफॉनिक से पैदा हो सकता है। जो हमने स्कीमें बनाई हैं आज वह संभव नहीं है। हाइड्रोफॉनिक फॉडर में जाएंगे, तो संभव है कि कम

जमीन में भी ज्यादा पैदावार हो सकती है। तो इस तरह के मॉडल यदि हम खड़े करेंगे, तो संभावना है। आज आवारा और नकारा पशुओं का एक कारण और है। जो नाइट्रोजन गैस कहीं उपलब्ध नहीं है। आज जब आर्टिफिशियल इन्सेमीनेशन करते हैं, तो Veterinary Pharmacist उपलब्ध नहीं हैं। वह नाइट्रोजन के डिब्बे में नहीं ले जाता है बल्कि वह आर्टिफिशियल इन्सेमीनेशन जेब में डालकर ले जाता है और जो गाय नए दूध में आई है जब उसका इन्सेमीनेशन करते हैं, तो सफल नहीं होते। उसके कारण ये नकारा और आवारा पशु हो रहे हैं। इसलिए नकारा और आवारा पशु का समाधान करने के लिए उसकी जड़ में जाना होगा। न कि उसका समाधान दारू को पिलाकर ढूंढना है। अगर हम यह काम करेंगे, तो मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश को यह शोभा नहीं देता है। यह देव धरती है और देव धरती में यदि इस तरह की स्कीमें लाएंगे तो

**13/03/2018/1725/MS/AG/1**

**श्री राकेश सिंघा जारी**-----------

मैं आखिरी आदमी होऊंगा जो ऐसा काम करेगा। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ऐसा अहसास होता है कि यह बजट दिशाहीन है। इसमें कोई शक नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने अच्छे प्रयास किए हैं लेकिन जब तक ये संशोधन इस बजट में नहीं आते हैं, मैं इस बजट का समर्थन नहीं कर सकता। जो परम्परा चली हुई है इसको उसी रूप में छाप देते हैं तो फिर चर्चा करने की क्या जरूरत रह जाती है। चलो, हमारी चर्चाएं छोड़ दो, सत्ता पक्ष की चर्चाओं को तो शामिल कर दो और जो इस तरह की ग्रेट मिस्टेक और नॉन-सीरियस काम किया है, इसको तो संशोधित करो। तब तो हम समझें कि चर्चा का कुछ फायदा है नहीं तो ये केवल औपचारिकताएं हैं कि मोहर लगाई और चलो। हाथ खड़ा करके चलो। मैं समझता हूं कि ये अच्छी परम्पराएं नहीं रहेंगी। हैल्दी डिस्कशन होनी चाहिए क्योंकि पक्ष और विपक्ष से ही हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली मजबूत हो सकती है। इसलिए सत्ता पक्ष को हमारे विचार सुनने की भी क्षमता रखनी चाहिए। इसके साथ अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद लेकिन मैं अपनी मजबूरी को प्रकट करते हुए इस बजट का समर्थन नहीं कर सकता।

**अध्यक्षः अब इस मान्य सदन की बैठक बुधवार 14 मार्च, 2018 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।**

**शिमला-171004** **सुन्दर सिंह वर्मा,**
**दिनांकः 13 मार्च, 2018** **सचिव।**